

राजस्थान पत्रिका

संस्थापक
कपूर चन्द्र कुलिश

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआईटी) देश के इंजीनियरिंग परिसरों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दुनियाभर को अनगिनत बड़े इंजीनियरिंग ब्रेन देकर देशभर के प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अपनी साख कायम की है। यह मुकाम निरंतर बनाए रखने के लिए किसी भी संस्थान को दुनियाभर में नित-नए होते जा रहे परिवर्तनों और प्रगति के साथ न सिर्फ कदमताल करनी होती है, बल्कि समय पर इनकी जरूरत को भांपते हुए उसके अनुरूप बदलाव भी करना पड़ता है। हमारे संस्थान इस आवश्यकता को काफी हद तक अच्छे से पूरा कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति से प्रेरित प्रौद्योगिकी संस्थानों में इसी साल से अपनाए जाने वाले इंटर कैम्पस, सेमेस्टर-लॉग स्ट्रैंडेंट मोबिलिटी प्रोग्राम, ऐसा ही नवाचार कहा जा सकता है।

इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि यह आइआईटी के छात्र को अपनी पसंद की किसी अन्य आइआईटी में एक सेमेस्टर में अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करेगा। वहां उसके को क्रेडिट बनेंगे, वे उसके मूल आइआईटी में जुड़ जाएंगे। इसमें छात्र को लाभ यह है कि एक ही डिग्री में उसे दो आइआईटी की

आइआईटी में इंटर कैम्पस अध्ययन सार्थक पहल

व्यवस्था का एक्सपोजर मिलेगा। इसमें दूसरा आइआईटी स्वाभाविक रूप से ऊंची रैंक का ही होगा। इसी ऊंची रैंक के आइआईटी के माहौल, संसाधनों तथा अपेक्षाकृत अधिक अनुभव, दक्ष और प्रतिस्पर्धी प्रोफेसर्स का सान्निध्य विद्यार्थी को बेहतर तरीके से पारंगत कर सकेगा। इसका असर सिर्फ उस सेमेस्टर विशेष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विद्यार्थी के पूरे अध्ययनकाल को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा, इसकी भी पूरी उम्मीद रहेगी। अभी भारत की कुछ देशों से संधि है, जिसके तहत उनके शैक्षणिक संस्थानों के साथ आदान-प्रदान की प्रक्रिया चलती है। देश के आइआईटी संस्थानों में इस तरह

की प्रक्रिया लागू करने का यह पहला अवसर होगा। इस व्यवस्था में सभी आइआईटीज में अकादमिक सहयोग बढ़ाने और छात्रों के लिए डिग्री में लचीलापन लाने का उसका उद्देश्य पूरा होगा। पहले साल में कुछ बड़े आइआईटीज के साथ यह नवाचार शुरू होगा है। धीरे-धीरे इसे सभी आइआईटीज में लागू किया जाना चाहिए। आज की जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा सेमेस्टर तथा समान ब्रांच के सेमेस्टर से आगे दूसरी ब्रांच के सेमेस्टर की सुविधा देने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए।

अब भी कई छात्र अपनी स्टडी से हटकर दूसरी स्टडी का अध्ययन करते हैं और उसे करियर भी बनाते हैं, लेकिन यह सब कुछ उन्हें अपने स्तर पर करना होता है। इसमें उन्हें अपनी मूल स्टडी तो पूरी करनी ही होती है। अधिकृत तौर पर दूसरे आइआईटी में दूसरी स्टडी को पढ़ाई की सुविधा मिलेगी, तो यह छात्रों के लिए ज्यादा हितकारी होगा। यह छात्रों के परिपूर्ण इंजीनियर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर उनके लिए अलग-अलग क्षेत्र में रोजगार के अनेक द्वार खोलने में सहायक होगी।

चीन का गुप्त परीक्षण: भारत के लिए यह समय संयम, सतर्कता और कूटनीतिक दृढ़ता का है

परमाणु अपारदर्शिता से बढ़ती रणनीतिक अस्थिरता

पिछले दिनों अमरीका ने चीन पर अत्यंत गंभीर और दुरगामी प्रभाव वाला आरोप लगाया है, जिसने वैश्विक परमाणु संतुलन, रणनीतिक पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय भरोसे की पूरी संरचना को चुनौती दे दी है। अमरीकी अधिकारियों का दावा है कि 22 जून 2020 को चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत स्थित लोफ नूर परीक्षण स्थल पर एक गुप्त परमाणु परीक्षण किया, जिसे सुनियोजित ढंग से अंतरराष्ट्रीय समुदाय और निगरानी तंत्र से छिपाया गया।

अमरीका ने इस आरोप को केवल एक आम बयान के रूप में नहीं रखा, बल्कि परीक्षण की सटीक तिथि और समय सार्वजनिक कर इसे तथ्यात्मक गंभीरता प्रदान की। यह स्पष्ट संकेत है कि वाशिंगटन इस वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानता है, न कि महज कूटनीतिक दबाव को रणनीति। यदि यह आरोप सत्य सिद्ध होता है तो यह दशकों से कायम परमाणु परीक्षण विराम की उस अनौपचारिक, लेकिन प्रभावी परंपरा को तोड़ने जैसा होगा, जिसने शीत युद्ध के बाद की दुनिया में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

अमरीकी विशेषज्ञों ने जिस 'डिकप्लिंग' तकनीक का उल्लेख किया है, वह विशेष रूप से चिंतनक है। इस तकनीक के माध्यम से भूमिगत परमाणु विस्फोट के भूकंपीय संकेतों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि वे सामान्य भू-गतिविधि जैसे प्रतीत हों। यदि किसी राष्ट्र ने इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रणालियों को चकमा देने का प्रयास किया है, तो यह केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि वैश्विक नियम-आधारित व्यवस्था को चुनौती देने का सुनियोजित प्रयास है। यह घटना परमाणु हथियार नियंत्रण की

विनय कौड़ा

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

@patrika.com



चीन की बढ़ती अपारदर्शिता और गुप्त गतिविधियां भारत के लिए यह संकेत हैं कि रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर तैयारी अनिवार्य है। भारत का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी विस्तार नहीं, बल्कि स्थिरता सुनिश्चित करना है।

विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार करती है। इस पुरे घटनाक्रम का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमरीका और रूस के बीच रणनीतिक परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। इस संधि ने वर्षों तक दो प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके समाप्त होते ही यदि तीसरी बड़ी शक्ति पर गुप्त परीक्षण का आरोप सामने आता है तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या भविष्य की हथियार नियंत्रण व्यवस्था को द्विदक्षीय के बजाय त्रिदक्षीय या बहुदक्षीय स्वरूप नहीं दिया जाना चाहिए। चीन को औपचारिक नियंत्रण ढांचे में शामिल किया जाना अधिक यथार्थवादी प्रतीत होता है।

चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें राजनीतिक प्रेरित बताया है। बीजिंग ने अपनी 'नो-फर्स्ट-युज' नीति के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। लेकिन समानांतर रूप से चीन की गतिविधियां अलग कहानी कहती हैं। हाल के वर्षों में नए आइसीबीएम साइलेंट क्षेत्रों का निर्माण, हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण, परमाणु पनडुब्बी बेड़े का विस्तार और परमाणु भंडार में तीव्र वृद्धि जैसे संकेत तीव्र आधुनिकीकरण

कार्यक्रम की ओर इशारा करते हैं। यह प्रवृत्ति चीन के 'न्यूनतम प्रतिरोध' के दावे को सदिध बनाती है। भारत के लिए यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि 2020 में गलतन घाटी में हुए संघर्ष ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सीमाई तनाव अब पारंपरिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। यदि उसी समय-सीमा में यह परमाणु परीक्षण हुआ तो यह एक व्यापक सार्वजनिक संदेश का हिस्सा हो सकता है।

क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में यह निर्विवाद तथ्य है कि चीन ने दशकों तक पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को खुला या परोक्ष संरक्षण दिया है। परमाणु रिफ़्टरों की आपूर्ति, बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में सहयोग और रणनीतिक ढाल प्रदान कर चीन ने दक्षिण एशिया में शक्ति-संतुलन को जानबूझकर भारत-विरोधी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। यह समर्थन केवल तकनीकी सहायता नहीं, बल्कि भारत को घेरने की व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहा है। ऐसी नीतियां चीन के 'जिम्मेदार शक्ति' होने के दावों को खोखला सिद्ध करती हैं। भारत की परमाणु नीति नो-फर्स्ट यूज और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध-दीर्घकाल से जिम्मेदार और

संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण रही है। भारत ने संख्या की अधी दौड़ में शामिल होने के बजाय अपनी प्रतिरोधक क्षमता की उत्तरजीविता और विश्वसनीयता पर बल दिया है। त्रिस्तरीय प्रतिरोधक क्षमता (भूमि, वायु और समुद्र आधारित), कमांड-एंड-कंट्रोल संरचना की मजबूती तथा तकनीकी आधुनिकीकरण जैसे कदम इस बात के प्रमाण हैं कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क और दूरदर्शी है। चीन की बढ़ती अपारदर्शिता और गुप्त गतिविधियां भारत के लिए संकेत हैं कि रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर तैयारी अनिवार्य है। भारत का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी विस्तार नहीं, बल्कि स्थिरता सुनिश्चित करना है। वैश्विक स्तर पर यह घटना एक बड़े प्रश्न को जन्म देती है। क्या वर्तमान परमाणु ढांचा बहुदक्षीय विश्व की वास्तविकताओं के अनुरूप है? शीत युद्ध के समय का द्विदक्षीय संतुलन अब अप्रासंगिक हो चुका है।

चीन के गुप्त परमाणु परीक्षण का मुद्दा महज आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि वैश्विक परमाणु व्यवस्था, पारदर्शिता और शक्ति-संतुलन के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। जून 2020 की घटना यदि वास्तव में एक परमाणु परीक्षण थी, तो उसका उद्देश्य और संदेश दुरगामी महत्व रखते हैं। यह बहुदक्षीय, पारदर्शी और समावेशी हथियार नियंत्रण ढांचे की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत के लिए यह समय संयम, सतर्कता और रणनीतिक दृढ़ता का है। जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत ने सदैव अंतरराष्ट्रीय नियमों का समान किया है लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं किया है। भारत का लक्ष्य स्पष्ट है- राष्ट्रीय हितों की रक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता का संरक्षण व नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन।

प्रसंगवश

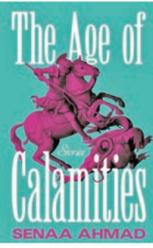
खेजड़ी के तस्करों के दुस्साहस की घटनाएं चिंताजनक, सख्ती जरूरी मिलीभगत का गठजोड़ तोड़े बिना ऐसी घटनाओं पर अंकुश संभव नहीं

खेजड़ी के पेड़ों को काटने के बाद लकड़ी की तस्कारी कर हरियाणा ले जाने और रुकने-होने-होते प्रयास कर रहे राजस्थान के वनकर्मियों पर हमले का दुस्साहस बताता है कि तस्करों में कानून का भय नहीं रह गया। यह तो तब है जब खेजड़ी बचाने को लेकर वीकानेर में चले लंबे आंदोलन के बाद सरकार खेजड़ी की काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हुए विधानसभा के इसी सत्र में ट्री प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी कर रही है। यह कोई एक-दो घटनाओं से जुड़ा मामला नहीं है। शेखावाटी में आज भी प्रशासन व वनरक्षकों की नाक के नीचे खेजड़ी के पेड़ रातों-रात काटे जा रहे हैं और सुबह होते-होते हरियाणा के बाजारों में पहुंच चि रहे हैं। झुझुं जिले में दो दिन पहले वन विभाग की नाकाबंदी तोड़कर लकड़ी तस्करों ने भागने की कोशिश की। पीछा करने पर तस्करों ने विभाग की गाड़ी को टक्कर मार रेंजर सहित कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास किया। लकड़ी तस्करों के परिवहन में काम आ रही एक पिकअप कच्ची मिट्टी में फंस गई तो 30 किंवदंत खेजड़ी की लकड़ी बरामद हुई लेकिन चालक फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि खेतों में पूरी रात पेड़ काटे जाते हैं और तड़के पिकअप वाहन कई थानों, चौकियों व टोल नाकों से गुजरकर सीमा पार कर जाते हैं।

बड़ा सवाल यह है कि क्या इन रास्तों पर निगरानी नहीं है, या फिर निगरानी के बावजूद आंखें मूंदी जा रही हैं? आए दिन वन विभाग की टीमों पर हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कानून में सजा का प्रावधान नहीं है। जब तस्कर नाकाबंदी तोड़कर सरकारी वाहन पर हमला करने का दुस्साहस कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि दंड का भय समाप्त हो चुका है। जब तक सीमा पार लकड़ी ले जाने की पूरी शृंखला जिसमें काटने से लेकर परिवहन और खरीद करने वाले तक शामिल हैं उसे नहीं तोड़ा जाएगा, मिलीभगत का गठजोड़ तोड़ना मुश्किल काम है। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ ही नहीं संपूर्ण महस्थल की जीवन रेखा है। सरकार जो कानून ला रही है उसे भी जमीनी स्तर पर लागू करने की कठोर व्यवस्था करनी होगी। सीमावर्ती जिलों में संयुक्त अभियान, रात की गश्त, परिवहन की डिजिटल निगरानी भी करनी होगी।

- युगलेश शर्मा
yuglेश.sharma@in.patrika.com

बुक इनसाइट



लेखिका सेना अहमद ने इस कहानी-संग्रह की नौ कहानियों में इतिहास को कल्पनाशील अतिथार्थवाद के साथ नए अंदाज में प्रस्तुत किया है। इन कहानियों में ऐमी बोलिन मरने के बाद भी जीवित बनी रहती हैं। जूलियस सीजर आधुनिक न्यूयॉर्क पर आक्रमण करता दिखाई देता है और नेपोलियन के कई रूप एक घर में फैल जाते हैं। संग्रह का सबसे प्रभावशाली हिस्सा अंतिम कहानी 'चूज योर ओन अपोकेलिप्स' है, जो अपनी पसंद से कहानी चुनने की शैली में लिखी गई है। इसमें

द एज ऑफ कैलेमिटीज

मैनहैटन प्रोजेक्ट के दौरान एक विषाक्त रेगिस्तान कई वैकल्पिक समयरेखाओं में टूटा दिखाया गया है। अतिथार्थवादी लेखन अक्सर दिखावटी या अनावश्यक लग सकता है, लेकिन अहमद अपनी कहानियों के मूल विषय पर लगातार ध्यान बनाए रखती हैं जब सब कुछ बिखर जाता है और जीवन अर्थहीन लगने लगता है तब मनुष्य कैसे व्यवहार करता है। इस संग्रह की सबसे प्रभावशाली कहानियां युद्ध और अन्य आपदाओं से विस्थापित लोगों के अनुभवों पर आधारित हैं।

फैक्ट फ्रंट

तैरने की सुंदर शैली वाला 'सी ऐंजल'

सी ऐंजल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्लायडोस लिमासिना है, मुख्य रूप से आर्कटिक और उष्ण समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। अपने पारदर्शी शरीर और पंख जैसे अंगों के कारण इसे 'समुद्री पत्ती' भी कहा जाता है। सी ऐंजल वास्तव में एक प्रकार का अर्धहीन लगने वाला है लेकिन इसमें खोल (शेल) नहीं होता। इसका शरीर लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसके दोनों ओर पंख जैसे भाग होते हैं जिनकी मदद से यह पानी



में तैरता है। इसकी तैरने की शैली इतनी सुंदर होती है कि मानो कोई परी आकाश में उड़ रही हो। हालांकि इसका रूप बेहद कोमल और

आकर्षक लगता है लेकिन यह एक शिकारी जीव है। यह मुख्य रूप से समुद्री तितली नामक छोटे जीवों का शिकार करता है। शिकार करते समय इसका शरीर अपना आकार बदल लेता है और यह अपने शिकार को मजबूती से पकड़ लेता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह समुद्री ईकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खाद्य शृंखला में संतुलन रखने में मदद करता है। जलवायु परिवर्तन का असर इन पर पड़ रहा है।

AI इंपैक्ट समिट भारत 2026

बेहतर होगी सड़क सुरक्षा

एआइ से स्पीड पकड़ेंगा सिस्टम, चालान से वसूली तक सब ऑटोमेटिक

अभिषेक यादव
patrika.com

एआइ करेगा ये काम

- तेज रफ़्तार की स्वतः पहचान
- चालान कटते ही डिजिटल वसूली
- बार-बार उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
- पुलिस की भूमिका केवल निगरानी तक सीमित

स्कूलों में एआइ सिम्युलेटर से ड्राइविंग



इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट 2026 में आइआईटी मद्रास ने सड़क सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय रणनीति पेश की। अहम पहल स्कूलों में 16 वर्ष के विद्यार्थियों को ड्राइविंग 'लाइफ स्किल' के रूप में सिखाने की है। एआइ आधारित ड्राइविंग सिम्युलेटर तैयार किए जा रहे हैं, जिनके जरिए सुरक्षित ड्राइविंग, सड़क संकेतों की समझ और जोखिम की पहचान सिखाई जाएगी। विशेष मॉड्यूल लड़कियों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। उद्देश्य है- कम उम्र में होने वाले हादसों को रोकना और सड़क व्यवहार की वैज्ञानिक समझ विकसित करना।

दोपहिया सुरक्षा पर विशेष जोर

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी (सीओईएफआरएस) के सीओओ अतुल सिंह के अनुसार, सड़क सुरक्षा नीति अब तक कार-केंद्रित रही है, जबकि सड़कों पर 45 प्रतिशत दोपहिया चालक और 20 प्रतिशत पैदल यात्री हैं और हर साल लगभग 35 हजार मौतें दोपहिया टक्करों में होती हैं। इसलिए निम्नलिखित से बेहतर एबीएस, एआइ-आधारित स्टेबिलिटी कंट्रोल,

स्मार्ट हेल्मेट लिंक और उन्नत ब्रेकिंग तकनीक अपनाने को कहा गया है। डेटा पर स्पष्टता: सीओईएफआरएस के प्रमुख प्रो. वेंकटेश बालासुब्रमण्यम ने बताया कि डेल्टाएचओ द्वारा भारत के सड़क हादसों के आंकड़ों में कई वर्षों में वास्तविकता से अधिक मौतें दर्शाई गईं। अब आइआईटी मद्रास डेटा-आधारित विश्लेषण के जरिए नीति निर्माण पर काम कर रहा है।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारत के खेतों में अब केवल ट्रैक्टर और हल की गूंज नहीं, बल्कि डेटा और एल्गोरिदम की जुगलबंदी भी दिखाई देगी। ब्रिटेन सरकार के सहयोग से एथेना इफोनॉमिक्स द्वारा जारी दो रिपोर्टों 'स्टेट ऑफ आर्ट' और 'पैपिड रिस्क्यू' ने भारतीय कृषि के कायाकल्प की एक नई तस्वीर पेश की है। विशेषज्ञों ने महीनों के शोध के बाद निकर्य निकाला कि 'एआइ भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है। भारत एआइ इन्वेंशन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की पूरी क्षमता है। एआइ बड़ा अवसर है जिससे हम कृषि को 'घाटे के सौदे' से उबारकर एक 'मुनाफे के व्यवसाय' में बदल सकते हैं।

इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट 2026 में प्रस्तुत इस शोध का मुख्य निकर्य है कि कृषि में एआइ का उपयोग वर्तमान में मुख्य रूप से 'भूश्रीन लॉर्निंग' के रूप में हो रहा है, जो सीधे तौर पर फसल सुरक्षा, पैदावार बढ़ाने और सटीक बाजार भाव दिलाने में सहायक है। हालांकि रिपोर्ट चेतावनी भी देती है कि यदि इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच हर गांव तक समान रूप से नहीं हुई, तो अमीर किसान और समृद्ध होने जबकि गरीब किसान पिछड़ सकते हैं।

चिकित्सा क्षेत्र में एआइ के उपयोग का प्रदर्शन

एआइ समिट के दौरान प्रदर्शनी में चिकित्सा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का लाइव प्रदर्शन किया गया। इसका उद्देश्य भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं की नई दिशा को प्रस्तुत करना है। चिकित्सा क्षेत्र में एआइ से मरीजों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी विशेष तकनीक आई है।

तीन प्रमुख क्षेत्रों में आएगा क्रांतिकारी बदलाव

1. क्रीट और रोग नियंत्रण: किसानों की सबसे जटिल समस्या फसल में लगने वाले कीट हैं। अब एआइ-आधारित ऐप केवल पोथे की फोटो देखकर बीमारी पहचान लेते हैं। इससे कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव रुकेगा और खेती की लागत में कमी आएगी।

2. क्रेडिट और फाइनेंस: पर्याप्त डेटा के अभाव में छोटे किसानों को बैंक ऋण मिलने में कठिनाई होती थी। अब एआइ सैटेलाइट डेटा और फसल

की सेहत का विश्लेषण कर किसानों का 'क्रेडिट स्कोर' तैयार कर रहा है, जिससे लोन की प्रक्रिया सरल हो गई है।

3. गुणवत्ता जांच: मंडियों में फसल की गुणवत्ता को लेकर होने वाली धोखाधड़ी अब बीते वक्त की बात होगी। 'एगनेक्स्ट' जैसी कंपनियों की एआइ मशीनें क्षण भर में मिर्च या हल्दी की शुद्धता और गेड बता देती हैं, जिससे किसानों को सही दाम मिलता है। इससे विवाद के मामले भी कम होंगे।

अंतिम छोर तक पहुंच: छोटे और महिला किसानों को लाभ

■ छोटे किसान: रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि एआइ का सर्वाधिक लाभ उन किसानों को मिल रहा है जिनके पास दो एकड़ से कम भूमि है। सामूहिक डेटा विश्लेषण के माध्यम से उन्हें वे सुविधाएं मिल रही हैं जो पहले केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित थीं।

■ महिला किसान: ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक से दूरी की धारणा को 'डिजिटल ग्रीन' के 'फार्मर डॉट वैंट' जैसे एआइ चैटबॉट्स ने तोड़ दिया है। अब महिला किसान स्थानीय भाषा में सलाह ले रही हैं, जिससे उनकी निर्णय क्षमता बढ़ी है।

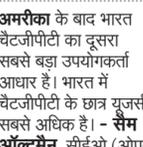
चिकित्सा क्षेत्र में एआइ के उपयोग का प्रदर्शन



समिट में क्या बोले एक्सपर्ट्स

एआइ के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ...

भारत में चैटजीपीटी के स्टूडेंट यूजर्स ज्यादा



अमरीका के बाद भारत चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता आधार है। भारत में चैटजीपीटी के छात्र यूजर्स सबसे अधिक हैं। - सैम ऑल्टमैन, सीईओ (ओपनएआइ)

एआइ टूल्स अपनाएं वरना पीछे छूट जाएंगे



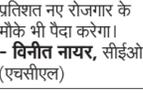
एआइ नौकरियां खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि काम की क्षमता को बढ़ा रहा है। युवा एआइ टूल्स को अपनाएं, वरना पीछे छूट सकते हैं। - संजीव ऑल्टमैन, सीईओ (ओपनएआइ)

इंसानी क्षमताओं को बेहतर बना रहा



एआइ आने वाली पीढ़ियों के लिए समाज में सुधार कर रहा है और इंसानी क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। - हरिश कृष्ण, एमडी (सिस्कॉ)

50 प्रतिशत नए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे



एआइ का असर 50 प्रतिशत नौकरियों पर पड़ेगा, लेकिन यह 50 प्रतिशत नए रोजगार के मौके भी पैदा करेगा। - विनीत नायर, सीईओ (एचसीएल)

तेजी से बन रहा जिंदगी का हिस्सा



एआइ तेजी से जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। हेल्थकेयर से खेती तक एआइ हर काम को आसान बना रहा है। - तेजप्रीत चोपड़ा, चेयरपर्सन (सीआइआइ नेशनल)

नौकरी के तरीके बदलेंगे



एआइ नौकरियों को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, बल्कि उनके काम करने के तरीके को बदल देगा। काम अलग-अलग कर देगा। - पुनीत चंडोक, अध्यक्ष (माइक्रोसॉफ्ट साउथ एशिया)

तेजी से बढ़ रही, लेकिन प्रसार समान नहीं



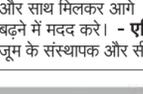
एआइ का प्रसार समान नहीं है। विकसित देशों में एआइ का उपयोग, शिकारशील देशों की तुलना में दोगुना है। - नताशा क्रेम्टन (माइक्रोसॉफ्ट की उपाध्यक्ष)

जहां प्रतिभा की कमी, वहां सहायक



यह ऐसे क्षेत्रों में सहायक होगा जहां गहराई से विचार करने की जरूरत है। कई देशों में प्रतिभा की कमी है जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। - नीरज अग्रवाल (प्रबंध निदेशक, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप)

तकनीक जोड़ने और आगे बढ़ने में मददगार



जूम में एआइ को लेकर हमारा नजरिया एक ही विश्वास पर आधारित है कि तकनीक लोगों को जोड़ने, रचनात्मक बनाने और साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद करे। - एरिक युआन, जूम के संस्थापक और सीईओ

नवाचार के नए रास्ते खोल रहा



एआइ कंपनियों के काम करने के तरीके को बदल रहा है और समावेशी विकास और नवाचार के नए रास्ते खोल रहा है। एआइ से आने वाले परिवर्तन को अपनाएं चाहिए। - मार्टिन थ्रोप्टर, सीईओ किंडल

देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही हो, तो अच्छी कंपनियां अपने-आप बिकती हैं। जहां युवा आबादी, टेक्नोलॉजी और खपत बढ़ रही हो, वहीं भविष्य का पैसा बनता है।



पत्रिका फाइनेंस

@ बिजनेस & वेल्थ

प्रॉफिट मीटर
इन कंपनियों की आय सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी (पिछले एक साल का इन कंपनियों का सालाना रेवेन्यू ग्रोथ रेट)

| | |
|-------|--------------------|
| 78.2% | टेकनी इलेक्ट्रिक |
| 41.2% | मुल्चुट फाइनेंस |
| 32.9% | कोरोमंडल इंटरनेशनल |
| 30.8% | नेशनल एल्युमीनियम |
| 26.4% | एचडीएफसी एएमसी |

निवेश आइटी स्टॉक्स में टॉप म्यूचुअल फंड्स की 10% से ज्यादा हिस्सेदारी, क्या यह छोटे निवेशकों के लिए है बड़ा खतरा? वैल्यू बाइंग से सोमवार को शेयर बाजार चढ़े

एआइ को लेकर बाजार में डर और अवसर दोनों साथ-साथ चल रहे

राहत: संसेक्स 650 अंक चढ़ा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई: एआइ टूलस एप्लिकेशन डेवलपमेंट, मेटेनस और टैरिफिंग जैसी पारंपरिक आइटी सर्विसेज को काफी हद तक ऑटोमेट कर सकते हैं। इससे आइटी कंपनियों के मौजूदा बिजनेस मॉडल और मार्जिन पर दबाव पड़ने की आशंका है। इस डर से 2026 में अब तक निपटी आइटी इंडेक्स में करीब 15% गिर चुका है। यह 2025 में आइटी इंडेक्स में आई 12.6% गिरावट से भी ज्यादा है। इस महीने आइटी शेयरों में आई गिरावट का असर अब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर दिखने लगा है। एसीई इक्विटी के मुताबिक, शीप 10 आइटी शेयरों में म्यूचुअल फंड्स के संयुक्त निवेश को वैल्यू घटकर 3.04 लाख करोड़ रुपए रह गई है, जो जनवरी 2026 के अंत में 3.56 लाख करोड़ थी।

म्यूचुअल फंड्स को इतना हुआ नुकसान

| कंपनी | शेयर लुटके | निवेश की वैल्यू घटी |
|-----------------|------------|---------------------|
| इंफोसिस | -16.5% | 22,600 |
| टीसीएस | -13.2% | 8,600 |
| एचसीएल टेक | -13.6% | 5,800 |
| टेक महिंद्रा | -13.3% | 3,900 |
| पर्सिस्टेंट सि. | -11.1% | 2,000 |
| कोफोर्ज | -18.5% | 3,670 |
| एमफेसिस | -12.8% | 1,740 |
| विप्रो | -12.1% | 1,231 |

10% तक मार्जिन पर असर पड़ सकता है एआइ ऑटोमेशन के कारण

इन आइटी स्टॉक्स पर म्यूचुअल फंड्स का दांव

| इंफोसिस | टीसीएस | एचसीएल | टेक महिंद्रा | पर्सिस्टेंट |
|----------|--------|--------|--------------|-------------|
| 1,17,000 | 55,600 | 36,700 | 30,200 | 19,900 |

आइटी स्टॉक्स: इन फंड्स की सबसे ज्यादा होल्डिंग

| म्यूचुअल फंड | होल्डिंग |
|---------------|----------|
| एस्बीआइ एमएफ | 62,000 |
| आइसीआइसीआइ | 55,000 |
| एचडीएफसी फंड | 41,600 |
| यूटीआइ एएमसी | 29,750 |
| निपॉन इंडिया | 28,350 |
| कोटक महिंद्रा | 23,870 |
| मिरे एसेट | 14,500 |
| मोतीलाल ओसवाल | 12,370 |

(टॉप 5 आइटी स्टॉक्स में होल्डिंग करोड़ रुपए में)

क्या कह रहे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स...

मोतीलाल ओसवाल: अगले तीन से चार वर्षों में एआइ के व्यापक उपयोग से आइटी सेक्टर के रेवेन्यू में 9 से 12% तक की गिरावट आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे काम तेजी से होने लगेगा और कुछ कामों की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि इसका असर कब और कितना होगा, यह अभी साफ नहीं है। एआइ को लेकर बाजार में डर और अवसर दोनों साथ-साथ चल रहे हैं।

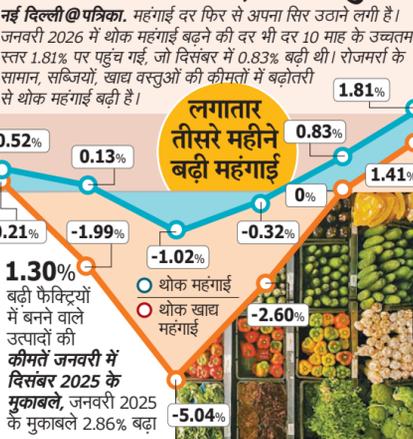
जेपी मोर्गन: एआइ नए अवसर भी पैदा करेगा और आइटी कंपनियों इस बदलाव से लाभ उठा सकती हैं। एआइ आइटी कंपनियों की हाल की को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उन्हें और सक्षम बनाएगा। हालांकि वैल्यूएशन अभी भी कमाई (अर्निंग्स) की तुलना में ऊंचे हैं, इसलिए आइटी शेयरों और गिरावट की आशंका है।

एचएसबीसी: एआइ मौजूदा बिजनेस मॉडल के भीतर ही काम करेगा, जहां आइटी सर्विसेज प्रदाताओं की भूमिका बनी रहेगी। बड़े संगठनों में एआइ 'मैजिक बॉक्स' की तरह अकेले काम नहीं कर सकता। उसे डेटा सिस्टम, ऑडिट चेक्स, साइबर सुरक्षा और रिस्क कंट्रोल जैसे मजबूत ढांचे की जरूरत होती है, जिसमें आइटी कंपनियों की अहम भूमिका है।

मुंबई @ पत्रिका: एशियाई बाजारों से मिलेजुले रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार सोमवार को बढ़त में बंद हुआ। सपाट शुरुआत के बाद कारोबार के दूसरे हाफ में निचले स्तर पर खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। संसेक्स गिरावट के साथ 82,480 अंक पर खुला, लेकिन अंत में 650 अंक या 0.79% की बढ़त लेकर 83,277 पर बंद हुआ। निपटी भी 0.83% की तेजी के साथ 25,682 पर रहा। कैपिटल गूड्स, रियल्टी, कंप्यूटर और मेटल शेयरों में भी मजबूती रही। इसकी वजह धरलू मांग के मजबूत रहने और इंड्रॉ पर खर्च जारी रहने की उम्मीद मानी जा रही है। वहीं, आइटी सेक्टर के शेयरों में भी कुछ रिकवरी हुई। इंडेक्स डेवियट एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी भी बढ़त में अहम भूमिका निभाई।

थोक महंगाई

जनवरी में 1.81% बढ़ी थोक मुद्रास्फीति
महंगाई ने उठाया अपना फन, 10 महीने के हाई पर पहुंची



कितनी बढ़ी थोक महंगाई

| वस्तु | दिसंबर | जनवरी |
|---------------------|--------|--------|
| प्रधानमंत्री आदिकरस | 0.21% | 2.21% |
| खाद्य पदार्थ | -3.50% | 6.78% |
| सब्सिडी | 1.14% | 3.66% |
| मांस | 2.95% | 7.58% |
| नॉन-फूड | 0.83% | 1.82% |
| ऑटोमोबाइल | -0.43% | 19.25% |

इनकी थोक महंगाई अभी भी कम

| वस्तु | दर | वाले | |
|-------|--------|-------|---------|
| अनाज | -1.41% | आलू | -38.85% |
| गेहूँ | -2.32% | प्याज | -33.42% |

(जनवरी 2025 के मुकाबले जनवरी 2026 में इतनी घटी कीमतें)

राजस्व को झटका

38 एफटीए के कारण सीमा शुल्क में होगा ₹1 लाख करोड़ का नुकसान



ट्रेड बैलेंस...

एफटीए से भारत को राजस्व का इतना नुकसान संभावित

| देश | 2025-26 | 2026-27 |
|-------------|---------|---------|
| आसिया | 40,731 | 40,883 |
| जापान | 11,852 | 11,365 |
| द. कोरिया | 10,524 | 10,872 |
| ऑस्ट्रेलिया | 4,879 | 5,016 |
| एलडीसी देश | 7,017 | 5,367 |
| पड़ोसी देश | 9,516 | 10,563 |
| यूईए | 6,231 | 9,267 |
| अन्य देश | 7,819 | 8,080 |

चीन-अमरीका से बढ़ा आयात, रूस से घटा

इन देशों को बढ़ा निर्यात

| देश | निर्यात | इजाफा |
|----------|---------|--------|
| यूईए | 3.97 | 29.27% |
| चीन | 1.64 | 55.65% |
| हांगकांग | 0.62 | 98.72% |
| नीदरलैंड | 1.25 | 20.47% |
| इटली | 0.79 | 32.10% |
| जर्मनी | 1.01 | 9.55% |

इन देशों को घटा निर्यात

| देश | निर्यात | गिरावट |
|-------------|---------|---------|
| अमरीका | 6.59 | -21.77% |
| बांग्लादेश | 0.84 | -20.25% |
| ब्रिटेन | 1.07 | -7.88% |
| सिंगापुर | 0.89 | -3.67% |
| ऑस्ट्रेलिया | 0.61 | -4.30% |
| फ्रांस | 0.57 | -11.20% |

इन देशों से बढ़ा आयात

| देश | आयात | इजाफा |
|-------------|-------|--------|
| रिव्दुजलैंड | 3.95 | 16.67% |
| चीन | 12.23 | 43.48% |
| यूईए | 7.04 | 23.71% |
| अमरीका | 4.49 | 7.69% |
| हांगकांग | 1.83 | 31.37% |
| स. अरब | 2.91 | |

2.86 अरब डॉलर का आयात किया भारत ने रूस से जनवरी 2026 में, यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 40.48% कम

ट्रेड डील

इस हफ्ते अमरीका जाएगा दल
इस हफ्ते भारत पर टैरिफ घट कर हो सकता है 18 फीसदी

नई दिल्ली: अमरीका इस सप्ताह भारत के कई निर्यात उत्पादों पर लगाए गए मौजूदा 25% टैरिफ को घटकर 18% कर सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि मुख्य वार्ताकार और ज्वाइंट सेक्रेटरी दर्पण जैन ने नेतृत्व में भारतीय अधिकारियों का एक दल अमरीका के साथ हुई ट्रेड डील की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अगले सप्ताह अमरीका का दौरा करेगा। यह दल ट्रेड डील के बचे समझौते बिंदुओं को फाइनल रूप देगा। इसके बाद मार्च 2026 तक फाइनल समझौता पत्र पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर होगा। अमरीका-भारत ट्रेड डील की घोषणा के बावजूद अभी समझौते के अनेक प्रावधान, सेक्टर व वस्तुओं की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों देशों का लक्ष्य मार्च में समझौते पर हस्ताक्षर करना है। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस की ओर से रैस्पॉन्सिव टैरिफ में कटौती के लिए जल्द ही एक कार्यकारी आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है। यदि इसमें देरी होती है, तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह इस मामले को उठाएगा।

अमरीका से सोना-चांदी का आयात बढ़ा सकता है भारत

नई दिल्ली @ पत्रिका: भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पहले ही अमरीका से तेल और गैस की खरीद बढ़ाई है। अब सरकार की योजना कीमती धातुओं के आयात में भी बदलाव करने की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भारत अब यूईए के बजाय अमरीका से अधिक सोना और चांदी खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस कदम से सोना-चांदी की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है और अमरीका के साथ व्यापार संतुलन (ट्रेड बलेंस) भी कम हो सकता है। अमरीका सोना और चांदी के व्यापार का एक बड़ा वैश्विक केंद्र है। वह सोना और चांदी का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, अमरीका कनाडा, भारत और ब्रिटेन जैसे देशों को अरबों डॉलर की कीमती धातुओं का निर्यात करता है। इन निर्यातों में कच्चा, परिष्कृत और आभूषण रूप में तैयार सोना-चांदी शामिल है।

पेज एक का शेष...

39 वर्ष...
राजनीतिक परिवार से ताल्लुक, कई जिलों में कलक्टर रहे: उत्तर प्रदेश में सितंबर 1986 में जन्मे अवि प्रसाद एलएलबी, एमबीए, एमबीएल और बीआइबीएफ (एच) पासआउट हैं। वर्तमान में रोजगार गारंटी परिषद मद्र के सीईओ हैं। पूर्व में कई जिलों में कलक्टर सहित कई पदों पर रह चुके हैं। वह उत्तरप्रदेश के एक प्रतिष्ठित व राजनैतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

शादी से...
हार्डकोरट ने आरोपी की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि विवाह के झूठे वादे पर प्राप्त सहमति अमान्य हो सकती है क्योंकि आरोपी पहले से विवाहित था।

ऐसे नकली...
3 'रमाट हनीपोट' सिस्टम- दूसरी बड़ी तकनीक 'हनीपोट' रही, जिसे 'साइबर अपराधियों' के लिए बिछाई गई डिजिटल चूहादानी' कहा जा सकता है। जैसे ही हेकर हमला करता है, यह सिस्टम उसे ब्लॉक करने के बजाय उलझाए रखता है और पैटर्न, लोकेशन आदि ट्रैक कर लेता है। भविष्य के हमले भी रुकेंगे।

4 यह मॉडल किन्ती भाषाओं को सपोर्ट करता है? यह मॉडल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मलयालम, तेलुगु और तमिल सहित पांच भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। यह 'कोड-स्विचिंग' (मिक्स भाषा) बोलने वाले भारतीयों की पहचान करने में भी सक्षम है।

गांव से शहर तक

कैशलेस इकोनॉमी की ओर भारत
₹40 लाख करोड़ की मुद्रा चलन में 57% भारतीयों की पहली पसंद यूपीआइ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई: भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और अब यूपीआइ पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) नकद लेन-देन से आगे निकल गया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 57 प्रतिशत भारतीय अब लेन-देन के लिए यूपीआइ को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि नकद का उपयोग 38 प्रतिशत तक सीमित रह गया है। यह बदलाव डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूत होती नींव को दर्शाता है। यह रिपोर्ट 15 राज्यों के 10,378 प्रतिभागियों पर आधारित सर्वे पर तैयार की गई, जिसमें उपभोक्ता, व्यापारी और सेवा प्रदाता शामिल थे।

यह हैं प्रमुख कारण

- छोटे व्यापारियों द्वारा यूपीआइ स्वीकार करने में वृद्धि
- तेज और सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया
- कम राशि के लेन-देन में भी डिजिटल विकल्प का उपयोग

ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी पैठ

- छोटे दुकानदार और बेंचर तेजी से यूपीआइ अपना रहे हैं
- प्रोत्साहन योजनाओं का असर
- एनपीसीआइ और रूपे से डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत

भारतीय शेयर बाजार में किसका कितना निवेश

| देश | निवेश |
|-----------|-------|
| अमरीका | 31.30 |
| लक्जमबर्ग | 5.23 |
| आयरलैंड | 4.66 |
| सिंगापुर | 4.58 |
| ब्रिटेन | 3.19 |
| मॉरीशस | 2.88 |
| नॉर्वे | 2.79 |
| जापान | 2.12 |
| फ्रांस | 1.90 |
| कनाडा | 1.86 |
| अन्य | 10.76 |

(राशि लाख करोड़ रुपए में)

एनपीएस में बदलाव

अलग फंड की तैयारी
इक्विटी में बढ़ सकता है निवेश, हेल्थ कवर भी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली: नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से जुड़े सरकारी कर्मचारियों और अन्य निवेशकों के लिए दोहरी खुशखबरी सामने आई है। एक ओर पेंशन फंड नियामक एनपीएस में इक्विटी निवेश की सीमा बढ़ाकर अधिक रिटर्न देने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पेंशन के साथ हेल्थ कवर जोड़ने और मेडिकल जरूरतों के लिए अलग मेडिकल पेंशन फंड बनाने की योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी। पेंशन फंड नियामक के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए इक्विटी निवेश की सीमा मौजूदा 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक की जा सकती है। इससे लंबी अवधि में अधिक रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ेगी और कर्मचारियों को बड़ा पेंशन कॉर्पस तैयार करने में मदद मिलेगी।

मेडिकल पेंशन फंड में मिलेंगे ये लाभ

- मेडिकल खर्चों के लिए अलग सुरक्षित फंड
- हेल्थ इश्योरेंस प्लान मिल सकेंगे
- अस्पतालों में इलाज के लिए बेहतर और तेज भुगतान व्यवस्था होगी

मजबूत बनाने की कोशिश: पेंशन फंड रेगुलेटर एनपीएस को और बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। अभी एनपीएस में सिर्फ 1 करोड़ लोग जुड़े हैं, जो काफी कम है। इसे बढ़ाने के लिए रेगुलेटर नेशनल पेंशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात कर रही है। इसकी की मद्दद से नए निवेशकों को आसानी से जोड़ा जा सकेगा।



Please Support me by Joining my Private channel

YOU WILL RECIEVE NEWSPAPERS EARLIER THAN ANYONE OUT THERE. 🙏

📖 Indian Newspapers:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| <u>1) Times of India</u> | <u>6) The Hindu</u> |
| <u>2) Hindustan Times</u> | <u>7) Live Mint</u> |
| <u>3) Business line</u> | <u>8) Financial Express</u> |
| <u>4) The Indian Express</u> | <u>9) Business standard</u> |
| <u>5) Economic Times</u> | <u>+All Editorial PDFs</u> |

Uploding
starts from
5AM

📌 Access to all this
In Just 19 Rupees
[lifetime Validity].

Click below to

Join

📖 International
Newspapers
Channel

📖 Magazine Channel
(National & International).



प्रेरणा

अच्छी यादें इकट्ठा कीजिए। ये वे खुशियां हैं, जो कभी खत्म नहीं होतीं। - नैरी क्यूरी

संपादकीय

जेन-जी बांग्लादेश को

अशांति में नहीं धकेलेगी

बांग्लादेश के नए पीएम के सलाहकार ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को 'रीसेट' किया जाएगा। इस सोच का कारण है वहां के समाज की पकिस्तानी समाज से अलग ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विकास की राह पर काफी आगे निकलना। यह सच है कि बांग्लादेश में युवाओं के एक वर्ग ने सत्तापरिवर्तन तो किया, लेकिन नेतृत्व और उद्देश्य के अभाव में धार्मिक उन्माद की ओर मुड़ा। अल्पसंख्यक हिन्दुओं (8% आबादी) को शिकार बनाया गया। लेकिन वोटों का विश्लेषण बताता है कि युवाओं ने भी कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी को ही नहीं, अपनी ही पार्टी एनपीपी को भी खारिज किया। देश के 1.32 करोड़ हिन्दू मतदाताओं ने भी अपना भरोसा बहुमत वाली बीएनपी पर जताया। संविधान सुधार पर हूँ रणधर्मियों में 68% मतदाताओं ने सुधार के पक्ष में वोट दिया। चूंकि ये सुधार एक लिबरल, निष्पक्ष समाज और विकासपरक शासन पर आधारित हैं-लिहाजा नए पीएम को हिन्दुओं के प्रति समानता का भाव और भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध रखने होंगे। पकिस्तान से उलट, बांग्लादेश कट्टरपंथ का हिमायती भी नहीं रहा। इसलिए उसकी प्रति व्यक्ति आय पकिस्तान से दोगुनी है। वह देश मल्लोफाइनैंग, उद्योग और निर्यात से समृद्ध हुआ। जेन-जी आन्दोलन किसी भी कौमत्र पर अपने देश को पकिस्तान जैसी अशांति और अविकास की ओर नहीं धकेलेगा।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com



श्रोता बनने की बारी आए तो अच्छे श्रोता बनिए

अच्छा सुनने के लिए अच्छा होना ही पड़ेगा। पक्षीराज गरुड़ ने जब ककभुशुंडि जी से निवेदन किया कि क्या सुनाए तो तुलसीदास जी ने गरुड़ जी की वाणी का वर्णन किया है- सुनत गरुड़ के गिरा बिनीत, सरल सुगम सुखद सुपुनीत। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखाप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही ककभुशुंडि जी के मन में परम उत्साह हुआ। यह एक श्रोता के लक्षण बताते हैं। जब भी श्रोता बनने की बारी आए, अच्छे श्रोता बनिए। जैसे गीता के मुख्य वक्ता तो कृष्ण जी ही हैं, पर जब उनके श्रोता बनने की बारी आई तो उन्होंने कमाल किया। कृष्ण जी ने गीता में 620 श्लोक बोले हैं। अर्जुन ने 57 बोले। गीता के पहले अध्याय में 27 श्लोक तक तो संजय ने दृश्य बताया। उसके बाद 19 श्लोक में अर्जुन धाराप्रवाह बोले और पूरे धैर्य के साथ श्रीकृष्ण ने उनको सुना। आजकल कोई किसी को सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन श्रोता बनने का अवसर आए तो गरुड़ जी की तरह, कृष्ण जी की तरह कुछ शुभ लक्षण भीतर उतारें।

• Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

नजरिया • हमें संतुलित जुड़ाव बनाए रखना चाहिए

स्थिर बांग्लादेश भारत की उन्नति के लिए भी लाभदायक

आस-पड़ोस

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर



बांग्लादेश चुनाव ने एक निर्णायक नतीजा दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को मिला दो-तिहाई बहुमत महज चुनावी जीत नहीं, बल्कि साल भर की अस्थिरता, वैचारिक टकराव और संस्थागत अनिश्चितता के बाद राजनीतिक स्थिरता का संकेत है। यह चुनाव एक सामान्य संसदीय प्रक्रिया से ज्यादा इस बात पर राष्ट्रीय निर्णय जैसा है कि श्रेष्ठ हसीना की खानगी और उथल-पुथल के बाद देश आगे कैसे बढ़ना चाहता है। एक सकारात्मक संकेत तत्काल दिखता है। जमात-ए-इस्लामी का कमजोर प्रदर्शन बताता है कि मतदाता कट्टरपंथी शासन को लेकर सतर्क हैं। भले समाज के कुछ हिस्सों में इस्लामवादी बयानबाजी का प्रभाव हो, लेकिन वोटों ने कट्टरपंथी ताकतों को सत्ता सौंपने से गुरेज किया है। यह घटना स्थिरता देने वाली है।

फिर भी ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी कि जमात का असर खत्म हो गया। उसका नेटवर्क, सामाजिक प्रभाव, और लोगों को सड़कों पर जुटाने की क्षमता कायम है। उसकी सियासी ताकत घट सकती है, लेकिन वैचारिक प्रभाव बना रहेगा। इसी सच्चाई से निपटना बीएनपी की पहली बड़ी परीक्षा होगी। बीएनपी को स्पष्ट बहुमत भारत के लिए स्वागत योग्य है। इससे गठबंधन की कमजोरियां घटेंगी और नीतिगत जड़ता का जोखिम कम होगा। यह बहुमत तारिक रहमान और उनकी टीम को वैधानिकता के साथ ही जिम्मेदारी भी देता है। अस्थिरता का बहाना अब नहीं चल पाएगा। शासन, आर्थिक पुनरुद्धार और संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी। बांग्लादेशी युवाओं ने गरिया, जवाबदेही और अवसरों की मांग की थी। बीएनपी सरकार की विश्वसनीयता अब इस पर निर्भर करेगी कि वह कैसे प्रशासनिक दक्षता बहाल करती है, निवेशकों का भरोसा लौटाती है और अल्पसंख्यकों को कैसे आवरस्त करती है।

आवामी लोग को भी अनिश्चितकाल के लिए अन्वेषण नहीं कर सकते। किसी बड़े राजनीतिक दल को स्थायी रूप से बाहर कर देना संरचनात्मक असंतुलन पैदा करता है। भले तत्काल प्रतिबंध हटाना संभव न हो, लेकिन राजनीतिक हलता सामान्य करने की राह खुली रहनी चाहिए। बांग्लादेश में स्थायी स्थिरता के लिए टकराव के बजाय समावेशन जरूरी है। श्रेष्ठ हसीना का भारत में रहना एक फैक्टर बना रहेगा, लेकिन सिर्फ यही द्विपक्षीय रिश्तों की धुरी नहीं

होनी चाहिए। दोनों देशों के व्यापक राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे पर निजी या कानूनी मसले भारी नहीं पड़ने चाहिए। न तो बांग्लादेश का भविष्य किसी एक व्यक्ति के भाग्य से परिभाषित होना चाहिए, न ही भारत-बांग्लादेश संबंध उसी एक मुद्दे तक सीमित होने चाहिए। बांग्लादेश के सामने एक बड़ी चुनौती वैचारिक कट्टरता के आकर्षण से बचना भी है। कट्टरपंथ थोड़े समय के लिए जनसमर्थन तो जुटा सकता है, लेकिन टिकाऊ शासन या आर्थिक मजबूती शायद ही दे पाए। बांग्लादेश में सेना की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। हल की अस्थिरता में वह काफी हद तक फेरव और संस्थागत बनी रही। जब तक राजनीतिक संक्रमण मजबूती है, उसका ऐसे ही स्थिर रहना जरूरी होगा। भारत के लिए यह समय संतुलित जुड़ाव रखने का है। नीते वर्ष भारत का संयम उल्लेखनीय रहा। वह तनाव बढ़ाने वाली बयानबाजी से दूर रहा। यही युक्तिगण जारी रहना चाहिए। न सार्वजनिक दिखावा, न टिप्पणी, न संवेदनशील मुद्दों को अनावश्यक फिर से खोलना। संयमित सुरों में कृतनीति बेहतर कारण होती है। रिश्तों को री-सेट करने के लिए अब संकेतिक पहल उपयोगी हो सकती है। मंत्री स्तर की पहल हो या

श्रेष्ठ हसीना का भारत में रहना एक फैक्टर बना रहेगा, लेकिन सिर्फ यही द्विपक्षीय रिश्तों की धुरी नहीं होनी चाहिए। दोनों देशों के व्यापक राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे पर निजी या कानूनी मसले भारी नहीं पड़ने चाहिए।

सही भावना से दिया कोई निमंत्रण, ऐसा कोई भी उच्च स्तरीय जुड़ाव सद्भाव का संकेत दे सकता है। पिछले दिनों ही शोक के क्षणों में सम्मानजनक कृतनीतिक जुड़ाव ने बताया कि कैसे प्रतीकात्मक कदम सिद्धांतों को बदले बिना भी भरोसा बढ़ा सकते हैं। आर्थिक तौर पर पारस्परिक निर्भरता ही स्थिरता का सबसे मजबूत फैक्टर है। कनेक्टिविटी, ऊर्जा व्यापार, सप्लाई चेन और 'पीपल टू पीपल' रिश्ते राजनीति से ऊपर उठ कर दोनों देशों को आपस में जोड़ते हैं। एक स्थिर पूर्वी पड़ोसी से भारत की उन्नति को भी लाभ होगा। यही पारस्परिकता नीति का मायदर्शक सिद्धांत होनी चाहिए।

एक स्थिर बांग्लादेश बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश घटता है, जबकि अस्थिर बांग्लादेश बड़ाता है। म्यांमार को लेकर अनिश्चितता और बंगाल की खाड़ी में बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच बांग्लादेश में राजनीतिक सामंजस्य बने रहना न केवल राष्ट्रीय, बल्कि क्षेत्रीय हितों को भी साधता है। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • हमें अपने विकल्पों को बढ़ाना होगा

तेल पर निर्भरता को कम करना अब जरूरी हो गया है

एनर्जी

अरविंद सुब्रमण्यन

भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार



2021 में भारत का रूस से तेल आयात उसके कुल तेल आयात का 2% था। 2024 में यह बढ़कर 30-36% तक पहुंच गया- मुख्यतः रूसी तेल पर भारी छूट के कारण। अब भारत पर रूस से तेल लेना बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने रूसी तेल आयात पूरी तरह बंद कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि रूसी क्रूड का हिस्सा पहले की तुलना में कुछ ही कम हुआ है- दिसंबर 2025 में यह 31.5% था, जो पिछले वर्ष के 36.5% से घटा है। वहीं अमेरिका से तेल आयात बढ़ रहा है।

सरकार ने साफ किया है कि ऊर्जा सुरक्षा और उपलब्धता उसकी प्राथमिकता है और यों भी उसकी नीति विविधता की दिशा में बढ़ने की है, किसी एक स्रोत पर निर्भर रहने की नहीं। विदेश सचिव का कहना है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों, मूल्य और बाजार-स्थितियों के आधार पर ही ऊर्जा स्रोतों का चयन करेगा। इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि भारत ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण की दिशा में कदम उठा रहा है।

आर्थिक गतिशीलता और बढ़ती समृद्धि ने जहां भारत को ऊर्जा के मामले में और अधिक आयात-निर्भर बना दिया है, वहीं भारत के लिए यह और आवश्यक हो गया है कि वह अपनी राजनीतिक स्वायत्तता को अधिकतम करने के लिए इस निर्भरता को घटाए। एक विकल्प यह हो सकता है कि हम अमेरिका की तरह हाइड्रोकार्बन उत्पादन और निवेश को बढ़ाएं। दूसरा, और संभवतः अधिक दूरदर्शी विकल्प है चीन की राह अपनाना और स्वयं को एक रिन्यूएबल एनर्जी आधारित इलेक्ट्रो-स्टेट में रूपांतरित करना। ऊर्जा के सूर्य और पवन जैसे स्रोत अधिकांश देशों में उपलब्ध हैं और भारत में तो विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में हैं। इन स्रोतों पर अधिक निर्भरता न केवल आयात-निर्भरता को घटाएगी, बल्कि व्यापक विद्युतीकरण को भी प्रोत्साहित करेगी- जो भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है : डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन, एआई और अन्य उभरती तकनीकें।

इसके अलावा, भारत के पास हाइड्रोकार्बन से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर राजनीतिक रूपांतरण के दो और टोस कारण हैं। पहला है- प्रदूषण। कोयला और तेल जलाने की घरेलू सामाजिक लागत विनाशकारी रही है, जैसा कि विश्व बैंक के एक हालिया अध्ययन से स्पष्ट होता है- नई दिल्ली को अक्षर एक गैस चैम्बर कहा जात है- यह हमें याद दिलाता है कि हाइड्रोकार्बन

पर निर्भरता बढ़ने के क्या परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में कोयले के उपयोग को और बढ़ाना विकल्पपूर्ण नहीं है- विशेषकर तब, जब 40-60 अरब डॉलर के थर्मल पावर निवेश पहले ही फंसे हुए हैं या जोखिम में हैं। नए कोयला संयंत्र इस वित्तीय बोझ को और बढ़ाएंगे।

बेशक, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना एक नए प्रकार की निर्भरता का जोखिम भी पैदा करता है। तेल पर निर्भरता घटाने की कोशिश कहीं तकनीकी पर निर्भरता में न बदल जाए- क्योंकि सोलर मैन्युफैक्चरिंग का 80% से अधिक निर्यात चीन के पास है और बैटरी आपूर्ति शृंखलाओं पर भी उसका दबदबा है। लेकिन यही हमें दूसरे, और कहीं अधिक निर्णायक कारण की ओर भी ले जाता है- सस्ती बिजली। यदि भारत को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का अवसर साधना है, तो उसे सस्ती और विश्वसनीय बिजली की आवश्यकता होगी। भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बिजली की ऊंची लागत ने गंभीर रूप से बाधित किया है। भारत में बिजली की लागत जितनी होनी चाहिए थी, उससे लगभग दोगुनी रही है- और प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भी लगभग दोगुना अधिक है। इस मुद्दे पर बिजली

यदि हमें अपनी ऊर्जा निर्भरता पर काबू पाना है, तो हमें स्वयं को एक इलेक्ट्रो-स्टेट में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को तेज करना होगा। केंद्र सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन केवल नीतिगत घोषणाएं पर्याप्त नहीं होंगी।

के कारण ही भारतीय कारखाने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते रहे हैं।

हल में हुए व्यापार समझौते भारत को चहना प्लस वन अवसर का लाभ उठाने का मौका दे सकते हैं- यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चीन से बाहर उत्पादन का विविधीकरण। लेकिन इसके लिए पहले कोयले सुधारों की आवश्यकता होगी- विशेषकर बिजली क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार, जो सस्ती, स्थिर और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित कर सकें। राजनीतिक स्वायत्तता, औद्योगिक पुनरुत्थान और पर्यावरणीय संतुलन- इन तीनों को साधने के लिए ऊर्जा नीति केंद्र में होनी चाहिए।

(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट) इस लेख के सहलेखक एनर्जी इकोनॉमिस्ट नवनील शर्मा हैं।



इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

टेक्नोलॉजी पिछले 12 महीने में सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में 30 साल की सबसे बड़ी गिरावट, खुद का अस्तित्व बचाने का संकट

सॉफ्टवेयर कंपनियों को एआई की चुनौती; एक साल में 181 लाख करोड़ घटा बाजार मूल्य, स्टार्टअप अब खुद को एआई से जोड़ रहे हैं

सारा केसलर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने सॉफ्टवेयर कंपनियों के अस्तित्व के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। नवंबर 2022 में चैटजीपीटी आने के तीन साल बाद अब इन कंपनियों को एआई की विध्वंसक क्षमता का अहसास हो रहा है। एआई ने इंटरनेट को जबर्दस्त नुकसान पहुंचाया है। सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए पहचान का संकेत पैदा हो गया है। इसलिए वे हर स्तर पर स्वयं को एआई कंपनियों बनाने की जी-तोड़ कोशिश में जुटी हैं। यही कारण है कि चमकते इमोजी और जाड़ू आइकन हर जगह नजर आने लगे हैं। एआई पॉपुलर वेबसाइट डोमेन बन गया है। वेंचर कैपिटल निवेशक कहते हैं, सभी सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में किसी न किसी किस्म का एआई पैल जुड़ा है। इस दहशत का कारण साफ है। पिछले 12 महीने में सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयर कीमतों में तीस साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है। जेपी मॉर्गन बैंक के अनुसार कंपनियों का बाजार मूल्य अपने

शिखर से 181 लाख करोड़ रुपये से अधिक नीचे आ गया है। एसएंडपी नीथ अमेरिकन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंडेक्स ही पिछले महीने लगभग बीस प्रतिशत गिर चुका है। बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों सेल्सफोर्स और सर्विसनाउ के शेयरों में पिछले साल 40 फीसदी से अधिक गिरावट आई है। और यह नुकसान लगातार जारी है। एंथ्रोपिक के क्लॉड ओपस 4.6 जैसे नए शक्तिशाली एआई टूलस की रिलीज ने बताया कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। स्टार्टअप की दुनिया पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 2024 में सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पिचबुक ने क्लाउड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल के लिए सब्सक्रिप्शन लेने वाले बिजनेस मॉडल को वेंचर की बुनियाद बताया था, लेकिन एआई के कारण अब यह हलचल धुंधली पड़ चुकी है। सॉफ्टवेयर बनाने और कंपनियों द्वारा उसका भुगतान करने के तरीकों को एआई बदल सकती है।

© The New York Times

अधिकतर पूंजी एआई कंपनियों में जा रही



स्टार्टअप और वेंचर फंड कंपनी 500 ग्लोबल के पार्टनर टोनी वांग बताते हैं, कुछ साल पहले चंद स्टार्टअप ही खुद को एआई कंपनियों के बतौर पेश करते थे। अब सभी स्टार्टअप ऐसा कर रहे हैं। सीबी इनसाइट्स के मुताबिक पिछले साल लगभग आधी वेंचर कैपिटल एआई स्टार्टअप के खाते में गई है। 151 स्टार्टअप कंपनियों में से 135 ने स्वयं को एआई कंपनियां बताया है। इनमें 14 के नाम एआई से खत्म हो चुके हैं।

वैटबॉट से साल भर में करोड़ 900 करोड़ रुपए पहुंचा

इंओगन मैकबे 2022 में कस्टमर सर्विस सॉफ्टवेयर कंपनी इंटरकॉम के दोबारा सीईओ बने। उन्हें लगभग एक माह हुआ था। कंपनी की बढ़त लगभग ठहर गई थी। मैकबे को जल्द ही अस्तित्व के संकट का आभास हो गया। उन्होंने कंपनी को एआई कंपनी में

तब्दील कर दिया। इसी साल चैट जीपीटी इंटरकॉम रिलीज हुआ। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इसके बाद उनकी कंपनी के करोड़ों में जम्कर उछाल आया। अब उनकी कंपनी की सालाना आय करीब 900 करोड़ रुपए हो गई।

फाउंडर्स का फोकस पूरी तरह एआई पर हो गया है

सॉफ्टवेयर फाउंडर्स के लिए इवेंट आयोजित करने वाली कंपनी एसएएएसटीआर की मार्केटिंग प्रमुख एमेलिया लेरुटी कहती हैं कि फाउंडर्स के रुझ में पिछले एक साल में काफी बदलाव आया है। वे अपने प्रोडक्ट में एआई शामिल करने लगे हैं। दरअसल, एआई के आने के बाद से कंपनियों में एक तरह की दहशत है। उन्होंने भी फाउंडर्स का फोकस दर्शाने के लिए कंपनी का नाम एसएएएसटीआर एआई कर लिया है। लेरुटी कहती हैं-उनका ज्यादा समय अब एआई एजेंडस को तैनात करने में बीताता है।

इस हफ्ते चर्चा में...

ट्रम्प के टैरिफ का ज्यादा भार अमेरिकियों पर ही



90 प्रतिशत भार पड़ा है, अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों पर राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ का। न्यूयॉर्क फंड की रिसर्च में यह जानकारी सामने आई है।

13.60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं चीन की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर चिपस बनाने के अभियान पर।

13 हजार करोड़ रुपए

से अधिक खर्च किए हैं, अमेरिका में हॉर्स रैसिंग में घोड़े दौड़ाने वाले मालिकों ने।

महत्वाकांक्षी अब अमेरिका में भी त्यक्त पूजा पर जोर ट्रम्प को खुश करने के लिए उनकी तस्वीर डॉलर पर छापने की तैयारी

पीटर डेकर

दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रम्प खुद को दुनिया की अकेली प्रभावशाली हस्ती बता रहे हैं। वे अपने आफको हीरो, भगवान, शहंशाह, फौजी कमांडर और यहां तक कि पोप के समान दिखा चुके हैं। उन्होंने होटलों, कैसिनो, एयरप्लेन, स्टीस, नेकट्राई और बोल्लबंद पानी तक पर अपना नाम चिपका रखा है। ट्रम्प और उनके समर्थक अब व्यक्ति पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रम्प की तस्वीरें पूरे वाइट हाउस में लगी हैं। सकाराई इमारतों पर उनके बहुमंजिला बैनर लटके हैं। वे नेशनल पार्कों के पास पर नजर आते हैं। जल्द ही एक डॉलर के सिक्के पर ट्रम्प की तस्वीर होगी। यदि मंशा पूरी हो गई तो वे वाशिंगटन डेलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वाशिंगटन कमांडर्स के भावी स्टेसन पर भी दिखाई पड़ेंगे। अमेरिकी प्रशासन ट्रम्प के नाम पर वॉरशिप की एक नई श्रेणी बनाने पर विचार कर रहा है। उनके सहयोगी विदेशी नेताओं पर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रम्प का नाम आगे बढ़ाने के लिए दबाव डालते और धमकते हैं।



जेन्सविले, ओहायो में मूर्तिकार के स्टूडियो में रखी डोनाल्ड ट्रम्प की 15 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा

© The New York Times

विवाद जापान में घटे चीनी ट्रिस्ट अर्थव्यवस्था को नुकसान

रिव अक्रीडाउटिक

चीन ने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा न करने की सलाह दी है। जापान की प्रधानमंत्री तक्राहूकी साने ने नवंबर में कहा था कि चीन का हमला होने की स्थिति में ताइवान की रक्षा करने के लिए जापान आगे आएगा। इस बयान से चीन भड़क गया है। जापान में सबसे अधिक पर्यटक चीन से आते हैं। पिछले साल दिसंबर में पूर्व वर्ष की तुलना में 45% पर्यटक कम आए। जापान सरकार के डेटा के अनुसार पिछले साल के तीन महीनों में देश में पर्यटकों के खर्च में 2.8% की गिरावट आई है। बीते चार वर्षों में यह पहली गिरावट है। जापान राष्ट्रीय टूरिज्म संगठन का कहना है कि चीनी पर्यटकों ने पिछले साल अन्य पर्यटकों के मुकाबले लगभग चार गुना ज्यादा खर्च किया था। जापान चीन से दुर्लभ धातुओं की सप्लाई पर रोक की स्थिति के लिए भी तैयारियां कर रहा है। इन धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर मिहाइल सिस्टम तक बनाने में होता है।

© The New York Times

राजनीति इजराइल के अंदरूनी मामलों में दखल पर ट्रम्प की आलोचना

इसाबेल कार्नर

राष्ट्रपति के कार्यलय ने एक बयान में स्पष्ट किया कि हरजोग ने अब तक माफी के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। न्याय मंत्रालय मामले की समीक्षा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत नहीं दिए जाने के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने जम्कर खरीखोटी सुनाई है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रम्प ने राष्ट्रपति इसका हरजोग के इस कृत्य को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा, नेतनयाहू को मुकदमे से माफी न देने के लिए इजराइल की जनता उन्हें नहीं छोड़ेगी। हालांकि इजराइल के फेरुल मामलों में खुले दखल और राष्ट्रपति के प्रति अपमानजनक लहजे की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। हरजोग सहित कई वरिष्ठ इजराइली नेताओं, अधिकारियों ने ट्रम्प के रवैये का विरोध किया है। वहीं नेतनयाहू के कुछ कट्टर समर्थकों ने ट्रम्प का समर्थन किया है। ट्रम्प की टिप्पणी के बाद इजराइली

फाइनेंस यूरोपीय देश वीसा, मास्टर कार्ड का विकल्प खोज रहे

विजयनवाकर

वर्षों से यूरोप में अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता खत्म करने की मांग होती रही है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रेड वॉर की वजह से ईयू में यूरोपीय व्यवसायियों और उपभोक्ताओं के लिए प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्म बनाने में दिलचस्पी बढ़ी है। इसमें पेमेंट सिस्टम भी शामिल होगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक बोर्ड के सदस्य पिरो सिपोलोन के अनुसार पेमेंट सिस्टम बनाने का मामला लंबे समय से लंबित है। यूरोपियन पेमेंट इनिशिएटिव की सीईओ मार्टीन वीमर्ट ने बताया कि हमने इंस्ट्रुटी से कहा है कि वीसा-मास्टरकार्ड को टक्कर देने पर गंभीरता से विचार करें। यूरोपियन यूनियन के देशों में होने वाले दो तिहाई कार्ड ट्रांजेक्शन वीसा या मास्टरकार्ड से होते हैं। 16 यूरोपीय बैंकों और फंडेनशिपल सर्विसेस के कंसोर्टियम ईपीआई ने 2024 में एपल पे जैसा पेमेंट कार्ड पेश किया है। डिजिटल यूरो करेंसी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे अमेरिकी फंडेनशिपल कंपनियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक इस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहा है। © The New York Times

तकनीक की ताकत

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई के शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में शुरू होना ऐसी ऐतिहासिक घटना है, जिससे देश में एआई को बहुत बल मिलने वाला है। यहां यह तथ्य किसी खुशखबरी से कम नहीं कि एआई के मामले में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत से आगे केवल अमेरिका और चीन हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे प्रतिस्पर्द्धी देश बनकर उभरा है। भारत के तेजी से बढ़ते तकनीकी तंत्र, उसके लिए उचित परिवेश और सशक्त प्रतिभाओं का इसमें बड़ा योगदान है। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि भारत अच्छे कंप्यूटर इंजीनियरों का देश है। एआई के मोर्चे पर हमारे इंजीनियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

हालांकि, यहां हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। ध्यान रहे, एआई के मोर्चे पर अमेरिका का वाइब्रेंसी स्कोर 78.6 है, जबकि चीन का 36.95 और भारत का स्कोर 21.59 है। हम एआई के मोर्चे पर दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस सहित कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आगे चल रहे हैं।

भारत एआई में तीसरी सबसे बड़ी ताकत होने के साथ ही, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, इसलिए भी भारत में एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन महत्वपूर्ण है। भारत ऐसा पहला देश है, जो

भारत एआई में तीसरी सबसे बड़ी ताकत होने के साथ, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, इसलिए यहां एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है।

विकसित नहीं है। पर जिसे एआई में विकसित माना जाता है। एआई शिखर सम्मेलन अब तक विकसित देशों में ही होते आए थे, यह पहला मौका है, तीसरी दुनिया के एक देश में आयोजन हो रहा है। यह विशाल आयोजन 16 फरवरी से शुरू हुआ है और 20 फरवरी तक चलना। इस

‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ के साथ-साथ एक एक्सपो या मेले का आयोजन भी नई दिल्ली में हो रहा है। इस मेले में 13 देशों के पवेलियन हैं और कुल पवेलियन की संख्या 300 बताई जा रही है। इससे भी एआई क्षेत्र में भारत की बढ़ती अहमियत स्पष्ट

हो जाती है। वाकई आज एआई के सहारे आम आदमी को मदद पहुंचाने, पृथ्वी की सुरक्षा करने और प्रगति सुनिश्चित करने की जरूरत है। यह शिखर सम्मेलन यदि आम आदमी को लाभ देने की दिशा में थोड़ी भी पहल कर सका, तो यह आयोजन सफल हो जाएगा। आज दुनिया के अनेक देश और विशेषज्ञ गौर से इस शिखर सम्मेलन की ओर देख रहे हैं। तमाम गरीब और विकासशील देश भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और उन्हें यह आशंका भी है कि एआई का लाभ उन तक कैसे पहुंचेगा? विकसित देशों में अगर तकनीक व विकसित उत्पाद किफायत में साझा करने का भाव होता, तो दुनिया में इतनी आर्थिक व सामाजिक असमानता नहीं होती। ऐसे में, एआई क्षेत्र में भारत का विकास तकनीक और उसके उत्पादों की कीमतों को भी कम रखने में सहायक होगा। अभी ज्यादा वर्ष नहीं बीते हैं, कोरोना वैक्सीन व दवाओं के मामले में हमने देखा है, जब दुनिया को जरूरत थी, तब भारत ने आपूर्ति की। भारत की यह ताकत स्थानीय स्तर पर ज्यादा बढ़नी चाहिए। चुनौती बहुत बड़ी है, अपने इंजीनियरों को भारत में ही रोकना होगा, ताकि तकनीक का भारतीय स्वरूप निखरे। भारत में एआई में निवेश बढ़ाना और उसके लिए परिवेश सुधारना होगा। नई दिल्ली में एआई का यह शिखर सम्मेलन हमारे लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होना चाहिए। हमारे लिए सही और किफायती लक्ष्य यही है कि भारतीय एआई प्रतिभाएं भारत को तेजी से आगे लाने में पूरा जोर लगा दें।

हिन्दुस्तान | **75 साल पहले** 17 फरवरी, 1951

कोलम्बो योजना

गत वर्ष जनवरी 1950 में कोलम्बो में राष्ट्रमंडलीय मंत्रिण एकत्र हुए थे और उन्होंने दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों की उन्नति के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करने का निश्चय किया। एक राष्ट्रमंडलीय परामर्शदात्री कमेटी भी संगठित की गयी, जिसकी तब वर्ष 1951 में सिडनी में बैठक हुई थी। राष्ट्रमंडलीय देशों ने दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के विकास लिए एक छः वर्षीय योजना तैयार की है, जो कोलम्बो योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना को कार्यान्वित करने में 2 अर्ब पौण्ड अर्थात् 26 अर्ब 67 करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। कोलम्बो योजना को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रमंडलीय परामर्शदात्री समिति की बैठक इन दिनों कोलम्बो में हो रही है। राष्ट्रमंडलीय देशों ने इस योजना में अपने दायरे से बाहर के देशों का सहयोग भी आमंत्रित किया है। पहली बार अमरीकी प्रतिनिधि राष्ट्रमंडलीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग ले रहा है। यह निश्चित है कि राष्ट्रमंडलीय देश अपने तौर पर जितने साधन जुटा सकते हैं, उतने जुटाने की कोशिश करेंगे। किन्तु जितनी विशाल धनराशि की आवश्यकता है, उतनी वे स्वयं नहीं जुटा सकते हैं। स्वभावतः उनकी दृष्टि अमरीका की ओर जाती है; कारण दुनिया के देशों में आज वही एक ऐसा देश है, जो सहायता और सहयोग का हाथ आगे बढ़ा सकता है। अमरीका भी यह अनुभव करता है कि दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया की सहायता की जानी चाहिए।

इस प्रदेश के लोगों का जीवन-स्तर काफी गिरा हुआ है। भूख और दरिद्रता में उन्हें डेर लिया है। यह स्थिति साम्यवाद के प्रसार के लिए बहुत अनुकूल है। जो लोग साम्यवाद को सन्ध्य जीवन के लिए एक खतरा महसूस करते हैं और उनमें अमरीका प्रमुख है, उन्हें इस स्थिति को बदलने के काम में आगे होकर हाथ बटाना चाहिए। केवल फौजी तैयारियों और राजनीतिक वागयुद्ध से साम्यवाद का प्रसार नहीं रोका जा सकता। उसके लिए तो भूख और दरिद्रता की जड़ को काटना होगा। कोलम्बो योजना का अभिप्राय रोग को जड़ मूल से नष्ट करना है। अमरीकी प्रतिनिधि ने कोलम्बो में यह कहा है कि अमरीका ने एशिया को बुरा श्रम समझकर अपना दिमाग से नहीं निकाल दिया है। वह इस प्रदेश में गरीबी से लड़ने में सहायता अवश्य देगा।

चलती हैं। इससे वायु प्रदूषण को कम करने में निश्चय ही मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ये गाड़ियां ध्वनि प्रदूषण को भी खत्म करने में कारगर मानी जाती हैं, क्योंकि इन गाड़ियों से आवाज बेहद ही कम निकलती है, नाममात्र का। इस कारण ध्वनि प्रदूषण पर भी इसका खूब असर पड़ेगा। ऐसे में, जरूरी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की और अधिक सुलभ बनाने के प्रयास किए जाएं। लोगों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि जरूरी हो, तो ऐसी गाड़ियों पर सब्सिडी भी बढ़ाई जाए, ताकि सड़कों पर सिर्फ यही वाहन दिखें। वास्तव में देखा जाए, तो आने वाले समय में सौर ऊर्जा से भी वाहनों को चलते हम देख सकते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का विकल्प हमें ढूंढना ही होगा। पृथ्वी को स्वच्छ बनाने के लिए पर्यावरण-हितैषी गाड़ियां आवश्यक हैं।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

कूटनीति का अहम औजार बनती एआई



अरविंद गुप्ता | पूर्व राजनिक एंव डायरेक्टर, वीआईएफ

सो मवार से नई दिल्ली में ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। यह कितना बड़ा आयोजन है, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि तकरीबन 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष इसमें शिरकत कर रहे हैं। कई टेक कंपनियों के सीईओ व हजारों एआई कंपनियों के प्रतिनिधि भी इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। 120 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में एआई के समावेशी उपयोग और उसके प्रभाव को व्यापक बनाने पर चर्चाएं की जाएंगी।

एआई का, विशेषकर चार-पांच वर्षों में हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है, यह प्रधानमंत्री मोदी के टवीट से जाहिर हो जाता है। सोमवार को ‘एक्स’ पर उन्होंने लिखा, मानव-केंद्रित विकास में एआई के इस्तेमाल को लेकर भारत खासा प्रतिबद्ध है। निस्संदेह, यह ऐसी तकनीक है, जो विश्व और हमारे समाज के स्वरूप को बदलने में सक्षम है। यहां तक कि हमारी रोजाना की जिंदगी पर भी यह काफी असर डालने वाली है। ऐसे में, स्वाभाविक ही तमाम देश एआई को प्राथमिकता देने लगे हैं। अगर एआई की दौड़ में वे पीछे छूट गए, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नतीजतन, कूटनीति में एक अहम औजार के तौर पर एआई इस्तेमाल होने लगी है। एआई सम्मेलन में (मिछले सम्मेलनों में भी) इतने बड़े पैमाने पर वैश्विक नेताओं की भागीदारी से इसकी तरसदी भी होती है।

पहले के समय में कूटनीतिक मुलाकातें होती थीं। राष्ट्राध्यक्ष एक-दूसरे से मिलते थे और अपने-अपने हित साधा करते थे। बाद में, ‘आर्थिक कूटनीति’ का दौर आया, फिर ऊर्जा, कोविड-19 के बाद ‘हेल्थ’, और अब एआई कूटनीति का जमाना है। इस तरह, बीते वर्षों में कूटनीति के हमने कई खंड देखे हैं, जो आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। नई दिल्ली में आयोजित एआई सम्मेलन इसी की अगली कड़ी है, जिससे संकेत मिलता है कि कूटनीति में एआई का प्रभाव और बढ़ने

अब तमिलनाडु में भी चुनावी रेवड़ी भरोसे राजनीति

देश के राजनेताओं, खासकर सत्तारूढ़ पार्टियों के बीच अब यह आम धारणा बन गई है कि मतदाताओं, विशेषकर महिला वोटरों की जेबें भरकर वे सत्ता-विरोधी रूझनों से पार पा सकती हैं। यह प्रयोग महाराष्ट्र जैसे अमीर सूबे से लेकर बिहार जैसे गरीब प्रांत तक सफल रहा है। हैरानी नहीं कि तमिलनाडु की द्रमुक सरकार अब राज्य के मतदाताओं पर तोहफों की बारिश कर रही है।

पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य की लगभग 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में पांच-पांच हजार रुपये भेजे, जो विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया सबसे बड़ा तोहफा बन गया है। इस वर्ष स्टालिन सरकार अब तक हर लाभार्थी के खाते में 9,000 रुपये भेज चुकी है। इनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 6.21 करोड़ है। इनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 3.15 करोड़ है, जो पुरुषों से कुछ अधिक है। स्टालिन सरकार द्वारा ‘कलैगनार मगलिर उरिमे थोयगई योजना’ के तहत 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में नगद ट्रांसफर का सीधा मतलब है कि राज्य की आधी से कम महिला मतदाताओं को ही इस योजना का लाभ मिला है। दरअसल, उन्हीं महिलाओं को इस योजना का सुपात्र माना गया है, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, जिनके घर की बिजली की मासिक खपत 300 हकाई से कम है, जिनके परिवार के पास सिंचित पांच एकड़ और अरिंसिचत 10 एकड़ से कम जमीन है। यह योजना परिवार की मुखिया, सभी ट्रांसजेंडर, अविवाहित

महिलाओं व विधवाओं पर लागू होती है। ऐसे में, क्या यह माना जाए कि जो महिलाएं इस योजना से लाभान्वित नहीं हुईं, वे द्रमुक को वोट नहीं देंगी? पार्टी को लगता है, ऐसा होने की आशंका नहीं है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि द्रमुक समर्थक किसी भी हाल में पार्टी का ही समर्थन करेंगे। उसका मानना है कि यह योजना उन लोगों को आकर्षित करेगी, जो अभी ऊहापोह में हैं। चुनाव से पहले ‘फ्रीबीज’ को चाहे जो भी नाम दिया जाए, अब यह सभी राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने भी कभी इसे ‘रेवड़ी’ कहा था, लेकिन अब वह भी इसकी उपयोगिता गिनाते हैं। निश्चित रूप से शासन और राज्य के बजट पर इस सबका असर पड़ता है, लेकिन राजनेताओं को अब इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनका मुख्य मकसद चुनाव जीतना बन गया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

एआई की दौड़ में कोई देश पीछे छूट गया, तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नई दिल्ली के एआई शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं की भागीदारी इसकी तरसदी कर रही है।



वाला है। इस बार के सम्मेलन की थीम है- ‘पीपुल, प्लेनेट और प्रोग्रेस’। संभवतः यह प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप ही है, जो एआई को इस कदर व्यापक बनाने की बात कहते रहे हैं कि समाज के हाशिये पर खड़ा व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो सके।

एआई सम्मेलन के जरिये भारत को एआई में ‘वैश्विक प्रतिभा’ के रूप में पेश किया जा रहा है। यह बताने की कोशिश हो रही है कि हमारा देश एआई के हर पहलू को स्वीकार करता है। सच भी यही है। अभी कुछ ही देश हैं, जो एआई में अग्रणी हैं। हमसे उन्नत एआई सिर्फ अमेरिका और चीन के पास है। कुछ यूरोपीय देश, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन आदि भी इसमें अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए, वैश्विक कूटनीतिक मंच इन्हीं देशों के आसपास सजने लगा है। तमाम सरकारें यह समझने लगी हैं कि आने वाला समय एआई या नई तकनीक का है, इसीलिए वैश्विक नेतृत्व के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए वे उन मुकों के साथ रिश्ते जोड़ने लगी हैं, जो नई तकनीक के धनी हैं।



एस श्रीनिवासन | विरिध प्रकाश

महिलाओं को सरकार से मुफ्त उपहार पाने की बहुत पुरानी आदत है। वे मानती हैं कि यह उनका जन्म अधिकार है, जिसे छीना नहीं जा सकता। तमिलनाडु में इस समय कुल मतदाताओं की संख्या 6.21 करोड़ है। इनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 3.15 करोड़ है, जो पुरुषों से कुछ अधिक है। स्टालिन सरकार द्वारा ‘कलैगनार मगलिर उरिमे थोयगई योजना’ के तहत 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में नगद ट्रांसफर का सीधा मतलब है कि राज्य की आधी से कम महिला मतदाताओं को ही इस योजना का लाभ मिला है। दरअसल, उन्हीं महिलाओं को इस योजना का सुपात्र माना गया है, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, जिनके घर की बिजली की मासिक खपत 300 हकाई से कम है, जिनके परिवार के पास सिंचित पांच एकड़ और अरिंसिचत 10 एकड़ से कम जमीन है। यह योजना परिवार की मुखिया, सभी ट्रांसजेंडर, अविवाहित

महिलाओं व विधवाओं पर लागू होती है। ऐसे में, क्या यह माना जाए कि जो महिलाएं इस योजना से लाभान्वित नहीं हुईं, वे द्रमुक को वोट नहीं देंगी? पार्टी को लगता है, ऐसा होने की आशंका नहीं है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि द्रमुक समर्थक किसी भी हाल में पार्टी का ही समर्थन करेंगे। उसका मानना है कि यह योजना उन लोगों को आकर्षित करेगी, जो अभी ऊहापोह में हैं।

चुनाव से पहले ‘फ्रीबीज’ को चाहे जो भी नाम दिया जाए, अब यह सभी राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने भी कभी इसे ‘रेवड़ी’ कहा था, लेकिन अब वह भी इसकी उपयोगिता गिनाते हैं। निश्चित रूप से शासन और राज्य के बजट पर इस सबका असर पड़ता है, लेकिन राजनेताओं को अब इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनका मुख्य मकसद चुनाव जीतना बन गया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण बदलाव कैसे हो

जब हम चर्चा करते हैं कि परिवर्तन कैसे लाया जाए, तो उस परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामान्यतः सतही बदलाव से होता है। दृढ़ निश्चय, निष्कर्ष, विश्वास, नियंत्रण और झिझक के जरिये हम उस सतही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसे चाहते हैं, जिसके लिए हम लालायित हैं। हम यह उम्मीद लगाते हैं कि उस तक पहुंचने में अचेतन मन, हमारे मन के गहरे स्तर तक हमारी सहायता करेगी। हमें लगता है कि यह आवश्यक है कि हम उन गहरे स्तरों को अनावृत करें, परंतु सतही स्तरों और तथाकथित गहरे स्तरों के बीच एक शाश्वत द्वंद्व है। मनोवैज्ञानिक इससे भली-भांति परिचित हैं।

क्या यह परिवर्तन लाएगा? क्या यह हमारे दैनिक जीवन का सर्वाधिक मूलभूत और महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि कैसे अपने आप में एक आमूल परिवर्तन लाया जाए? क्या सतही स्तर पर कुछ बदलाव वह परिवर्तन ला सकेगा? क्या चेतना के ‘मैं’ के विभिन्न स्तरों को समझना; अतीत अर्थात् बचपन से आज तक के विभिन्न व्यक्तिगत अनुभवों को अनावृत करना; अपने माता-पिता, पूर्वजों व प्रजाति के सामूहिक अनुभवों का स्वयं में निरीक्षण करना; उस समाज विशेष को संस्कारबद्धता का अनुसंधान करना, जिसमें हम रहते हैं, क्या यह सब विश्लेषण ऐसा परिवर्तन ला पाएगा, जो छिटपुट सामंजस्य बिडाना भर न हो?

मैं यह महसूस करता हूं और निस्संदेह आपको भी यह महसूस होता होगा कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। एक ऐसा परिवर्तन, जो प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, जो परिवेश की मांगों के दबाव और तनाव का परिणाम नहीं है। ऐसा परिवर्तन कैसे लाया जाए? मेरी चेतना मानव जाति के अनुभव का योग तो है ही, उसमें

वर्तमान से मेरा अपना निराला रिश्ता भी जुड़ा है; क्या वह चेतना परिवर्तन ला सकती है? क्या अपनी चेतना व गतिविधियों का मेरा अध्ययन मेरे मन को यूं स्थिर कर सकता है, ताकि वह बिना निंदा के निरीक्षण कर सके? क्या जो मैं हूं और मुझे जैसा होना चाहिए, इनके बीच द्वंद्व नहीं है? क्या द्वंद्व बुनियादी बदलाव ला सकता है? जो मैं हूं और जो होना चाहता हूं, उनके बीच अनवरत एक द्वंद्व चल रहा है। परिवर्तन अनिवार्य है, पर क्या इस

उत्पादों या सेवाओं में एआई का इस्तेमाल किया। सुबह है कि एआई का पूरा ‘स्टैक’ यहां बनाया गया है, ताकि हर पहलू में निवेश हो, शोध हो। ‘इंडियाएआई मिशन’ चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

इस सम्मेलन से भारत खुद को उभरती एआई ताकत के रूप में पेश करने में सफल हुआ है। फिर, इससे उद्योग, शिक्षा, कृषि जैसे तमाम क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

इस सम्मेलन से भारत खुद को उभरती एआई ताकत के रूप में पेश करने में सफल हुआ है। फिर, इससे उद्योग, शिक्षा, कृषि जैसे तमाम क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

इस सम्मेलन से भारत खुद को उभरती एआई ताकत के रूप में पेश करने में सफल हुआ है। फिर, इससे उद्योग, शिक्षा, कृषि जैसे तमाम क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

इस सम्मेलन से भारत खुद को उभरती एआई ताकत के रूप में पेश करने में सफल हुआ है। फिर, इससे उद्योग, शिक्षा, कृषि जैसे तमाम क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

इस सम्मेलन से भारत खुद को उभरती एआई ताकत के रूप में पेश करने में सफल हुआ है। फिर, इससे उद्योग, शिक्षा, कृषि जैसे तमाम क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

इस सम्मेलन से भारत खुद को उभरती एआई ताकत के रूप में पेश करने में सफल हुआ है। फिर, इससे उद्योग, शिक्षा, कृषि जैसे तमाम क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

इस सम्मेलन से भारत खुद को उभरती एआई ताकत के रूप में पेश करने में सफल हुआ है। फिर, इससे उद्योग, शिक्षा, कृषि जैसे तमाम क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

इस सम्मेलन से भारत खुद को उभरती एआई ताकत के रूप में पेश करने में सफल हुआ है। फिर, इससे उद्योग, शिक्षा, कृषि जैसे तमाम क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

इस सम्मेलन से भारत खुद को उभरती एआई ताकत के रूप में पेश करने में सफल हुआ है। फिर, इससे उद्योग, शिक्षा, कृषि जैसे तमाम क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

इस सम्मेलन से भारत खुद को उभरती एआई ताकत के रूप में पेश करने में सफल हुआ है। फिर, इससे उद्योग, शिक्षा, कृषि जैसे तमाम क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

इस सम्मेलन से भारत खुद को उभरती एआई ताकत के रूप में पेश करने में सफल हुआ है। फिर, इससे उद्योग, शिक्षा, कृषि जैसे तमाम क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय चल ही रहा है। चूंकि भारत की विदेश नीति का आयाम व्यापक है, इसलिए एआई में जो उपलब्धि नई दिल्ली के खाते में आएगी, वह निःस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे कोरोना के समय हमने टीके बांटे थे। एआई का लाभ इस तरह साझा करने से कूटनीतिक मंचों पर भारत का कद और ऊंचा उठ सकता है।

ये गाड़ियां समस्याएं भी पैदा कर रही

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शान में कसौदे खूब पड़े जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले यह भी जान लें कि ये गाड़ियां जो का जंगल भी बन जाती हैं। इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूं। मैंने एक नामी कंपनी की स्कूटी खरीदी। हालांकि, सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मुझे दी गई थी, फिर भी, उसकी कीमत पेट्रोल वाली स्कूटी से काफी ज्यादा थी। खैर, वह स्कूटी जब घर आई, तो मैं काफी खुश था। उसे चलाने भी लगा। मगर करीब छह महीने हुए थे कि उसमें कुछ दिक्कतें आने लगीं। मैं उसे लेकर सर्विस सेंटर गया, जहां मुझे बताया गया कि इसके पूरे आसानी से नहीं मिलते, इसलिए कुछ दिनों के बाद आकर ठीक कराना उचित होगा। कुछ दिनों के बाद मेरी उस समस्या का निराकरण हो भी गया, लेकिन करीब ढेढ़ साल होते-होते उस स्कूटी की बैटरी जवाब देने लगी। असल समस्या तभी आई। जब मैं बैटरी बदलवाने के लिए

सर्विस सेंटर गया, तो उसकी कीमत इतनी थी कि उससे सस्ती मुझे पेट्रोल वाली स्कूटी लगी। आखिरकार मैंने उस स्कूटी को कबाड़ के हवाले कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कल-पुर्जे आसानी से नहीं मिलते, फिर उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, बैटरी भी एक बड़ी समस्या है। यहां मैं उसके निपटान की चर्चा नहीं कर रहा हूं। फिर, इसका चार्जिंग प्वाइंट खोजना भी किसी बड़ी जंग जीतने से कम नहीं है। भले ही दिल्ली-पनसी आर में कई चार्जिंग प्वाइंट दिखते हैं, लेकिन चार्ज करने में लगने वाले समय को देखते हुए उन प्वाइंट पर लंबे समय तक खड़ा रहना भला किसे पसंद आएगा? दिक्कत यह भी है कि अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर आर लंबी यात्रा पर नहीं निकल सकते। पेट्रोल-डीजल के पंप तो आपको आसानी से दिख जाएंगे,

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

पर्यावरण के मित्र होते इलेक्ट्रिक वाहन

अभी-अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘पीएम 2-बस सेवा योजना’ के तहत चंडीगढ़ के लिए लगभग 25 इलेक्ट्रिक बसों की वरचुअल तरीके से शुरुआत की। इससे पहले, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी पहल हो चुकी है, जहां की सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हिमाचल रोडवेज के लिए सिर्फ नई इलेक्ट्रिक बसें और अन्य सरकारी वाहन ही खरीदने का मन बनाया है। हिमाचल सरकार अपने सूबे में डीजल और पेट्रोल का प्रयोग भी कम करेगी। यह एक अच्छी पहल है, जिसका न सिर्फ स्वागत किया जाना चाहिए, बल्कि इसकी सफलता की दिली कामना भी करनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि अपने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। सड़कों पर अब ज्यादा संख्या में ईवी दिखने लगी हैं। ये गाड़ियां पेट्रोल या डीजल पर नहीं चलतीं, बल्कि बैटरी से

चलती हैं। इससे वायु प्रदूषण को कम करने में निश्चय ही मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ये गाड़ियां ध्वनि प्रदूषण को भी खत्म करने में कारगर मानी जाती हैं, क्योंकि इन गाड़ियों से आवाज बेहद ही कम निकलती है, नाममात्र का। इस कारण ध्वनि प्रदूषण पर भी इसका खूब असर पड़ेगा। ऐसे में, जरूरी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की और अधिक सुलभ बनाने के प्रयास किए जाएं। लोगों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि जरूरी हो, तो ऐसी गाड़ियों पर सब्सिडी भी बढ़ाई जाए, ताकि सड़कों पर सिर्फ यही वाहन दिखें। वास्तव में देखा जाए, तो आने वाले समय में सौर ऊर्जा से भी वाहनों को चलते हम देख सकते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का विकल्प हमें ढूंढना ही होगा। पृथ्वी को स्वच्छ बनाने के लिए पर्यावरण-हितैषी गाड़ियां आवश्यक हैं।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कई फायदे हैं। एक तो यह कम धुआं छोड़ती हैं और फिर शोर भी नहीं करतीं। इतना ही नहीं, इनका मेंटनेंस यानी रख-रखाव भी तुलनात्मक रूप से आसान होता है। पेट्रोल-डीजल की गाड़ियां जहां अधिक खर्चीली होती हैं, वहीं ईवी में जेब कम दली होती है। फिर, पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में बढ़ी हैं, उस कारण भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी अधिक अच्छी जान पड़ती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर यही हुआ है कि लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। इन सबको देखते हुए हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही अपनीनी चाहिए। वैसे भी, भारत में प्रदूषण की जो स्थिति है, हवा जितनी खराब हो गई है, उसे देखते हुए हमें स्वच्छ ईंधन से चलने वाली गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ानी चाहिए।

सुभामा, टिप्पणीकार



अनुलोम-विलोम इलेक्ट्रिक गाड़ियां



सुभामा, टिप्पणीकार



शुद्ध मन से ही सफल होगी साधना

साधना के लिए मन का शुद्ध और कामनारहित होना जरूरी है। जब हम किसी इच्छा के अधीन होकर किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, तो भले ही वह पूरा हो जाए, लेकिन उससे हमें मन की शांति नहीं मिलती। मन की शांति के लिए जरूरी है कि हम निष्काम होकर साधना करें। ऐसा करने पर मिलनेवाली सफलता स्थाई होती है।

अध्यात्म



रामकृष्ण परमहंस

यदि किसी में शुद्ध सत्व गुण का उदय हो, तो वह सदा केवल ईश्वर चिंतन ही करता है। उसे और कुछ भी नहीं भाता। किसी-किसी को प्रारब्धवश जन्म से ही शुद्ध सत्व गुण प्राप्त होता है। रजोमिश्रित सत्व गुण के रहने पर धीरे-धीरे मन नाना दिशाओं में जाने लगता है। इससे 'मैं जगत का उपकार करूंगा', इस प्रकार का अभिमान आ जाता है। यदि कोई कामना शून्य होकर परोपकार के लिए कर्म करे, तो उसमें दोष नहीं। इसे निष्काम कर्म कहते हैं।

कुछ लोगों में ही शुद्ध सत्व गुण देखने को मिलता है। निष्काम कर्म करते-करते रजोमिश्रित सत्व गुण धीरे-धीरे शुद्ध सत्व गुण में परिणत होता है।

मन की तल्लीनता जरूरी

ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने पर कर्म त्याग अपने आप हो जाता है। ईश्वर जिन लोगों से कर्म करवा रहे हैं, उन्हें करने दो। संध्या गायत्री में लीन होती है, गायत्री प्रणव में लीन होती है, प्रणव समाधि में लीन होता है। इस प्रकार संध्यादि कर्म समाधि में लीन होता है।

जब तक सचिदानंद में मन लीन न हो जाए, तब तक उन्हें पुकारना और संसार के काम-काज करना, दोनों बातें चल सकती हैं। उनमें मन तल्लीन हो जाने पर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे, मानो कोई कीर्तन गा रहा है- 'निताई आमार माता हाथी'। पहले जब वह गाना शुरू करता है, तब गीत के शब्द, राग, ताल, मान, लय, सभी बातों पर ध्यान रखते हुए सही ढंग से गाता है। फिर जब गीत के भाव में उसका मन थोड़ा

मन होता है, तब वह सिर्फ 'माता हाथी, माता हाथी' ही कहता है। फिर जब उस भाव में मन और भी तल्लीन हुआ, तब वह सिर्फ 'हाथी, हाथी' ही कहता है। अंत में जब मन पूरी तरह तल्लीन हो जाता है, तब वह 'हा' कहकर ही भावमग्न होकर चुप हो जाता है। शुरू-शुरू में कर्म की बड़ी चहल-पहल रहती है, परंतु तुम ईश्वर की ओर जितना ही अग्रसर होओ, उतना ही तुम्हारा कर्म कम होता जाएगा।

दो प्रकार के साधक

साधक दो प्रकार के होते हैं- एक प्रकार के साधक का स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह होता है, दूसरे प्रकार के साधक का स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है; पर बिल्ली का बच्चा स्वयं मां को नहीं पकड़ता। मां उसे जहां कहीं छोड़ दे, वहीं पड़ा रहकर वह 'म्याऊं-म्याऊं' करता रहता है। बंदर का बच्चा खुद अपनी मां को पकड़े रहता है, इसलिए अगर कभी उसका हाथ छूट जाए, तो वह गिर पड़ता है और उसे चोट पहुंचती है।

बिल्ली के बच्चे को यह भय नहीं है, क्योंकि उसे उसकी मां स्वयं पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसी प्रकार ज्ञानयोगी या कर्मयोगी साधक बंदर के बच्चे की तरह स्वयं के प्रयत्न से मुक्ति लाभ करने का प्रयास करता है, परंतु भक्त साधक ईश्वर को ही एकमात्र कर्ता जानते हुए बिल्ली के बच्चे की तरह, उन्हीं के चरणों में निभर होकर निश्चिंत होकर पड़ा रहता है।

ज्ञान और भक्ति में भेद

ज्ञानी कहता है, 'सोऽहम्! मैं ही वह शुद्ध आत्मा हूँ, परंतु भक्त कहता है, 'अहा, यह सब उनकी महिमा है!' शिव के अंश से जन्म होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। उसका मन सदा 'ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या' इसी बोध की ओर जाता है। विष्णु के अंश से जन्म हो, तो प्रेम भक्ति होती है। वह प्रेम भक्ति कभी नहीं जाती। बहुत ज्ञान-विचार करने के बाद यदि किसी समय यह प्रेम भक्ति कुछ कम भी हो जाए, तो फिर एक समय बाद यह वदु वंश का ध्वंस करनेवाले मूसल की तरह देखते-देखते

बढ़ भी जाती है। प्रेम भक्ति में 'मैं' तिरोहित हो जाता है। स्वयं को तिरोहित कर उस अदृश्य शक्ति में लीन हो जाना ही प्रेम भक्ति है।

मिते मन के संशय

ज्ञानी के भीतर मानो एक ही दिशा में गंगा बहती है। उसके लिए सब कुछ स्वयंनवत है। वह सदा स्व-स्वरूप में अवस्थित रहता है। भक्त के भीतर गंगा एक दिशा में नहीं बहती, उसमें ज्वार-भाटा आता रहता है। वह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता-गाता है। भगवान के साथ विलास करना चाहता है। वह उस आनंद सागर में तैरता-डूबता रहता है।

पुराणों के मतानुसार भक्त एक है और भगवान एक। 'मैं' एक और 'तुम' एक। देह मानो एक घट है, इस देहरूपी घट में मन-बुद्धि-अहंकाररूपी जल रखा है। ब्रह्म मानो सूर्य स्वरूप है। वह इस जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। यही प्रकाश मनुष्य के अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाता है और एक नई राह दिखाता है। एक बार राह मिल जाने पर मनुष्य के मन के सभी संशय मित जाते हैं।



रामकृष्ण परमहंस जयंती (19 फरवरी)

आस्था-अनास्था

डॉ. एम. आर. राजेश्वरी

रावण और कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का रहस्य

रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में कौन थे?

-सोमित्र, वाराणसी

सनक, सनंदन, सनातन तथा सनतकुमार भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ लोक गए। वहां उनके द्वारपाल जय-विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और उनका अपमान किया। इससे क्रुद्ध होकर चारों मुनि कुमारों ने जय-विजय को पृथ्वी लोक पर असुर के रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया।



भगवान विष्णु के भक्त बनकर जीने के बाद शाप मुक्त होना चाहेंगे या फिर तीन योनियों में भगवान के शत्रु बनकर जीने के बाद मुक्त होना चाहेंगे।

दोनों ने कहा, 'सौ जन्म भगवान से दूर रहने की बजाय हम तीन जन्मों का ही चयन करेंगे।'

जय और विजय ने असुरों के रूप में पहली योनि में हिरण्यक्ष तथा हिरण्यकशिपु, दूसरी योनि में कुंभकर्ण एवं रावण और तीसरी योनि में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने नरसिंह, राम तथा कृष्ण का अवतार धारण कर उनका संहार कर शाप से मुक्ति दिलाई।

(साभार: 'हिंदू पुराणों की नीति कथाएँ', तिरुमल तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति)

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?
पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अकसर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन-मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें:
धर्मक्षेत्र, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश)

दिलों को जोड़ता माहे रमजान

रमजान (19 फरवरी से)

रोजे अर्थात रमजान इस्लाम के पांच फर्जों में से एक फर्ज। इस्लाम का निर्माण जिन पांच स्तंभों पर किया गया है, रमजान उन स्तंभों में से एक स्तंभ है।

रमजान का नाम आते ही सफेद टोपी पहने भूखे-प्यासे और समूह में इबादत करते लोग अक्सर जेहन में आ जाते हैं। जो हां! यह सच भी है, लेकिन पूरा सच नहीं है। पूरा सच इसलिए नहीं कि रमजान केवल भूखे-प्यासे रह कर दिन गुजारने और शाम को जम कर खाने का नाम नहीं है।

रमजान के महीने में भूखे-प्यासे रहकर इबादत करने के अतिरिक्त भी अन्य बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। यदि साफ कहे, तो सिर्फ पेट नहीं जुवाना का भी रोजा रखना होता है। खाने-पीने की चीजों के साथ कटु वचन, अभद्र भाषा, अनुचित बातों का भी त्याग करना होता है, तभी सच्चे अर्थ में रोजेदार कहलाने का सवाब मिलता है। रमजान को माहे मुबारक भी कहा जाता है, क्योंकि

इसी माह में कुरआन नाजिल हुआ। कुरआन इस्लाम का आधार ग्रंथ है।

रमजान के साथ जुड़े हैं, कुछ धार्मिक क्रिया-कलाप तथा आर्थिक त्याग भी। जैसे फितरा और जकात। फितरा और जकात अपनी आमदनी में से निकाले गए एक निश्चित धन के हिस्से को कहा जाता है, जिस पर केवल गरीबों और जरूरतमंदों का हक होता है। जो कि इस माह के मध्य, ईद की नमाज से पहले अदा करना जरूरी होता है। यह बात हर मुस्लिम को मालूम होती है।

इस्लाम प्रत्येक मुस्लिम को कमाई में से गरीब व मजदूरों का हिस्सा तय करता है, जिसे अदा करना फर्ज किया है। जैसे रमजान फर्ज है, उसी प्रकार जकात भी फर्ज है।

यहां इस्लाम की एक और खूबसूरती परिलक्षित होती है। इस्लाम कहता है कि पहले अपने पड़ोस में देखो, फिर मुहल्ले में उसके बाद अपने रिश्तेदारों में दूढ़कर उनकी मदद करो। रमजान इबादत का महीना है, इसलिए इस माह में इबादतें बढ़ जाती हैं। पांच वक्त की नमाज के साथ-साथ तरावियां भी जमात (सामूहिक) के साथ पढ़ी जाती हैं, जिनका



रमजान के महीने में विशेष महत्व है।

रमजान का धार्मिक महत्व तो है ही, मगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें, तो सामाजिक महत्व भी है। रमजान दिलों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माहे रमजान खुद भूखे-प्यासे रहकर अन्य लोगों की भूख-प्यास को समझने तथा समझाने में आसानी पैदा करता है। एक भूखे-प्यासे इंसान से बेहतर और कौन दूसरे भूखे-प्यासे इंसान को समझ

सकता है। 'भूखे की गत भूखा जाने, प्यासे की प्यासा।' जो दूसरे की तकलीफ को समझता है, वही जरूरतमंद की मदद भी करता है। यह सहज और स्वाभाविक-सी बात है। 'अति सुधो स्नेह कौ मारग है।' कहने का अर्थ यही है कि रमजान भूखे-प्यासे रहकर इबादत करने का ही नाम नहीं है, वरन एक-दूसरे की मदद को तैयार रहना भी माहे रमजान में शामिल है।

रमजान का स्पष्ट संदेश है, स्वयं को समाज के लिए प्रस्तुत करना। विश्व के तमाम जरूरतमंदों से कहना कि तकलीफ में आप अकेले नहीं हैं; हम आपके साथ हैं, आपकी सहायता के लिए।

इस्लाम की खूबसूरती इस प्रकार भी देखी जा सकती है कि इस्लाम कहता है कि जकात-खैरत का पैसा जरूरी नहीं कि किसी मुस्लिम को ही दिया जाए; आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। विशेष वरह किसी भी मजहब को मानने वाला हो। यहां यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि रमजान 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना से ओतप्रोत है।

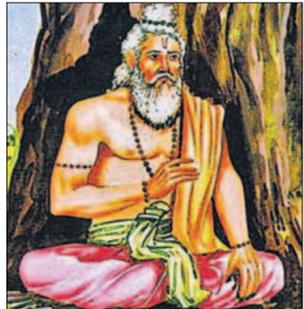
अंत में यही कि रोजे रखिए, इबादत करिए और फिर ईद की खुशियां मनाइए, मगर अपने आस-पास ध्यान रखिए कि कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है। आप सभी को माहे रमजान की बरकतें मुबारक।

मुख्तार अहमद

ब्रह्मा के अवतार ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य

याज्ञवल्क्य जयंती

पौराणिक कथाओं के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषि को भगवान ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ में पत्नी सावित्री की जगह गायत्री को स्थान देने पर सावित्री ने उन्हें मानव रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण ही उनका जन्म चारण ऋषि के यहां याज्ञवल्क्य के रूप में हुआ। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार ये देवरात के पुत्र थे। इनका जन्म फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी (22 फरवरी) को हुआ था। परम विदुषी 'मैत्रेयी' याज्ञवल्क्य की पत्नी थीं।



करते हुए याज्ञवल्क्य ने उन्हें सारा ज्ञान लौटा दिया। उस ज्ञान को गुरु के अन्य शिष्यों ने तीतर पक्षी के रूप में ग्रहण कर लिया। शिष्यों द्वारा तीतर पक्षी के रूप में ग्रहण किए जाने के कारण यज्ञवेद की यह शाखा 'तैत्तिरीय संहिता' के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना के पश्चात ज्ञान से रहित हो जाने के कारण याज्ञवल्क्य ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए सूर्य की उपासना की। सूर्य ने अश्व रूप धारण कर उन्हें 'यजुर्वेद' के उन मंत्रों की दीक्षा दी, जिसका ज्ञान

अभी तक किसी को नहीं था। अश्व रूप में सूर्य से प्राप्त होने के कारण शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा 'वाजसनेयि माध्यन्दिन संहिता' है। इसमें चालीस अध्याय हैं, जिनमें दर्श-पूर्णमास, सोमयज्ञ, अश्वमेध और राजसूय जैसे महत्वपूर्ण वैदिक यज्ञों के मंत्र संकलित हैं। अंतिम अध्याय प्रसिद्ध 'इंशावार्योपनिषद्' है। दूसरी 'काण्व संहिता' के नाम से जानी गई। इसमें वैदिक यज्ञों, अनुष्ठानों और कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का व्यवस्थित संकलन है। यह चालीस अध्यायों में विभाजित है। शुक्ल यजुर्वेद-संहिता के मुख्य मंत्रद्रष्टा महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। इस संहिता में चालीस अध्याय हैं। सभी पूजा आदि धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों में इसके मंत्र प्रयोग होते हैं। 'रुद्राष्टाध्यायी' भी इसी संहिता में है। इतना दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ 'शतपथ ब्राह्मण' है। 'बृहदारण्यक' उपनिषद् इसी का भाग है। यह उपनिषद् राजा जनक के दरबार में 'याज्ञवल्क्य' और 'गार्गी' के बीच हुए संवाद पर आधारित है। ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य का यह कथन- 'जिस क्षण मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी संन्यास लिया जा सकता है।' आज भी संन्यास का मूल आधार माना जाता है।

अश्वनी कुमार

सप्ताह के व्रत-त्योहार

17 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक

- 17 फरवरी (मंगलवार):** फाल्गुन कृष्ण अमावस्या तिथि सायं 05.31 मिनट तक। फाल्गुन अमावस। भौमवती अमावस। पंचक प्रारंभ प्रातः 09.06 मिनट से।
- 18 फरवरी (बुधवार):** फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा तिथि सायं 04.58 मिनट तक। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारंभ। चंद्रदर्शन। पंचक।
- 19 फरवरी (गुरुवार):** फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि अपराह्न 03.59 मिनट तक। श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती। फूलारा दूज (मथुरा-वृंदावन)। रमजान (मु.) मास प्रारंभ। पंचक।
- 20 फरवरी (शुक्रवार):** फाल्गुन शुक्ल तृतीया तिथि दोपहर 02.39 मिनट तक। भद्रा रात्रि 01.50 मिनट से। शक फाल्गुन प्रारंभ। गंडमूल रात्रि 08.08 मिनट से। पंचक।
- 21 फरवरी (शनिवार):** फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि दोपहर 01.01 मिनट तक। भद्रा दोपहर 01.01 मिनट तक। पंचक समाप्त सायं 07.07 मिनट।
- 22 फरवरी (रविवार):** फाल्गुन शुक्ल पंचमी तिथि प्रातः 11.10 मिनट तक। याज्ञवल्क्य जयंती। गंडमूल सायं 05.55 मिनट तक।
- 23 फरवरी (सोमवार):** फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि प्रातः 09.10 मिनट तक। -पं. ऋषुकांत गोस्वामी

रोजनामचा

वर्ग पहली: 8243

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | | | | |
| 7 | | 8 | | |
| 9 | 10 | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | | |
| 18 | | 19 | 20 | |
| 21 | | | | |

- बाएं से दाएं**
- समाधान कर देना; सुलझा देना; हल निकाल देना (2,2,2)
 - तमाशाबीन; देखने वाला; दर्शन करने वाला (3)
 - असावधान; चिंताहीन; जिसे परवाह न हो (5)
 - विविध; अनेक; मातामह (2)
 - जनक; जन्मदाता; तात (2)
 - प्रियतमा; प्रेयसी; महिला; स्त्री (3)
 - आत्मीय; चहेता; प्रिय; 'आम' का विपर्याय; प्रधान; मुख्य; विशेष (2)
 - आधिपति; नरेंद्र; गुप्त; महीष; प्रशासक; धनी; प्रिय; स्वामी (2)
 - बल खाता हुआ; लहराता हुआ; जोशीला (5)
 - परिणाम; फल (3)
 - असफल करना; विफल करना (3,3)

ऊपर से नीचे

- झपटना; तेजी से आगे बढ़ना (4)
- रसदार; स्वादित; बांका; छबीला (3)
- मना करना; रोकेना; निषिद्ध करना (1,3)
- अचेत हो जाना; शिथिल हो जाना; होशों हवास खो बैठना (5,1,2)
- दिल पिघल जाना; हृदय द्रवित हो जाना (3,3,2)
- किशोरी; तरुणी; नौका (2)
- नक्षत्र; आंख को पुतली (2)
- अगुआ; नेता; मुखिया; सरदार (4)
- सजीव; प्राणी (4)
- करुणा; कृपा; दया; अनुग्रह (3)

वर्ग पहली: 8242

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

सुडोकू: 8225 * मध्यम

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 9 | 5 | | |
| | 8 | | | | | 4 | |
| 9 | 4 | | 8 | 2 | 1 | | |
| | | 9 | | | | | 2 |
| 6 | 1 | | | | 8 | 9 | |
| 7 | | | | | 3 | | |
| | | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| | 9 | | | | | | 6 |
| | | 5 | | 6 | 8 | | |

खेलने का तरीका: दिमागी खेल और नंबरों की पहली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएँ। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू: 8224

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 8 |
| 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 |
| 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 |
| 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 |



पं. राघवेंद्र मूर्थी ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें



व्रत और त्योहार | पंचांग

17 फरवरी, मंगलवार, शक संवत्: 28 माघ (सौर) 1947, पंचाब पंचांग: 06 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 28 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण अमावस्या तिथि सायं 05.31 मिनट तक। शताभिषा नक्षत्र, परिध योग रात्रि 12.29 मिनट तक पश्चात शिव योग, नाग करण। चंद्रमा मकर राशि में प्रातः 09.06 मिनट तक उपरांत कुंभ राशि में। सूर्य उत्तरायण। शिभिर ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। फाल्गुन अमावस। भौमवती अमावस। पंचक प्रारंभ प्रातः 09.06 मिनट से।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि कुछ वास्तु दोष, जो हम दूर नहीं कर सकते हैं, उनके क्या उपाय हैं? -स्वस्तिका, गाजियाबाद

- यदि ईशान कोण कटा हुआ हो, तो इस दिशा में भूमिगत जल के स्रोत बढ़ाएं।
- कुछ फाउंटन इत्यादि भी इस दिशा में लगाएं।
- इस दिशा में छोटे पौधे लगाएं। इस दिशा में यदि संभव हो, तो लॉन भी बनाने की कोशिश करें।
- इस दिशा में ज्यादा-से-ज्यादा प्रकाश हो। यदि संभव हो, तो कटे भाग में बाउंड्री बढ़ाकर समकोण बनाएं। यहां पर एल्युमीनियम या जिंक के हेलिक्स लगाएं।



न्यायपालिका में एआइ

यह सर्वथा उचित है और समय की मांग के अनुरूप भी कि इंडिया एआइ इपैक्ट शिखर सम्मेलन के अवसर पर न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर भी एक सत्र का आयोजन किया गया। इसमें इस पर विचार किया गया कि मशीनी दक्षता किस प्रकार भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। चूंकि इस कार्यक्रम में विधिवेत्ताओं के साथ ला फर्मों के विधि विशेषज्ञों ने भी भाग लिया, इसलिए यह आशा की जाती है कि आने वाले समय में न्यायिक तंत्र में एआइ का उपयोग और बढ़ेगा एवं उससे आम लोगों को लाभ भी मिलेगा। जब जीवन के हर क्षेत्र में एआइ का उपयोग हो रहा है, तब फिर न्यायपालिका के क्षेत्र में भी ऐसा होना चाहिए। वैसे तो सीमित स्तर पर न्यायिक तंत्र में एआइ का उपयोग हो रहा है, लेकिन अभी इसका आकलन किया जाना शेष है कि उसके वांछित परिणाम मिल पा रहे हैं या नहीं? वर्तमान में ई-कोर्ट परियोजना के तहत न्यायिक तंत्र में एआइ आधारित कई तरह के टूल उपयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे मशीन लर्निंग टूल अदालतों फैसलों का अंशजो से क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करता है। इसके माध्यम से हजारों निर्णयों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। एक अन्य टूल फाइलों का विश्लेषण करने, प्रासंगिक कानूनों और उद्धरणों को खोजने में मदद करता है। इसी तरह कुछ उच्च न्यायालयों में ऐसे टूल प्रयोग हो रहे हैं, जो गवाहों के बयानों को सीधे डिजिटल टेक्स्ट में बदलने का काम करते हैं।

न्यायिक तंत्र में एआइ का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि लोगों को समय पर न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ें। निःसंदेह एआइ निर्णय देने का काम नहीं कर सकता और न ही उससे ऐसा कोई काम लिया जाना चाहिए। मानवीय विवेक का स्थान एआइ नहीं ले सकती, लेकिन उसका इतना सहयोग तो लिया ही जा सकता है, जिससे कागजी कार्रवाई का बोझ कम हो। अनुसंधान, विश्लेषण और डाटा संग्रह का काम भी एआइ के जरिये हो सकता है। इस सबके साथ ही यह भी समझा जाना चाहिए कि न्यायिक तंत्र में एआइ का इस्तेमाल तभी प्रभावी होगा, जब अपेक्षित न्यायिक सुधार भी किए जाएंगे। यह आवश्यक है कि तारीख पर तारीख के सिलसिले पर विराम लगे। इसी तरह जनहित याचिकाओं के नाम पर फलतु की याचिकाओं पर लगाम लगना भी जरूरी है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, लेकिन आवश्यक हो चुके बुनियादी न्यायिक सुधार आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है। करोड़ों लंबित मुकदमों केवल करोड़ों लोगों को हताश-निराश ही नहीं कर रहे, बल्कि देश की प्रगति में बाधक भी बन रहे हैं।

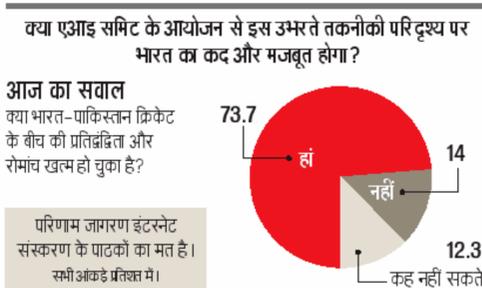
महत्वपूर्ण कदम

दिल्ली पुलिस को आतंकवाद व मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राजधानी में स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड मुख्यालय के निर्माण की शुरुआत किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सोमवार को स्पेशल सेल के इस इंटीग्रेटेड मुख्यालय का ई शिलान्यास किया। यह मुख्यालय 368 करोड़ की लागत से दक्षिणी दिल्ली की लोधी कालोनी में बनेगा। इस मुख्यालय में अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वार रूम, साइबर लैब व प्रशिक्षण हॉल समेत तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। इससे यह आतंकवाद व मादक पदार्थों की तस्करी से मुकाबले के लिए देश के किसी भी राज्य की पुलिस के मुकाबले अपनी तरह का तकनीकी रूप से सर्वाधिक उन्नत केंद्र बन जाएगा।

स्पेशल सेल का नया इंटीग्रेटेड मुख्यालय बनने से पुलिस सशक्त होगी, साथ ही दिल्ली और भी सुरक्षित होगी

राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण दिल्ली आतंकियों के निशाने पर हमेशा रहती है। ये सही है कि स्पेशल सेल की सतर्कता के कारण ही यहां विगत कुछ वर्षों से बड़ी आतंकी घटना नहीं हो पाई है, लेकिन लाल किला बम धमाके जैसी घटनाएं यहां आतंकियों की सक्रियता दर्शाती रहती हैं, जिनमें लोगों की जान भी जाती है। राजधानी होने के कारण यहां विदेशी राजनेताओं समेत तमाम प्रमुख लोगों का आना-जाना लगा रहता है। यह मुख्यालय बनने से पुलिस सशक्त होगी तो दिल्ली भी और सुरक्षित होगी।

कह के रहेंगे **माधव जोशी**



एआइ जगत को दिशा देने की कोशिश



हर्ष वी. पंत

एआइ शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी भ्रूणजनीति को गी नए सिरे से संतुलित करने में सक्षम हो सकता है

नई दिल्ली में आरंभ एआइ प्रभाव शिखर सम्मेलन कूटनीतिक मोर्चे पर ही एक मील का पत्थर नहीं, बल्कि सुनियोजित रणनीतिक पुनर्संरचना का प्रतीक भी है। यह शिखर सम्मेलन भारत की इस भावना को दर्शाता है कि वह इस उभरती हुई तकनीक से जुड़े विमर्श को प्रभावित कर उसे समावेशी एवं लोकतांत्रिक बनाना चाहता है। इस आयोजन के माध्यम से भारत एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से जुड़ी चर्चा को सुरक्षा एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की अमूर्त चिंताओं से इतर उसके प्रभाव की ओर मोड़ना चाहता है। जैसे कि कौन इससे लाभान्वित हो रहा है और कौन नहीं और कौन इस खेल के नियम निर्धारित कर रहा है?

इससे पहले एआइ संबंधी आयोजन विकसित देशों में हुए और पहली बार वैश्विक दक्षिण में ऐसा शिखर सम्मेलन हो रहा है। प्रतीकात्मक रूप से भी यह बड़ा परिवर्तन है। पूर्व के आयोजनों में चर्चा का केंद्र मुख्य रूप से एआइ माडल

के विकास और जोखिमों पर केंद्रित रहा। इस दृष्टि से भारत की मेजबानी में यह आयोजन अलग कहानी कहने जा रहा है। भारत एआइ परिचालन को एक तकनीकी मुद्दे से परे विकास संबंधी पहलू के रूप में पुनर्परिभाषित करने के प्रयास में लगा है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मानवता के लिए एआइ' वाले उस मंत्र को ही दर्शाता है कि किसी तकनीक का उद्देश्य निजी पूंजी को बढ़ाने के बजाय व्यापक सार्वजनिक हितों का होना चाहिए।

भारत का एजेंडा तीन मानक स्तंभों पर आधारित है। ये तीन स्तंभ हैं पोपल यानी लोग, प्लैनेट यानी पृथ्वी और प्रोग्रेस यानी प्रगति। इन तीन स्तंभों को व्यावहारिक दृष्टि से सात विषयगत 'चक्रों' में विभक्त किया गया है। ये सात चक्र हैं-कंप्यूटिंग और डाटा तक पहुंच का लोकारोपण, सामाजिक प्रभाव के लिए एआइ, सुरक्षित और विश्वसनीय एआइ, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में एआइ, कृषि और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं ग्लोबल साउथ के लिए एआइ। यह दृष्टिकोण एआइ को समावेशन और स्थायित्व के दायरे में एक रणनीतिक विकल्प के तौर पर रेखांकित करता है। इस क्रम में मिनी एआइ पर भी जोर दिया जा रहा है। मिनी एआइ से तात्पर्य ऐसे माडल से है, जो उपयोग में सुगम होने के साथ ही किफायती एवं बहुभाषी भी हों। खासतौर से कमजोर कनेक्टिविटी वाले परिदृश्य में भी प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। ऐसी दृष्टि के साथ भारत यह जताना चाहता है कि नवाचार अनिवार्य रूप से बड़ा पैमाने और अत्याधुनिक प्रणालियों तक ही सीमित नहीं रह सकता। इसके



नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी इंडिया एआइ इपैक्ट समिट ● आइएनएस

बजाय उसकी दृष्टि उपयोगिता को केंद्र में रखती है। इसमें पूर्वोन्माहित को सार्वजनिक स्वास्थ्य माडल, जलवायु के प्रति अनुकूल कृषि और डिजिटलीकृत सेवाओं का वितरण महत्वपूर्ण हैं। इससे एआइ केवल कारपोरेट कौशल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि राज्य की क्षमताओं को सुदृढ़ करने का एक उपकरण बन जाती है। इस तरह यह एक ओर विकास एआइ केवल कारपोरेट कौशल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि राज्य की क्षमताओं को सुदृढ़ करने का एक उपकरण बन जाती है। इस तरह यह एक ओर विकास एआइ केवल कारपोरेट कौशल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि राज्य की क्षमताओं को सुदृढ़ करने का एक उपकरण बन जाती है। इस तरह यह एक ओर विकास एआइ केवल कारपोरेट कौशल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि राज्य की क्षमताओं को सुदृढ़ करने का एक उपकरण बन जाती है।

यह कहें कि भारत में फुल स्टैक एआइ लॉडर बनने की भरपूर संभावनाएं हैं तो यह उसी धारणा को मजबूत करता है कि यह देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक व्यापक गठबंधन को नेतृत्व दे सकता है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों का इस सम्मेलन से जुड़ाव इसकी बहुपक्षीय दिशा को भी दर्शाता है।

समग्रता में देखा जाए तो भारत एआइ परिरुध्य पर स्वयं को पश्चिम के नवाचार केंद्रों और वैश्विक दक्षिण की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं, अमेरिकी नेतृत्व वाले उद्यमशील इकोसिस्टम और सरकारी नियंत्रण वाले चीन के व्यापकता से परिपूर्ण तंत्र के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित करने में लगा है। एआइ संचालन से जुड़ी एक राह भारत की व्यापक विदेश नीति के रूझान को भी दर्शाती है। अलग-थलग पड़े बिना रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना इस नीति के मूल में है। तकनीकी राष्ट्रवाद के इस दौर में ऐसा रुख-स्वैया न केवल विश्व के शक्ति केंद्रों से जुड़े रहने, बल्कि अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी

अवसर और चुनौतियों भरे समझौते

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित और अस्थिर व्यापारिक प्रवृत्तियों एवं टैरिफ के निरंतर बढ़ते दबावों के बीच भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमति बनना भारत की रक्षाकृत होती कूटनीतिक क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विपरीत परिस्थितियों में भी भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी व्यापार समझौता एकतरफा या अमेरिका-केंद्रित नहीं होगा, बल्कि पारस्परिकता, सम्मान और बराबरी के सिद्धांतों पर आधारित होगा। यह भारत के उस बदले हुए आत्मविश्वास का दर्शाता है, जिसके तहत भारत अब केवल रियायतें मांगने वाला देश नहीं रहा, बल्कि आर्थिक वृद्धि की निरंतर गति, राजनीतिक निरंतरता और डिजिटल क्रांति के बल पर एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अमेरिका के लिए भी यह तथ्य स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत की सहभागिता के बिना वैश्विक आर्थिक संतुलन और रणनीतिक लक्ष्यों को साधना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जाएगा। यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक भी है, जो शक्ति-संतुलन में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता को रेखांकित करता है।



ज. सुरजीत सिंह

व्यापार समझौतों की सफलता उनके व्यावहारिक एवं संतुलित क्रियान्वयन से ही निर्धारित होगी



अमेरिकी राजदूत गोर के साथ पीयूष गोयल ● एनआइ

श्रृंखला में बार-बार के व्यवधानों से अमेरिका की चीन पर अत्यधिक निर्भरता अब केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जोखिम बन चुकी है। ऐसे परिदृश्य में भारत का विशाल और युवा श्रमबल, सुदृढ़ लोकतांत्रिक संस्थाएं, निर्यात-आधारित आर्थिक व्यवस्था एवं तीव्र गति से विकसित हो रही तकनीकी क्षमताओं के कारण अमेरिका का झुकाव भारत की ओर बढ़ा है। रक्षा, डिजिटल सेवाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वच्छ ऊर्जा जैसे अग्रणी क्षेत्रों में सहयोग अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव का स्पष्ट संकेत है। जो स्वीकार्यता पहले परोक्ष और अनौपचारिक थी, वह अब अमेरिका की रणनीतिक और व्यापारिक नीति का घोषित अंग बन सकती है।

समग्र दृष्टि से देखा जाए तो भारत-अमेरिका व्यापार समझौता मात्र एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की परिवर्तित होती वैश्विक पहचान का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल भारत के साथ अमेरिका के आर्थिक हितों की भी पूर्ति करता है। हाल के वर्षों में चीन की आर्थिक नीतियों, भू-राजनीतिक आक्रामकता और आपूर्ति

रखता है। यदि यह समझौता दूरदर्शिता, संतुलन और सुदृढ़ धरेलू सुधारों के साथ लागू किया गया, तो यह भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपीय संघ से व्यापार समझौते भारतीय एमएसएमई को न केवल उत्पादन विस्तार, बल्कि गुणवत्ता, मानकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता के अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचने में सक्षम बना सकते हैं। इससे धरेलू उद्योगों की संरचना अधिक सुदृढ़ होगी, व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन को गति मिलेगी और क्षेत्रीय आर्थिक अस्तुतलनों को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। समकालीन वैश्विक व्यवस्था में व्यापार अब केवल आर्थिक लेनदेन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि भू-राजनीतिक प्रभाव, शक्ति-संतुलन और रणनीतिक हितों को साधने का एक प्रभावी उपकरण बन चुका है।

क्वाड, इंडो-पैसिफिक सहयोग और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते जैसी पहल अब पृथक प्रयास न होकर एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत संचालित हो रही हैं। यह आर्थिक कूटनीति का आधुनिक स्वरूप है, जहां व्यापारिक साझेदारियों रणनीतिक उद्देश्यों को मजबूती देती हैं और रणनीतिक सहयोग आर्थिक अवसरों के लिए द्वार खोलता है। यद्यपि व्यापार समझौते से उत्पन्न होने वाले अवसर व्यापक और दूरगामी हैं, किंतु चुनौतियां भी कम नहीं हैं। धरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप सक्षम बनाना, निर्यात सुधारों को गति देना, श्रम सुधारों को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाना तथा लाइसेंसिटेक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना अनिवार्य होगा। यदि इन आंतरिक सुधारों पर स्मृचित और समयबद्ध ध्यान नहीं दिया गया, तो अमेरिका से होने वाले और अन्य देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों से प्राप्त संभावनाएं सीमित प्रभाव तक ही सिमट सकती हैं। व्यापार समझौतों की वास्तविक सफलता उनके औपचारिक अनुमोदन में नहीं, बल्कि उनके प्रभावी, व्यावहारिक और संतुलित क्रियान्वयन में निहित होगी।

(लेखक अर्धशास्त्री हैं) response@jagran.com

संरक्षण के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए, ताकि वे रोजगार और देश की आर्थिक व्यवस्था में और अधिक योगदान दे सकें।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

घरेलू उद्यमों का विकास

'विकसित भारत का आधार बनने एमएसएमई' शीर्षक आलेख में ऋतु सारस्वत ने सही कहा है कि देश को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) की ओर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें लोकल चीजों को लेकर जोर देना चाहिए। अर्थात् हमें स्वदेशी उत्पादों के बारे में अधिक और खुलकर बात करनी चाहिए। सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है, लेकिन जब देश में स्वदेशी पर चर्चा के साथ ठोस काम भी होगा, तो यह लघु उद्योगों को संजीवनी देने का कार्य करेगा। खबर है कि चीन से आयात होने वाले छोटे-छोटे उत्पाद देश में ही तैयार करने में तैयारी चल रही है। अच्छा होगा कि इस कार्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की सरकार द्वारा सहायता ली जानी चाहिए। हमारा देश गांवों का देश है, इसलिए यह कला जा सकता है कि लघु उद्योगों का विस्तार गांवों में करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है और युवाओं के पलायन को रोकना जा सकता है। स्वदेशी का सपना तभी पूरा हो सकता है, जब देश के घरेलू उद्योग विकसित होंगे। माना कि भारत को अपने स्वदेशी उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक आयात-निर्यात के नियमों और समझौतों का पालन करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि छोटे उद्योगों के विकास की ओर गंभीरता न दिखाई जाए। सरकार को लघु उद्योगों के

वदलता बांग्लादेश और चुनौतियां बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनना केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय है। दो दशकों बाद हुए इस बदलाव ने भारत-बांग्लादेश संबंधों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नई राजनीतिक परिस्थिति में भारत को अपनी कूटनीति का संतुलन पर सिर से साधना होगा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक विश्वास को पुनः स्थापित करने की होगी। लंबे समय तक चले करीबी समीकरण अब स्वतः जारी नहीं रहेंगे। बीएनपी नेतृत्व ने भले ही भारत से बेहतर संबंधों की इच्छा जताई हो, परन्तु घरेलू राजनीति के दबाव में उसे कठोर रुख अपनाया पड़ सकता है। यही कारण है कि आने वाले महीनों में भारत को बयानबाजी से अधिक व्यावहारिक कूटनीति पर ध्यान देना होगा। दूसरी अहम चुनौती सुरक्षा और सीमा प्रबंधन की है। अगर टाक अपनी घरेलू राजनीति के तहत सीमा या घुसपैठ जैसे मुद्दों को जोर से उठाता है, तो पूर्वोत्तर भारत पर दबाव बढ़ सकता है। चुनाव परिणाम के बाद दोनों देशों की ओर से सकारात्मक संकेत भी आए हैं। असल प्रश्न यह है कि क्या दोनों देश पुराने समीकरणों की जगह परिपक्व और बराबरी पर आधारित नया रिश्ता बना पाएंगे? भूगोल, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और क्षेत्रीय स्थिरता ये सभी कारक बताते हैं कि सहयोग ही सबसे व्यावहारिक रास्ता है। चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

शिवाजी महाराज जैसा कोई नहीं

कांग्रेसी नेता अपनी तुष्टिकरण की आदत के कारण ऐसे बयान दे देते हैं जो कि मुर्खता की सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं। उसके बाद तीव्र आलोचना होने पर यूटर्न लेकर सारा टीकरा मीडिया के सर मढ़ देते हैं। वह देते हैं मीडिया ने गलत अर्थ निकाला। ऐसा ही एक बयान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्द्धन सपकाल ने भी दिया है। उनके अनुसार शिवाजी महाराज के बराबर के योद्धा थे टीपू सुल्तान। लेकिन लगता है उनको ज्ञात ही नहीं है कि शिवाजी महाराज ने भारत की एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि टीपू सुल्तान ने अपने राज्य के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक न्यायपूर्ण और समृद्ध शासन स्थापित किया, जबकि दूसरे का शासन अत्याचारी और दमनकारी था। शिवाजी महाराज ने कभी नागरिकों को तुकसान नहीं पहुंचाया जबकि टीपू ने नागरिकों पर अत्याचार किए। शिवाजी ने संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया, जबकि टीपू संस्कृति व कला का दुश्मन था। शिवाजी महाराज ने एक समृद्ध आर्थिक नीति अपनाई थी, जबकि टीपू दमन करके के लिए अर्थ इकट्ठा करता था। टीपू ने हिंदुओं का कत्ल किया, उन्हें जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया और उनकी संपत्ति लूटी। उसने मंगलोर एवं केरल के हिंदुओं को भी जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। टीपू ने अनेकों मंदिरों को नष्ट किया। उसे कोई भी कैसे आदर्श मान सकता है। उसकी तुलना शिवाजी महाराज करना तो अपराध है। धर्मदंड नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

पश्चिमा और दक्षिण अमेरिकी देशों की आवाज को बुलंद करने की गुंजाइश भी देता है। वैश्विक स्तर पर भारत के स्वर भी उसकी धरेलू नीतियों से भी मेल खा रहे हैं। इस दिशा में कल्याणकारी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि परामर्श और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एआइ से जुड़ी पहल भारत के दावों को ठोस आधार प्रदान करती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि भारत केवल तकनीकी समावेशन का उपदेश ही नहीं दे रहा, बल्कि उसे अमल में भी ला रहा है।

महत्वाकांक्षियों को सदैव वास्तविकता की कसौटियों का भी सामना करना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत को लेकर मुश्किलें बढ़ती हैं तो उसे घरेलू मोर्चे से सीमांकितवदर आपूर्ति श्रृंखला के लिए विदेश पर निर्भरता तकनीकी संप्रभुता को सवाल के घेरे में खड़ा करती है। इसके अलावा एल्गोरिदम संबंधी पूर्वोग्रह से लेकर निजी डाटा संरक्षण जैसे प्रश्न भी हैं। ऐसे में यदि भारत वैश्विक स्तर पर एआइ की विश्वसनीयता की मांग को लेकर मुश्किलें बढ़ती हैं तो उसे घरेलू मोर्चे पर भी नियामकीय अनकूला प्रदर्शित करनी होगी। इसलिए यह एआइ शिखर सम्मेलन भारत के समक्ष चुनौतियां और अवसर दोनों प्रदान करता है। भारत यदि इसमें सफल होता है तो वह एआइ से जुड़ी भू-राजनीति को भी नए सिरे से संतुलित करने में सक्षम हो सकता है। इतना तो तय है कि भारत इस एआइ-एफएक्स में केवल एक डिब्बे में जगह पाने से संतुष्ट नहीं होने वाला। वह इंजन का हिस्सा भी बनना चाहता है।

(लेखक आब्द्वरि रिसर्च फाउंडेशन में उपस्थित हैं) response@jagran.com



ऊर्जा धार्मिक व्यक्ति

किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार की प्रकृति कुछ विशिष्ट गुणों से निर्धारित होती है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की पहचान भी उसके गुणों से होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य है। धैर्य का अर्थ है-वर्तमान भी परिस्थिति में विचलित न होना। परेशान होना, घबराान या अधीर हो जाना मनुष्य के लिए न तो उचित है और न ही हितकर। एक धार्मिक व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है, वर्तमान को समझता है और भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करता है। धैर्य के बाद आता दमन या आत्मसंयम। दमन का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण, जबकि शमन होना है दूसरों पर नियंत्रण। जो व्यक्ति समाज में फैले अन्याय, अराजकता और अस्वामिक गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष करता है, वह शमन करने वाला कहलाता है। जबकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध और लोभ को नियंत्रित करता है, वही दमन करने वाला है। एक धार्मिक व्यक्ति में दमन का गुण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना आत्मसंयम के धर्म की कल्पना अधूरी है।

अस्तेय हमारी आचार-संहिता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अस्तेय का अर्थ है-चोरी न करना। दूसरों की वस्तु, धन या अधिकार छीन लेना बाहरी चोरी है, वर्तमान को समझता है और भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करता है। धैर्य के बाद आता दमन या आत्मसंयम। दमन का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण, जबकि शमन होना है दूसरों पर नियंत्रण। जो व्यक्ति समाज में फैले अन्याय, अराजकता और अस्वामिक गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष करता है, वह शमन करने वाला कहलाता है। जबकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध और लोभ को नियंत्रित करता है, वही दमन करने वाला है। एक धार्मिक व्यक्ति में दमन का गुण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना आत्मसंयम के धर्म की कल्पना अधूरी है।

अस्तेय हमारी आचार-संहिता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अस्तेय का अर्थ है-चोरी न करना। दूसरों की वस्तु, धन या अधिकार छीन लेना बाहरी चोरी है। जबकि आंतरिक चोरी मन में होती है-जैसे ईर्ष्या, अनुचित लाभ की इच्छा या किसी का हक छीनने की मानसिक प्रवृत्ति। विचार, वाणी और कर्म, तीनों स्तरों पर चोरी से बचें। यही भाव शौच का भी है। शौच का अर्थ केवल बाहरी स्वच्छता नहीं है। वास्तविक शौच है-मन को पवित्र रखना और शरीर को स्वच्छ रखना। मन को शुद्ध रखने के लिए दो मार्ग हैं-बाहरी और आंतरिक। बाहरी मार्ग है स्वयं को निरंतर अच्छे कर्मों में लगाना। अर्थात् निःस्वार्थ सेवा और पुण्य कर्म करना। आंतरिक मार्ग है-अपने लक्ष्य और ईश्वर का स्मरण। बाह्य रूप से समाज सेवा और आंतरिक रूप से श्रद्धा, इन दोनों से मन शुद्ध रहता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

response@jagran.com

पोस्ट

इशान किशन ने एकदम धुंधले की तरह खेला। सभी छोटी टीमों में से पाकिस्तान को हराना भारत के लिए सबसे आसान लग रहा था, क्योंकि टी-20 क्रिकेट के प्रति उसका रवैया पिछली सदी जैसा ही है। हमेशा की तरह उन्हें करारी हार मिली। फुल कंवल कुटाई।

वीरेंद्र सहवाग@virendersehwaag

भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर हाय-तीबा करन निरर्थक है। 'अमम की अशा' वाले लोग बेवजह शोर मचा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने किसी भी मंच पर पाकिस्तान के प्रति गर्मजोशी नहीं दिखाई, तो खेल के मैदान पर ऐसा दिखाने की अपेक्षा क्यों की जाए?

अखिलेश शर्मा@akhilleshsharma1

एआइ समिट के लिए दिल्ली आने पर बहुत रोमांचित महसूस कर रही हूं। कार में बैठते ही तुरंत वाईफाई सुविधा मिलने लगी और आधे घंटे के सफर में उमका बघुवी इस्तेमाल भी किया। वाईफाई स्पीड भी जर्मनी में म्युनिख सिग्योरिटी काफ्रेस की तुलना में कहीं बेहतर रही। आशा जडेजा मोटवानी@ashajadeja325

जनपथक

आदत है जब हार की मिले कहा से जीत, अपना टीवी तोड़कर मारो सिर पर ईट। मारो सिर पर ईट मनाओ खुब मुहूर्तम, सोचो कोई उपाय होय दु ख थो थो तू कम! देनी है हर बार तुम्ही को बंधु शाहादत, क्रिकेट होय या युद्ध डाल लो इसकी आदत।

- ओमप्रकाश तिवारी

समित का थीम 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय'



नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट 2026' के दौरान सोमवार को काफ़ी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचे • गेट

स्थानीय कानूनों का पालन करें डिजिटल प्लेटफार्म: वैष्णव



अश्विनी वैष्णव • कड़वत फोटो

नई दिल्ली, प्रे: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वैश्विक डिजिटल प्लेटफार्मों को स्पष्ट संदेश दिया है कि उन्हें भारत में संचालन करते समय यहां के संवैधानिक और कानूनी ढांचे का पूरी तरह पालन करना होगा। वैष्णव ने सोमवार को कहा कि कंटेंट बनाने वाले वैश्विक डिजिटल प्लेटफार्मों को उन देशों की संस्कृति के बारे में जानना चाहिए जिनमें वे काम करते हैं। इनको सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति जागरूक रहना चाहिए। एआइ इंपैक्ट समिट के एक कार्यक्रम में मोशन पिक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष व सीईओ चार्ल्स रिक्किन ने कहा कि संस्कृति के बारे में जानना चाहिए जिनमें वे काम करते हैं। इनको सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति जागरूक रहना चाहिए। एआइ इंपैक्ट समिट के एक कार्यक्रम में मोशन पिक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष व सीईओ चार्ल्स रिक्किन ने कहा कि संस्कृति के बारे में जानना चाहिए जिनमें वे काम करते हैं। इनको सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

प्रदूषण नियंत्रण में मदद कर सकता है एआइ

नई दिल्ली, प्रे: देश में सड़क दुर्घटनाओं से बचने और वाहनों के प्रदूषण की समस्याओं को नियंत्रित करने में एआइ मददगार हो सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी पंकज अग्रवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट के दौरान कहा कि सड़क और परिवहन उद्योग में एआइ के एकीकरण की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में ड्राइविंग को पाठ्यक्रम में शामिल करने से इस दिशा में मदद मिल सकती है। **एआइ और सड़क सुरक्षा:** भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डाटा-आधारित समाधान पर पैमाने चर्चा के दौरान, उन्होंने कहा कि एआइ दुर्घटनाओं से बचने और

मृत्यु दर कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि डाटा से पता चलता है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित पहली समस्या तेज गति से वाहन चलाना है। इसलिए एआइ की मदद से सटीक डाटा जुटाने और मानवीय हस्तक्षेप के बिना साक्ष्य उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

एआइ से लैस 'हाइड्रोपोनिक' खेती पर निवेश करेंगे भारतीय उद्यमी

नई दिल्ली, प्रे: देश के एक उद्यमी जिनको एक दशक पहले सूखे के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, अब कर्नाटक में महंगे मसाले और औद्योगिक पौधे उगाने के लिए एआइ से लैस हाइड्रोपोनिक खेती में 214 करोड़ रुपये निवेश कर रहे हैं। **हाइड्रोपोनिक खेती का मतलब बिना मिट्टी के, केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करके पौधे उगाना है। इस तकनीक में पानी में आवश्यक खनिजों को मिलाकर सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है।** मंगलौर की पनामा हाइड्रो-एक्स के संस्थापक और सीईओ विवेक राज ने कहा कि कंपनी ने वहाँ तक शोध एवं विकास पर 146 करोड़ खर्च करने के बाद चार पेटेंट वाली एआइ प्रौद्योगिकी विकसित की हैं। इसमें ऐसे प्रणाली शामिल हैं जो फसल की बीमारियों का लक्षण दिखने से पहले पता लगा सकती हैं।

और सीईओ विवेक राज ने कहा कि कंपनी ने वहाँ तक शोध एवं विकास पर 146 करोड़ खर्च करने के बाद चार पेटेंट वाली एआइ प्रौद्योगिकी विकसित की हैं। इसमें ऐसे प्रणाली शामिल हैं जो फसल की बीमारियों का लक्षण दिखने से पहले पता लगा सकती हैं।

टेक लीडर्स की सलाह, एआइ से घबराएं नहीं, नए टूल सीखते रहें

लगातार सीखने की चाह ही एआइ के महासागर में करेगी नैया पार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: देश में एआइ को लेकर बहस तेज है- क्या इससे नौकरियां जाएंगी या नए अवसर बनेंगे? आश्चर्यों के बीच तकनीकी उद्योग के दिग्गजों ने कर्मचारियों और बुद्धिमानों को 'शांत रहने व लगातार कुशल उन्नयन' की सलाह दी है। एआइ इंपैक्ट समिट 2026 में वक्ताओं ने कहा कि आने वाले 3-5 वर्षों में कार्यबल का पुनर्गठन तेज होगा, लेकिन एआइ नई नौकरियों के अवसर भी पैदा करेगा, इसलिए कर्मचारियों को एआइ टूल सीखकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखना होगा। पीटीआइ के अनुसार, नौकरी डाटा काम के मालिक संजीव ब्रिखचंदानी ने कहा कि जैसे कंप्यूटर आने पर बॉकिंग में उत्पादकता बढ़ी थी, वैसे ही एआइ भी अवसर लेकर आएगा। वहीं एजवर वकी सीईओ सतीश सोलारमैया ने कहा कि एआइ क्षमता बढ़ाने वाला माध्यम है और जीवन पर्यंत सीखने की चाह ही आगे बढ़ने का मंत्र होगा। संपर्क फरटोडेशन के प्रमुख विनीत नायर ने कहा कि एआइ से कुछ नौकरियां जाएंगी, लेकिन उतनी ही नई नौकरियां भी बनेंगी, जिनके लिए कुशल



भारत मंडपम में एआइ इंपैक्ट एक्सपो 2026 के दौरान एक स्टाल पर प्रदर्शित एआइ रोबोटिक सर्जरी का मॉडल • एपी

जनशक्ति जरूरी होगी। एआइ 'मल्टीप्लायर' की तरह काम कर सकता है। एचसीएल के विनीत नायर का कहना है कि करीब आधी नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन उतने ही नए मौके भी बनेंगे- शर्त यह है कि लोग नई स्किल सीखें। **अनुमान है कि एआइ वैश्विक स्तर पर लगभग 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा करेगा, जबकि करीब 9.2 करोड़ नौकरियां भी प्रभावित भी कर सकता है।** माइक्रोसाफ्ट के पुनीत चडोका ने कहा कि भारत में 59 प्रतिशत व्यवसायों में एआइ एजेंटों का इस्तेमाल हो रहा है। एचसीएल के विनीत नायर का कहना है कि करीब आधी नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन उतने ही नए मौके भी बनेंगे- शर्त यह है कि लोग नई स्किल सीखें। अनुमान है कि एआइ वैश्विक स्तर पर लगभग 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा करेगा, जबकि करीब 9.2 करोड़ नौकरियां भी प्रभावित भी कर सकता है। माइक्रोसाफ्ट के पुनीत चडोका ने कहा कि भारत में 59 प्रतिशत व्यवसायों में एआइ एजेंटों का इस्तेमाल हो रहा है।

जस्टिस माहेश्वरी बोले- जजों की जगह नहीं ले सकता एआइ

जाला दीक्षित • जागरण

नई दिल्ली : दिल्ली में सोमवार से शुरू हुए एआइ समिट में दुनियाभर के दिग्गज भाग ले रहे हैं और कामकाज में एआइ के उपयोग, इसके फायदे और कमियों पर मंथन चल रहा है। इसी क्रम में न्यायापालिका में एआइ के इस्तेमाल पर भी एक सत्र में मंथन हुआ, जिसका निष्कर्ष था कि एआइ न्याय की रफ्तार बढ़ा सकता है, लेकिन जजों की जगह नहीं ले सकता। फेसल पर पहुंचने की प्रक्रिया में मदद और केस मैनेजमेंट के लिए एआइ की सहायता ली जा सकती है और ली जा रही है। लेकिन, अंतिम फैसला सिर्फ इंसान ही कर सकता है, क्योंकि उसमें भावनाओं को महसूस करने और परिस्थितियों को समझने की क्षमता होती है। विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि हम चीजों की स्ट्रीमलाइन करने में मशीन की मदद ले सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला निश्चित तौर पर जज का होना चाहिए। मानवीय भावनाएं फेसल की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं, जिसे मानव ही समझ सकता है।

- न्यायापालिका में एआइ के इस्तेमाल पर हुए सत्र में विधि आयोग के अध्यक्ष ने रखी बात
- हम मशीन की मदद ले सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जज का होना चाहिए

सीखना होगा कि मशीन एल्गोरिदम के आधार पर चीजें स्टोर करने के लिए तैयार की जाती है और टूट की जाती है। जो भी उसमें जाता है, उसे रख लेती है। यह मानव से भिन्न है। एक खुले दिमाग का मानव सही और गलत के बीच अंतर कर सकता है। सुसंगत और असंगत के बीच भेद कर सकता है। मशीन को भूलने में मुश्किल होती है। वह भूल नहीं सकती, जबकि मानव में भूलने की क्षमता होती है। यह अंतर है। एआइ का अतिविकसूल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें, तो हमें अपनी वास्तविक बुद्धि को आगे रखना चाहिए। न्यायापालिका में तकनीक को बढ़ावा देने और टूल उपलब्ध कराने में मदद कर रही कंपनी टीईआरईएस और एनईजीडी के सीईओ विकास महेंद्रा व रजनीश कुमार ने बताया कि एआइ से मुकदमों में तेजी लाने का काम हो रहा है। **संबंधित >> जागरण सिटी**

समित से दिल्ली समेत अन्य राज्यों के पर्यटन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: एआइ समिट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के आने से दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे आसपास के पर्यटन राज्यों में पर्यटन गतिविधियों में तेजी की उम्मीद है। दूर दूरवेल्व व होटल्स संगठनों के अनुसार एआइ समिट के चलते दिल्ली समेत अन्य राज्यों में पर्यटन गतिविधियों में 30 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया जा रहा है। विशेष बात यह है कि राजस्थान के जयपुर, उत्तराखंड के ऋषिकेश व उत्तर प्रदेश के आगरा के साथ ही अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर भी पर्यटकों के पसंदीदा पर्यटन स्थल में शामिल है। इंडियनस फेडरेशन टूरिज्म एट्रिब्यूटी के संस्थापक शैलेंद्र श्रीवास्तव के अनुसार रामलला के दर्शन को न सिर्फ हिंदू बल्कि बाहर से आ रहे प्रतिनिधि भी उत्सुक हैं और बुकिंग बढ़ी है। उनके अनुसार,

- उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे पर्यटन राज्यों में 30% तक बढ़ोत्तरी की उम्मीद
- ताजमहल के साथ अयोध्या का रामलला मंदिर भी विदेशी मेहमानों की सूची में

लोग मंदिर के वास्तुशिल्प, भव्यता को देखने के साथ सनातन संस्कृति को समझना चाहते हैं। फेडरेशन आफ एसोसिएशन इंडियन टूरिज्म एंड हास्पिटैलिटी के महासचिव राजीव मेहरा कहते हैं कि एआइ समिट से देश के पर्यटन उद्योग को बड़ी उम्मीद है। विश्वभर से लोग दिल्ली आ रहे हैं। राजीव मेहरा के अनुसार, यह देश के पर्यटन उद्योग के लिए अच्छा मौका है। विदेशियों में सबसे अधिक मांग ताजमहल की रहती है। यह समिट 20 फरवरी तक चलेगा।

भारत में एआइ के नए सुरक्षा बदलाव के बीच साइबर हमले बढ़े

नई दिल्ली, एनआइ: भारत में एआइ के चलते नए सुरक्षा बदलाव के बीच डिजिटल खतरे में बढ़ोतरी हुई है। देश के संगठनों को अब औसतन 3,195 साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। चेक प्वाइंट साफ्टवेयर की 2026 साइबर सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, "2025 में भारत में साप्ताहिक औसत साइबर हमले 3,195 थे, जो 2024 की तुलना में दो प्रतिशत अधिक है।" चेक प्वाइंट साफ्टवेयर के रिसर्च के उपाध्यक्ष लोतेम फिकेल्स्टीन ने बताया कि हमले के पैटर्न में यह बदलाव मुख्य रूप से साइबर अपराधियों के टूलकिट में एआइ के एकीकरण द्वारा प्रेरित है। रिपोर्ट के अनुसार एआइ साइबर हमलों की मैकेनिक्स को बदल रहा है, केवल उनकी मात्रा को नहीं बल्कि हमलावर पूरी तरह से मैनुअल संचालन से बढ़ते हुए स्वचालन के उच्च स्तरों की ओर बढ़ रहे हैं।



रोबोट का क्रेज...

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट 2026' के दौरान सोमवार को एक स्टॉल पर रोबोट का क्रेज देखने को मिला। उत्सुकता के साथ आगंतुकों ने इस पल को मोबाइल में भी कैद किया • गेट

शादी से पहले किसी पर भरोसा न करें: सुप्रीम कोर्ट



- शीर्ष अदालत ने शादी से पहले शारीरिक संबंधों में सावधानी बरतने की सलाह दी
- शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने के मामले में मुकदमा चलाने से इन्कार

नई दिल्ली, प्रे: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नौ सदस्यीय पीठ सबरीमाला समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सात अप्रैल से अंतिम सुनवाई प्रारंभ करेगी। पीठ इसके साथ ही विभिन्न धर्मों की धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर भी विचार करेगी। सितंबर, 2018 में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसले में सबरीमाला स्थित अय्याया स्त्राली मंदिर में 10 से 50 वर्ष उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। बाद में 14 नवंबर, 2019 को संसदीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से विभिन्न धर्मस्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मुद्दा बड़ी पीठ को संदर्भित कर दिया था।

महिलाओं से भेदभाव मामले की नौ जज करेंगे सुनवाई

- सात अप्रैल से प्रारंभ होकर 22 अप्रैल तक चलेगी सुनवाई
- धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर विचार के लिए सात स्त्राल किए

केरल सरकार ने कहा, उचित रुख अपनाएं
 उधर, प्रे के अनुसार केरल की वामपंथी सरकार ने सोमवार को कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे में कई संवैधानिक जटिलताएँ हैं, इसलिए विचार-विमर्श के जरिये इस पर उचित रुख अपनाया जाएगा।

था। सबरीमाला मामले के अतिरिक्त फैसले में मस्जिदों व दरवाहों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश व गैर-पारसी पुरुष से विवाह करने वाली पारसी महिलाओं के अगियारी के विषय अग्नि स्थान पर प्रवेश का मुद्दा भी बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया था। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त, जस्टिस जोयमाला बागची व जस्टिस विपुल एम. पंचोलो की पीठ ने कहा कि

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: सोमवार से शुरूवार तक चलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महकभुम 'एआइ इंपैक्ट समिट 2026' में हिस्सा लेने के लिए दुनियाभर के दिग्गज यहां पहुंच चुके हैं। इस शिखर सम्मेलन के जरिये तेजी से बदलती एआइ की दुनिया को समझना और आम लोगों तक इसके फायदे और असर को पहुंचाना आसान हो सकता है। इसमें न केवल टेक कंपनियों के दिग्गज, बल्कि अनेक देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हिस्सा ले रहे हैं। **एआइ इंपैक्ट समिट क्या है :** इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट 2026 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्रालय और इंडिया एआइ मिशन की पहल है। यह पांच दिन का कार्यक्रम है, जिसमें पॉलिसी, रिसर्च, इंडस्ट्री और आम भागीदारी, सबको जोड़ा गया है। सरकार ने इस समिट की थीम रखी है- सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। **इससे पहले कहाँ हो चुकी है समिट:** साल 2023 में सबसे पहले एआइ समिट ब्रिटेन में हुई थी। इसके बाद मई, 2024 में दक्षिण कोरिया में एआइ को सुरक्षित और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया था। फरवरी, 2025 में पेरिस में एआइ एक्सपन समिट में एआइ को सार्वजनिक हित और टिकाऊ विकास से जोड़ने पर चर्चा हुई थी। **दिल्ली की समिट की क्या है महत्त्व:** दिल्ली समिट को सरकार ग्लोबल साठथ में पहली

वैश्विक एआइ समिट बता रही है। इस बार चर्चा सिर्फ एआइ के खतरे तक नहीं, बल्कि इस पर है कि एआइ का फायदा गरीब और मध्यम वर्ग तक कैसे पहुंचे। सरकार ने इसे एआइ विभाजन को खत्म करने की दिशा में एक कदम बताया है। यानी तकनीक से लैस और तकनीक रहित लोगों के बीच दूरी कम हो।

'एआइ से स्वास्थ्य कर्मियों का बोझ होगा कम'

नई दिल्ली, प्रे: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सोमवार को कहा कि एआइ में हेल्थकेयर कार्यबल का बोझ कम करने की क्षमता है। साथ ही इससे डाक्टर-भरीज के रिश्ते को मजबूती मिलेगी, न कि यह उसकी जगह ले लेगा। इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट,

एआइ समिट एक नजर में

- 20 फरवरी तक एआइ के विभिन्न पहलुओं पर किया जाएगा मंथन
- 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान
- 13 देशों के पेंवैलियन शामिल होंगे एक्सपो में
- 500 से ज्यादा सत्रों में विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा
- 3250 से ज्यादा एआइ विशेषज्ञ रखेंगे अपनी बात
- 300 से ज्यादा एमो के जरिये एआइ के प्रयोग दिखाए जाएंगे
- 600 से अधिक स्टार्टअप प्रोजेक्ट से वाकिफ होंगे लोग

समित में शामिल होने के लिए 'इंपैक्ट डाटा इंडियाएआइ डाटा जीओबी डाटा इन पर फंजीकरण करा सकते हैं

'मियां पर नफरती भाषण में हिंमत को मिली राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 'मियां मुस्लिम' पर नफरती भाषण व शूटिंग के विवादित वीडियो के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्म सारमा के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई व एसआइटी गठन करने से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने को कहा है। याचिकाकर्ताओं की मांग पर कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जल्द सुनवाई का आग्रह किया। ये निर्देश प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त, जोयमाला बागची व विपुल एम. पंचोलो की पीठ ने भाकपा नेत्र एपी राजा और एक अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर दिए। जस्टिस सूर्यकान्त ने कहा कि हाई कोर्ट क्षेत्राधिकार को है और उसे मामला सुनने का अधिकार है।

संभावनाओं की राह

तेजी से बदलती भू–राजनीतिक परिस्थितियों में दुनिया भर में अभी सबसे ज्यादा जोर आधुनिक तकनीकों के विकास और इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा नवाचार के प्रयोग पर दिया जा रहा है। सभी देश अपनी विकास नीतियों में अद्यतन तकनीकों को अपना रहे हैं और पारंपरिक तरीके से होने वाले बहुत सारे कामों का स्वरूप अब बदल रहा है। खासतौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआइ के फैलते दायरे ने वैश्विक स्तर पर कामकाज के तौर–तरीकों और उसमें इंसानी भूमिका पर व्यापक असर डाला है। इसे समय के साथ कदम मिला कर चलने और विकास के परिप्रेक्ष्य में जरूरी माना जा रहा है तथा सभी देश एआइ के सकारात्मक उपयोग को लेकर सक्रिय दिख रहे हैं। भारत की इसमें एक महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। गौरतलब है कि नई दिल्ली में सोमवार से पांच दिनों का एआइ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें कई देशों के राष्ट्रध्यक्ष से लेकर एआइ कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य एआइ के व्यापक तंत्र पर चर्चा के साथ–साथ आम लोगों की जिंदगी पर इसके सीधे असर और फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

दरअसल, तकनीक के मामले में जितनी तेज रफ्तार से नवाचार का प्रयोग हुआ है, सभी जरूरी क्षेत्रों में एआइ का दायरा फैला है, उसमें इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है कि इसकी संभावनाओं और उम्मीदों के साथ–साथ इससे जुड़ी आशंकाओं पर भी विचार हो। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि विकास के किसी स्वरूप से अंतिम तौर पर आम लोग प्रभावित होते हैं और कोई भी तकनीक इसी कसौटी पर देखी जाएगी कि उससे मनुष्य का कितना समग्र हित सुनिश्चित हो सका और दुनिया की ज्यादातर आबादी के लिए वह कितनी उपयोगी साबित हुई। हाल के दिनों में जब से एआइ के बढ़ते दायरे और इसके असर की बात होने लगी है, तब से इसे भविष्य में नौकरियों का सृजन करने का औजार भी बताया गया है। दूसरी ओर, एआइ के फैलते पांव के समांतर रोजगार पर इसके व्यापक प्रभाव और खतरों को लेकर आशंकाएं भी जताई गई हैं। दिल्ली के सम्मेलन में एक उद्देश्य एआइ से रोजगार, आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर और उसके खतरों को कम करने के लिए ठोस उपायों तथा प्रयासों पर भी चर्चा करना है।

यह जगजाहिर है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायरा कितने बड़े क्षेत्र में फैल चुका है। हाथ में मौजूद स्मार्टफोन अब केवल तस्वीरें संपादित करके सोशल मीडिया के मंचों पर सुर्खियां हासिल करने का जरिया भर नहीं है। चिकित्सा जगत में एआइ का उपयोग बीमारी की पहचान से लेकर इलाज में भी होने लगा है। अपराध पर लगाम लगाने के मामलों में एआइ की उपयोगिता साबित हो चुकी है। शिक्षा जगत से लेकर रक्षा और कारोबार के विभिन्न क्षेत्र में नए स्तर पर इसका प्रयोग हो रहा है। जाहिर है, विकास के नए मानक रचने और आधुनिक दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए एआइ के मामले में हर वक्त अद्यतन रहने की जरूरत होगी। मगर रोजगार के अवसरों के सिकुड़ने से लेकर कई स्तर पर लोगों की जिंदगी से जुड़े बहुस्तरीय जोखिम के जैसे मामले तेजी से सामने आने लगे हैं, उसका हल निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। साथ ही एआइ डेटा केंद्रों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और पानी की खपत को लेकर जिस तरह की चिंताएं उभरी हैं, अगर उसका कोई ठोस हल नहीं निकाला गया, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर विकास कसौटी पर होगा।

महंगाई की मार

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। माना जा रहा है कि मजबूत घरेलू खपत, नीतिगत सुधारों और तेज आर्थिक वृद्धि से यह मुकाम हासिल हुआ है। अब यह दावा किया जा रहा है कि निकट भविष्य में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लेगा। मगर, आर्थिक विकास के आंकड़ों से जुड़े आकलन के इस पैमाने में क्या महंगाई को कम या स्थिर करने का पहलू भी शामिल किया गया है? यह सवाल इसलिए अहम है कि एक तरफ विकास की चमकती तस्वीर पेश की जा रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। सरकार की ओर से पिछले सप्ताह और सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष की शुरुआत ही महंगाई में बढ़ोतरी के साथ हुई है। देश में थोक महंगाई जनवरी में बढ़कर 1.81 फीसद पर पहुंच गई, जबकि गत वर्ष दिसंबर में यह 0.83 फीसद पर थी। इसी तरह खुदरा महंगाई पिछले माह बढ़कर 2.75 फीसद हो गई, जिससे खाद्य सामग्री समेत कई जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं।

गौरतलब है कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्य वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन, ईंधन और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। इस कारण उनके जीवनयापन की लागत बढ़ जाती है, उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है और उन्हें अपने दूसरे खर्चों में कटौती के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, थोक महंगाई में बढ़ोतरी खाद्य एवं गैर–खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में मासिक आधार पर वृद्धि के कारण हुई है। सबसे ज्यादा चिंताजनक है खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ना, क्योंकि इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। पिछले माह खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर 1.55 फीसद रही, जबकि गत वर्ष दिसंबर में इसमें 0.43 फीसद की गिरावट दर्ज की गई थी। इनमें भी सब्जियों की महंगाई दर सबसे ज्यादा 6.78 फीसद पर पहुंच गई है। यानी अब आम आदमी की थाली में सब्जियों की मात्रा कम हो गई है। महंगाई दर में यह उतार–चढ़ाव दर्शाता है कि विकास में स्थिरता और समानता का संतुलन सधने की जरूरत है।

खेती और खाद्य सुरक्षा की नई चुनौतियां

भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में अनाज उत्पादन में थोड़ी–सी भी कमी व्यापक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए यूरिया जैसी बुनियादी कृषि सामग्री को लेकर तय की गई किसी भी नीति का मूल्यांकन केवल बजट संतुलन के नजरिए से नहीं किया जाना चाहिए।

देवेंद्रराज सुथार

भारतीय कृषि व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले यूरिया उर्वरक को लेकर केंद्र सरकार के हालिया निर्णय ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आदेश के तहत यूरिया की बोरी का वजन 50 किलो से घटा कर 40 किलोग्राम कर दिया गया है। इसके साथ ही यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा भी 46 से घटा कर 36 फीसद कर दी गई है। सरकार इसे सुधारात्मक कदम के रूप में पेश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस निर्णय ने किसानों की लागत बढ़ा दी है और कृषि उत्पादन तथा देश की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

यूरिया खेती में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है। गेहूं, धान और मक्का जैसी उच्च उत्पादकता वाली फसलों की उपज काफी हद तक नाइट्रोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह पौधों की बढ़वार, पत्तियों के विकास और दाने भरने की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य तत्त्व है। ऐसे में यूरिया के स्वरूप में किया गया कोई भी बदलाव सीधे तौर पर फसलों की पैदावार, किसानों की आय और अंततः उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। सरकार के नए फैसले के बाद यूरिया की एक बोरी में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा में भारी गिरावट आई है। पहले 50 किलो की बोरी में 46 फीसद नाइट्रोजन के हिसाब से लगभग 23 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध होती थी। अब 40 किलो की बोरी में 36 फीसद नाइट्रोजन के साथ यह मात्रा घट कर केवल 14.4 किलो रह गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसान को उतनी ही नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक यूरिया खरीदना पड़ेगा।

अगर मौजूदा 270 रुपए प्रति बोरी की कीमत को आधार बनाया जाए, तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। पहले जहां किसानों को प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए लगभग साढ़े सत्रह सौ रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब वही जरूरत पूरी करने के लिए 2835 रुपए खर्च करने होंगे। यानी बिना दाम बढ़ाए ही किसानों पर करीब 37 फीसद अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। यह बोझ खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद मुश्किल भरा साबित हो सकता है।

देश में लगभग एक करोड़ साठ लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसमें से करीब 65 फीसद भूमि की सिंचाई वर्षा पर आधारित है। यहां दलहन, तिलहन और बागवानी जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों में यूरिया की खपत अपेक्षाकृत कम होती है और कई मामलों में एक टन प्रति हेक्टेयर से भी कम रहती है, लेकिन शेष लगभग पचास लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि पर गेहूं और धान जैसी उच्च उत्पादकता वाली फसलें ली जाती हैं, जिनके लिए नाइट्रोजन की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। मौजूदा कृषि सिफारिशों के अनुसार गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर सालाना लगभग तीन सौ किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है। जबकि 46 फीसद नाइट्रोजन वाले यूरिया के हिसाब से यह आवश्यकता लगभग 620 किलो यूरिया से पूरी हो जाती थी। इसी आधार पर देश के सिंचित क्षेत्रों के लिए सालाना करीब तीन करोड़ बीस लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत आंकी



जाती है। जब कुल खपत चार करोड़ मीट्रिक टन से अधिक है, तो सवाल उठता है कि बाकी यूरिया कहां जा रहा है? इस सवाल का जवाब देश में लंबे समय से चले आ रहे यूरिया के दुरुपयोग में छिपा है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि सबसिडी वाले यूरिया का एक बड़ा हिस्सा

यूरिया की उपलब्धता का संकट केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की खाद्य सुरक्षा से भी है। पिछले तीन वर्षों में गेहूं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद सरकारी खरीद अपने लक्ष्य से काफी पीछे रही है। यह स्थिति तब है, जब सरकार पैदावार के बड़े–बड़े दावे करती रही है। इस थिरोधाभास से संकेत मिलता है कि देश में गेहूं का वास्तविक उत्पादन और घरेलू खपत लगभग बराबर स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में यदि यूरिया की कमी या महंगाई के कारण पैदावार में गिरावट आती है, तो देश को अनाज आयात पर निर्भर होना पड़ सकता है।

कृषि के बजाय औद्योगिक उपयोग में चला जाता है। अनुमान है कि कुल सबसिडी वाले यूरिया का लगभग एक–तिहाई, यानी एक करोड़ मीट्रिक टन

मौन की शक्ति

रेखा शाह आरबी

मौन निशब्द है, लेकिन यह भाषा है, भाव, शब्द, अर्थ, साधना, भक्ति, शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, सुंदर और मुखर भी है। यह अमूल्य आभूषण भी है। मौन को जितनी भी उपाधि दी जाए, कम ही है। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि यह शक्तिशाली है। कभी–कभी हम बोलकर शब्दों के जरिए जितना सटीक अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उससे ज्यादा चुप रहकर बोल लेते हैं। कुछ भाव–भावनाओं के लिए तो शब्दकोश में शब्द खोजते रह जाते हैं, लेकिन नहीं मिलता। वहीं भाव भंगिमा की सहायता से मौन के सहारे एकदम सटीक, बेहतर तरीके से अपनी बात कह देते हैं। कुछ लोग शब्दों की अनुपस्थिति को मौन मान लेते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौन का मतलब सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, स्पष्टता और समझ पाने की गहरी क्षमता है। इससे इंसान के भीतर आत्मचिंतन और एकाग्रता में इजाफा होता है। मौन उसे ही माना जा सकता है, जहां हमारा चित्त पूरी तरह से शांत हो। वहीं बिना वजह का बोलना हमारी ऊर्जा का फिजूल खर्च है। ऐसी जगह पर शाब्दिक ‘मौन’ ऊर्जा की बचत ही करता है। साथ ही अत्यधिक वाचाल होना विभिन्न प्रकार के विवादों को न्योता देना होता है, जिससे हम अनावश्यक विवाद में उलझते हैं।

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मौन को वरदान के तौर पर देखा जाता है। इसके जरिए हम खुद के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ते हैं। जब हम मौन में रहते हैं, तो अपने ऊपर चिंतन–मनन करते हैं। अपने जीवन के बारे में ठीक–ठाक विश्लेषण करते हैं, जो हमारे जीवन में सार्थक और चमत्कारिक बदलाव लाता है। इससे हम दुनिया के बाहरी शोर को परे रखकर आंतरिक ज्ञान और स्थिरता पाते हैं। यह सब हमारे मन को शांत करता है और जीवन को सकारात्मक बनाता है। कहा जा सकता है कि मौन हमारा आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास करता है।

मौन की एक शक्ति हमारे परिस्थितजन्य तात्कालिक आवेग को रोक कर कुछ भी अनुचित कहने से रोकना है, जो रिश्तों को बचाने का काम करता है। अक्सर अत्यधिक बोलने वाले आवेग में ऐसी बातें बोल देते हैं, जो लोगों को अप्रिय लगती है और फिर रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। पर जिन्हें मौन का अभ्यास होता है, वे अपने तात्कालिक आवेग पर नियंत्रण रख लेते हैं। बाहर से देखने पर मौन में भले खामोशी दिखती है, लेकिन यह एक सक्रिय अवस्था है जो जीवन में आंतरिक शक्ति, शांति जीवन में लाने का कार्य करती है। जानकार लोग

भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम केवल न बोलने को मौन समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में मौन तब होता है, जब मन की खटपट मिट जाए, मन पूरी तरह शांत हो जाए। हमारे होंट भी इसी कारण चलते हैं, क्योंकि जब मन अशांत होता है, तब हम मौन होकर भी मौन नहीं होते हैं। शब्दहीनता को मौन समझ लेना इसका सस्ता अर्थ लगाना है।

श्रीमद्भागवत गीता में मौन को मानसिक ‘तप’ के साथ–साथ आत्मसंयम का साधन और ईश्वर की वाणी सुनने का मार्ग बताया गया है। मौन का अर्थ केवल वाणी से नहीं, बल्कि मन की चंचलता को रोकने से है। और मन की चंचलता को रोकना अपने आप में दुःसाध्य कार्य है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार, मानसिक शांति, आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक आवश्यक साधन है।

किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं– सकारात्मक और नकारात्मक। मौन का नकारात्मक पहलू यह है कि यह कई बार अर्थ का अनर्थ भी कर देता है। भले ही इसके बहुत सारे लाभ हों, लेकिन अक्सर यह संशय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसे एक दुधारी तलवार की तरह देखा जा सकता है, जो अपने नकारात्मक पक्ष में भी ज्यादा धारदार या नुकसानदेह नहीं है। फिर भी इसमें थोड़ी धार तो होती ही है। इसलिए मौन का भी उपयोग करते हुए सचेत रहने की जरूरत होती है। अगर सही समय पर सही बात को नहीं बोला जाए तो गलतफहमी भी उत्पन्न करता है। अक्सर हमारे मौन को हमारी असहमति या कमजोरी मान लिया जाता है, जिससे स्थिति सुधरने के बजाय और भी बिगड़ जाती है। जब संवाद रुक जाता है, तब मौन से भावनाएं मर जाती हैं और रिश्तों में विश्वास और असुरक्षा की भावना पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है।

मौन वही सही है, जो मन को शांति दे। जब किसी विषय वस्तु पर कोई व्यक्ति चुप रहता है, तो अन्य लोग उसकी चुप्पी को बहुत ही आसानी से सहमति या असहमति मान लेते हैं। जबकि हर बार ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी अन्य परेशानी में उलझा हुआ हो या उस स्थिति के लिए कुछ सही शब्द नहीं मिल रहे हों, जिसके कारण वह फिलहाल चुप है। हालांकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी गंभीर मुद्दे पर चुप्पी कोई हल निकालने के बजाय समस्या को दोगुना बढ़ा देती है। समाधान के लिए बात करना जरूरी होता है और वह भी समय पर। अगर समय पर बात नहीं की जाए, तो कई बार स्थिति हाथ से निकल जाती है। कहा जा सकता है कि समय के मुताबिक मौन अपनी जगह पर सही है और संवाद भी अपनी जगह पर सही है। बस इनमें से किसी का चुनाव समय और जरूरत के मुताबिक और सतर्कता से हो।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com |chaupal.jansatta@expressindia.com

सूचनाओं का जंजाल

सूचना क्रांति ने जिस तरह पूरी दुनिया को अपने जाल में उलझाया है, वह किसी से छिपा नहीं है। सूचनाओं की इतनी भरमार है कि शाब्द ही कभी मानव मस्तिष्क ने इतनी सूचनाओं का भार झेला हो। परिणाम यह हुआ है कि किसी भी मुद्दे पर सही और गलत के बीच अंतर तय करना मुश्किल हो गया है। सूचनाओं के नाम पर मनुष्य की भावनाओं के साथ सोशल मीडिया मंच के एल्गोरिद्म ऐसा खेल खेल रहे हैं कि मस्तिष्क सही को गलत और गलत को सही मानने पर मजबूर हो जाता है। मानव मस्तिष्क सूचनाओं का गुलाम हो चुका है। हमारी वैचारिक स्वायत्तता सूचनाओं के समंदर में गोते खा रही है। हमें क्या और कैसे सोचना है, यह हम नहीं बल्कि सूचनाएं तय कर रही हैं और इन सूचनाओं को तैयार करने वाले समूह हमें अपने अनुसरण कटपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। हमें इससे बचना होगा। इनका एक बहुत सामान्य–सा तरीका होता है जैसे डर, गर्व, अपराधबोध इत्यादि के सहारे भावनात्मक रूप से उद्देलित करना। अगर हम सावधान हो जाते हैं और परेसी गई सूचनाओं से हट कर खोजने पर विश्वास करते हैं, तो इनके जंजाल से बच जाते हैं।

- *अनुभव सिंह, प्रवाराज*

संवेदनहीनता का सिरा

‘जा नलेवा लापरवाही’ (संपादकीय, 9 फरवरी) पढ़ा। ऐसा लगता है कि हमारी संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं और हम सब केवल मशीन बन कर रह गए हैं। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत का मामला जानलेवा लापरवाही का उदाहरण है।रोजाना होने वाली भागदौड़, नियमों की अनदेखी और ‘मुझे क्या’ वाला रवैया आखिरकार किसी न किसी की जान लेकर ही दम लेता है। दूसरी ओर, यह साफ होता है कि

सुरक्षा की कुंजी

‘य बचपन’ (लेख, 13 फरवरी) बचपन (संख्ये) का एक गंभीर समस्या को उजागर करता है। आज बच्चे डिजिटल माध्यमों और आनलाइन खेल की बचपन में तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। पहले बच्चे दादा–दादी और नाना–नानी से कहानियां सुन कर संस्कार और जीवन–मूल्य सीखते थे, लेकिन अब वही कहानियां मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से देखी जा रही हैं। कम उम्र में ही बच्चों को कई बार अनुपयुक्त जानकारी

नैतिक दायित्व

‘वा यु प्रदूषण से सेहत पर बढ़ता संकट’ (लेख, 11 फरवरी) पढ़ा। पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है, जिसका असर मानव और प्रकृति पर बुरी तरह पड़ रहा है। प्रदूषित वातावरण में रहने वालों की आज औसत आयु घट रही है। बच्चों से लेकर बड़े–बूढ़े कैंसर और सांस संबंधी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। प्रदूषण आम तौर पर स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आज साइकिल से और पैदल चलना प्रदूषण को कम करने में सार्थक प्रयास हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तरह के छोटे–छोटे प्रयास ही वायु प्रदूषण को रोकने में महती भूमिका निभा सकते हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबका नैतिक दायित्व है, क्योंकि इसी से प्रकृति बचेगी और इसी से आने वाली पीढ़ियां बचेंगी।

- *साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर*



महोत्सव

बंगलुरु : कादु मल्लेश्वरा स्वामी मंदिर के रथोत्सव महोत्सव के दौरान शोभायात्रा में लोक नर्तक।

बोल

कृत्रिम मेधा मानव जाति के लाभ के लिए एक सांख्यिक साधन बने। भारत की भूमिका बेहद सफल उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में है और यह वैश्विक मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। - एंटोनियो गुतेर्रेस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव



बोल

वाशिंगटन, भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों जैसे प्रमुख रणनीतिक साझेदारी के साथ हमारे व्यापार, निवेश सहयोग और सैन्य-तकनीकी संबंधों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है और दबाव बना रहा है। - सर्गेई लावरोव, रूस के विदेश मंत्री



सम-सामयिक

नौसेना : पुरानी पनडुब्बियों की विदाई, नई लाने में देरी

जनसत्ता संवाद

नौसेना में चार दशक पुरानी पनडुब्बियों की विदाई और नई पनडुब्बियों को लाने में देरी से सवाल उठने लगे हैं। घटती संख्या, धीमी निर्माण प्रक्रिया और बढ़ते क्षेत्रीय खतरों अहम चुनौती बनते जा रहे हैं। नौसेना के अधिकारियों का मानना है कि पानी के भीतर की लड़ाई के लिए अपनी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। भारत के पास 17 पारंपरिक पनडुब्बियों का बेड़ा है, जिनमें से कई 30 साल से ज्यादा पुरानी हैं।



चीन की स्थिति

चीन के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और जिसका तेजी से विस्तार भी हो रहा है। इस वक्त चीन के पनडुब्बी बेड़े में 65 और 2035 तक 80 पनडुब्बी होने का अनुमान है। वहीं, भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण पनडुब्बी कार्यक्रम पी-75आइ को भी समय से पूरा नहीं कर पा रहा है। 43,000 करोड़ की इस परियोजना के तहत लक्ष्य दूसरे देश की कंपनियों के साथ मिलकर बेहतर संसार और हथियारों से लैस छह आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण करना है।

चार दशक की सेवा के बाद पिछले साल के आखिर में भारतीय नौसेना ने आइएनएस सिंधुघोष को सेवा से हटाया गया। इसके बाद भारत के पास अब 16 पारंपरिक पनडुब्बियां बची हैं। यह संख्या लगभग उतनी ही है, जितनी 1990 के आखिरी वर्षों में थी। तब पनडुब्बियों की भारी कमी को देखते हुए 1999 में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने 30 साल का कार्यक्रम मंजूर किया था। तब वाइस एडमिरल एके चटर्जी के बनाए 30 वर्षीय योजना में 24 पनडुब्बियों की जरूरत बताई गई थी। योजना थी कि 12 साल में दो अलग विदेशी डिजाइनों पर एक साथ छह-छह

पनडुब्बियां और रूस से लीज पर ली गई चक्रा परमाणु पनडुब्बी (एसएसएन) ही बचेंगी। अगर साल के अंत तक मझगांव डाक लिमिटेड (एमडीएल) और थाइसेनकूप मरीन सिस्टम्स के बीच पी-75आइ का काम शुरू होता है, तो पहले 18 महीने डिजाइन में लगेंगे। फिर लगभग सात साल बनने में लगेंगे। यानी पहली पनडुब्बी करीब 2035 तक तैयार होगी। अभी कोई एसएसएन सेवा में नहीं है और चक्रा-तीन की लीज 2028 तक टली हुई है।

शोध

कमजोर हड्डियां : शरीर के ही खास प्रोटीन से होगा इलाज

जनसत्ता संवाद

उम बढ़ने के साथ शरीर की हड्डियां कमजोर होने से 'आस्टियोपोरोसिस' और 'आस्टियोआर्थराइटिस' जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। ये दुनिया के सबसे आम और गंभीर हड्डी और जोड़ रोगों में शामिल हैं। निजात दिलाने के लिए वैज्ञानिकों ने शरीर के ही एक खास प्रोटीन से दवा बनाने पर शोध किया है।

'आस्टियोपोरोसिस' और 'आस्टियोआर्थराइटिस' जैसी बीमारियां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को परेशान करती हैं। भारत की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) की लखनऊ में स्थित प्रयोगशाला 'सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट' (सीडीआरआई) के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और आइआइटी- खड़गपुर संस्थानों के साथ मिलकर दो छोटी प्रोटीन-आधारित दवाएं विकसित की हैं। प्रयोगशाला और पशु परीक्षणों में यह 'पेप्टाइड थैरेपी' सुरक्षित और प्रभावी साबित हुई है। सीडीआरआई में कार्यरत रहे नैबेध चट्टोपाध्याय इस शोध के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। उनके साथ शिवानी शर्मा, चिराग कुलकर्णी समेत कई अन्य वैज्ञानिक शामिल हैं। चट्टोपाध्याय के मुताबिक, ये 'पेप्टाइड' 'आस्टियोपोरोसिस' और 'आस्टियोआर्थराइटिस' के इलाज को काफी आसान बना सकते हैं।

शोधकर्ताओं ने 'स्क्लेरास्टिन' नामक प्राकृतिक प्रोटीन पर शोध किया। यह हड्डी को शिकारों से बचाता है। यह उस प्रक्रिया को धीमा करता है, जिससे 'आस्टियोपोरोसिस' में हड्डियां कमजोर पड़ती हैं। दूसरा, हड्डी में होने वाली असामान्य वृद्धि को यह रोकता है और उपस्थिति (कार्टिलेज) को बचाता है। इससे 'आस्टियोआर्थराइटिस' की परेशानी कम होती है।

देश की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) की लखनऊ में स्थित प्रयोगशाला 'सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट' (सीडीआरआई) के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और आइआइटी- खड़गपुर, संस्थानों के साथ मिलकर दो छोटी प्रोटीन-आधारित दवाएं विकसित की हैं। प्रयोगशाला और पशु परीक्षणों में यह 'पेप्टाइड थैरेपी' सुरक्षित और प्रभावी साबित हुई है। सीडीआरआई में कार्यरत नैबेध चट्टोपाध्याय इस शोध के प्रमुख वैज्ञानिक हैं।



(फाइल फोटो)

उम्र के बाद 60 से 70 फीसद महिलाओं में 'आस्टियोआर्थराइटिस' के मामले देखने को मिलते हैं, जबकि पुरुषों में ये मामले महज 40 फीसद तक सामने आते हैं। खासकर बुजुर्गों एवं रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में इन रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस कारण मरीजों में विकलांगता होने का खतरा भी बना रहता है।



विश्व परिक्रमा

ओपनएआइ : प्रपत्र से सुरक्षित शब्द हटाया, मुनाफे पर जोर

जनसत्ता संवाद

एआइ चैटबॉट बनाने वाली कंपनी ओपनएआइ ने साल 2023 के अपने ध्येय प्रपत्र (मिशन स्टेटमेंट) में कहा था कि उसका लक्ष्य एसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) का विकास करना है, जो मानवता के लिए सुरक्षित और फायदेमंद हो तथा जिसका उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ कमाना न हो। हालांकि, अब उसने 'सुरक्षित' शब्द हटा दिया है। नवंबर 2025 में जारी आंतरिक राजस्व घोषणा फार्म में ओपनएआइ ने अन्य बदलावों के साथ-साथ अपने 'मिशन स्टेटमेंट' से सुरक्षित शब्द हटा दिया है।

शब्दों में यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है, जब कंपनी एक गैर-लाभकारी संगठन से तेजी से एक ऐसे व्यवसाय में तब्दील हो गई है, जिसका ध्यान मुनाफे पर केंद्रित है।



ओपनएआइ को वर्तमान में अपने उत्पादों की सुरक्षा से संबंधित कई मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह बदलाव खबर बनने लायक है। ओपनएआइ ने 'सोरा' नाम के एक

वीडियो कृत्रिम मेधा एप का भी निर्माण किया है। कंपनी की स्थापना 2015 में एक गैर-लाभकारी वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। इसका मूल उद्देश्य धन कमाना नहीं था, बल्कि अपने निष्कर्षों को सांख्यिक और रायल्टी-मुक्त बनाकर समाज को लाभ पहुंचाना था। अपने एआइ माडल के विकास के लिए आवश्यक धन जुटाने के वास्ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सैम आल्टमैन के नेतृत्व में ओपनएआइ ने 2019 में एक लाभ-आधारित सहायक कंपनी बनाई।

माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू में इस उद्यम में एक अरब अमेरिकी डालर का निवेश किया। 2024 तक यह राशि 13 अरब अमेरिकी डालर से अधिक हो गई। इसके बदले में, माइक्रोसॉफ्ट को भविष्य के मुनाफे का एक हिस्सा देने का वादा किया गया था, जो शुरुआती निवेश के 100 गुना तक सीमित था।



जानें-समझें

कृत्रिम मेधा सम्मेलन

भारत के लिए क्यों अहम है यह मौका

जनसत्ता संवाद

यह साल कृत्रिम मेधा के लिए निर्णायक माना जा रहा है। दुनिया तकनीकी बढ़त की नई होड़ में दिख रही है। भारत कृत्रिम मेधा पर वैश्विक सम्मेलन - '2026 एआइ इंपैक्ट समिट' की मेजबानी ऐसे समय में कर रहा है, जब वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी तेज हो रही है। एआइ आज प्रमुख और तेजी से व्यापक होती जा रही तकनीक है। वर्ष 2029 तक 'डेटा स्टोरेज, कंप्यूटेशनल क्षमता और ऊर्जा आवश्यकताओं' समेत इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे में लगभग तीन ट्रिलियन डालर का निवेश होने का अनुमान है। अलबत्ता, एआइ के सामाजिक-आर्थिक लाभों को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। भारत में हो रहे सम्मेलन में इनको लेकर रास्ता ढूँढ़ने की कोशिश की जाएगी।

एजीआइ : मिथक या हकीकत

कृत्रिम मेधा की दुनिया में अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद 'आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस' (एजीआइ) के जल्द आने के दावे भ्रामक हैं। एजीआइ को एक ऐसी एआइ के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक समझदार वयस्क व्यक्ति की प्रतिभा और दक्षता से मेल खाता है। इसमें तर्क, स्मृति और बोध शामिल हैं। कृत्रिम मेधा प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए उन मापदंडों को इस्तेमाल किया है जो मानवीय तर्क पर भी खरे उतरते हैं। अक्टूबर 2025 में, एरिक स्मिथ और योशुआ बेंगियो सहित विभिन्न क्षेत्रों के 30 से अधिक प्रसिद्ध एआइ विशेषज्ञों ने एजीआइ की सटीक परिभाषा विकसित करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। उन्होंने मानव बुद्धि को दस प्रमुख संज्ञानात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया है जिसमें तर्क, स्मृति और बोध शामिल हैं।

बाजार में होड़

विश्व के अग्रणी 'लार्ज लैंग्वेज माडल्स' (एलएलएम) के बीच प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है। एलएलएम को शक्ति प्रदान करने के लिए जरूरी संगणन क्षमता की असीमित मात्रा वर्तमान भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में नवीनतम चुनौती बनकर उभरी है। एआइ संगणन आपूर्ति श्रृंखला में, अंतरराष्ट्रीय बाजार



(फाइल फोटो)



कृत्रिम मेधा का विकास जन-केंद्रित और समावेशी होना चाहिए। एआइ संसाधनों तक लोगों तक पहुंच होनी चाहिए।

भारत केवल भागीदार नहीं, बल्कि एआइ युग के नियमों, मानकों और अवसरों को आकार देने वाला प्रमुख निर्माता बनना चाहता है। - एस कृष्णन, सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) सचिव



कृत्रिम मेधा एक जटिल क्षेत्र है, और इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि, सही मार्गदर्शन के साथ इसमें दुनिया बदलने की क्षमता है। यह सामाजिक और मानवीय प्रगति की अगली पीढ़ी को बढ़ावा देगा, जिसे 'बुद्धिमान प्रगति' कहा जा सकता है। - राहुल बत्रा, प्रौद्योगिकी मामलों के विशेषज्ञ

का केंद्रीयकरण बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी कंपनी एनवीडिया की वैश्विक चिप बाजार में लगभग 80-95 फीसद की हिस्सेदारी है। अमेरिकी 'हाइपरस्केल क्लाउड' प्रदाता एनवीडिया के राजस्व का 40 फीसद और वैश्विक 'क्लाउड कंप्यूटिंग' बाजार का 70 फीसद हिस्सा रखते हैं।

भारत की स्थिति

भारत का विशाल और विविध बाजार, कृत्रिम इंजीनियरिंग प्रतिभा, अंग्रेजी में कुशल कार्यबल, डेटा संप्रभुता और डिजिटल ढांचा- एआइ के लिए आकर्षक स्थान बनाता है। सरकार एआइ क्षेत्र में आ रहे बदलावों के हिसाब से नियम बना रही है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनुकूल साबित हो सकते हैं। वर्ष 2025 के अंत तक गुगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन समेत बड़ी अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भारत में 67.5 अरब डालर का निवेश किया है। आम बजट 2026 से पहले पेश किया गया

सुरक्षा संबंधी चिंताएं

एरिक स्मिथ समेत कई आलोचकों ने लंबे समय से एआइ के संभावित नुकसानों के बारे में भी चेतावनी दी है। एरिक स्मिथ गुगल के पूर्व सीईओ (2001-2011) हैं। उनकी सलाह को एआइ में वैश्विक असमानता के लिहाज से अहम माना जाता है। एरिक स्मिथ अब 'दुष्ट एआइ' से उत्पन्न जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए सुरक्षा उपायों की सक्रिय रूप से वकालत करते हैं। स्मिथ के अलावा माट्टियाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर योशुआ बेंगियो ने स्वायत्त एआइ एजेंटों से संबंधित चिंताओं को उजागर किया है। योशुआ बेंगियो को 'एआइ का गाइडफादर' भी कहा जाता है। इन दोनों का कहना है कि उन्नत एआइ माडल गुप्त रूप से गलत लक्ष्यों का पीछा करता है। ये कमजोरी उन एआइ माडल्स में देखी जा रही है, जो चैटबॉट और एजेंट जैसे उपकरणों का आधार हैं।

भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भी इसी दृष्टिकोण को दोहराता है। हालांकि, इसके साथ ही यह चेतावनी भी देता है कि भारत को 'एप्लिकेशन-आधारित नवाचार, घरेलू डेटा का उत्पादक उपयोग, मानव पूंजी की प्रचुरता और सार्वजनिक संस्थानों के विकेंद्रीकृत प्रयासों के समन्वय की क्षमता' को प्राथमिकता देनी चाहिए।

भारत की 1.2 अरब डालर की कार्ययोजना

सबसे ज्यादा काम उन्नत सेमीकंडक्टर चिप, एआइ संगणन क्षमता और एआइ माडल की तैनाती में किए जाने हैं। भारत का लगभग 1.2 अरब डालर का इंडियाएआइ मिशन उसके गंभीर इरादे का संकेत देता है। ये राशि लगभग उतनी ही है, जितना ओपनएआइ जैसी कोई अमेरिकी कंपनी छह महीने में खर्च करती है। संप्रभु, समावेशी और उपयोग-केंद्रित इकोसिस्टम के उद्देश्य से 12 स्वदेशी माडल के साथ भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके बावजूद भारत को अभी भी अपने मूल ऊर्जा और डेटा ढांचे को बढ़ाने की जरूरत है।

व्यक्तित्व

सतेंद्र : कुक जलडमरूमध्य को पार करने वाले पहले एशियाई पैरा तैराक

जनसत्ता संवाद

भारत के सतेंद्र सिंह लोहिया न्यूजीलैंड में कुक जलडमरूमध्य को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा तैराक बन गए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले 38 वर्षीय लोहिया को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

लोहिया ने अपनी कामयाबी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'ऐतिहासिक उपलब्धि। न्यूजीलैंड में कुक जलडमरूमध्य पर जीत। दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक न्यूजीलैंड के कुक जलडमरूमध्य को अपनी टीम के साथ सफलतापूर्वक पार करने के बाद आज मैं बेहद भावुक और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पहली बार एशिया के किसी पैरा तैराक ने इसे पार किया है।'

वे जनवरी के तीसरे सप्ताह में न्यूजीलैंड पहुंचे और वहां उन्होंने बेहद ठंडे पानी में कड़ा अभ्यास किया। उन्होंने नौ घंटे और 22 मिनट में 23.6 किलोमीटर तैराक यह उपलब्धि हासिल की। उनकी कामयाबी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 'पद्मश्री और तेजजिंग नोंगें राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक सतेंद्र एस लोहिया ने दुनिया के सबसे कठिन समुद्री मार्गों में से एक न्यूजीलैंड के कुक जलडमरूमध्य को सफलतापूर्वक पार करके इतिहास रच दिया है।' उन्होंने कहा, 'वह कुक जलडमरूमध्य



दूरी 12 घंटे 26 मिनट में पूरी की। इसके बाद उन्होंने 2019 में अमेरिका का कैटलीना चैनल पार किया। इसके बाद मुंबई के 'स्विम सर्किट' को पार किया, जो करीब 33 किलोमीटर लंबा है। उसे पांच घंटे 42 मिनट में पूरा किया। उन्हें वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2019 में उन्हें तेजजिंग नोंगें राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए चुना गया, जो भारत सरकार द्वारा साहसिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया।

चिंतन

भारतीय वायुसेना को नई मजबूती देगी राफेल डील

भारत और फ्रांस के बीच प्रस्तावित 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील केवल एक रक्षा खरीद नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की सामरिक सोच का संकेत है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान जिस 3.60 लाख करोड़ रुपये के संभावित समझौते पर चर्चा हो रही है, वह भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में गुणात्मक बढ़ोतरी कर सकता है। दो मोर्चों चीन और पाकिस्तान की चुनौती के बीच यह सौदा रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास करीब 29 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हैं, जबकि आधिकारिक मंजूरी 42.5 स्क्वाड्रन की है। यानी लगभग 13 स्क्वाड्रन की कमी पहले से ही चिंता का विषय है। आने वाले दशक में जगुआर, मिग-29 और मिराज-2000 जैसे विमानों के चरणबद्ध सेवानिवृत्त होने से यह अंतर और बढ़ सकता है। ऐसे में नई पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की तत्काल आवश्यकता स्पष्ट है। राफेल पहले ही अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। हालिया अभियानों में इसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता, अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने वायुसेना को सामरिक बढ़त दिलाई है। वर्तमान में भारत के पास एफ-3 मानक के राफेल हैं, जो 4.5 जेनरेशन के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। प्रस्तावित डील के तहत एफ-4 और बाद में एफ-5 श्रेणी के 'सुपर राफेल' मिलने की संभावना है। यूरोपीय मानकों के अनुसार एफ-5 को छोटी पीढ़ी के जेट की श्रेणी में रखा जा रहा है। यदि यह समयसीमा के अनुसार 2030 के बाद मिलते हैं, तो भारत फ्रांस के बाद इन अत्याधुनिक विमानों का प्रमुख ऑपरेटर बन सकता है। इस डील का एक और महत्वपूर्ण पहलू 'मेक इन इंडिया' है। कुल 114 विमानों में से 18 सीधे उड़ान-योग्य अवस्था में मिलेंगे, जबकि 96 का निर्माण भारत में होगा। इनमें लगभग 60 प्रतिशत कलपुर्जों का स्वदेशीकरण प्रस्तावित है। इससे भारतीय एयरोस्पेस उद्योग को नई गति मिलेगी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और हजारों रोजगार सृजित होंगे। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। हालांकि, कुछ सवाल भी उठते हैं। महत्वपूर्ण हैं। चीन पहले ही छोटी पीढ़ी के विमानों के विकास में आगे बढ़ चुका है। ऐसे में भारत को केवल प्लेटफॉर्म खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास पर भी समान बल देना होगा। क्या 42.5 स्क्वाड्रन का लक्ष्य अगले दशक में पूरा हो पाएगा? क्या समय पर आपूर्ति और लागत नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा? ये वे प्रश्न हैं जिन पर सरकार और रक्षा प्रतिष्ठान को पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी रक्षा सहयोग से कहीं व्यापक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच वार्ता केवल विमानों की खरीद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उभरती प्रौद्योगिकियों, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक भू-राजनीति पर भी केंद्रित होगी। कुल मिलाकर 114 राफेल की संभावित डील वायुसेना के लिए 'ऑक्सीजन' साबित हो सकती है, लेकिन इसे दीर्घकालिक सामरिक दृष्टि से जोड़ना आवश्यक है। मजबूत वायुशक्ति केवल युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि शांति और संतुलन की गारंटी भी होती है।

सारा संसार



मसाली अम्मन मंदिर मसाली देवी को समर्पित एक मंदिर है, जिन्हें शक्ति देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह कोयंबटूर जिले के अजनालगाई के पंचायत शहर में स्थित है, इसे अरुणमिगु मसाली अम्मन मंदिर या अजनालगाई मसाली अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर बेहद ही आध्यात्मिक है, जिस वजह से लोग यहां खिंचे चले आते हैं।

सरोकार

योगेंद्र माथुर



शादी ब्याह में आर्थिक संपन्नता के प्रदर्शन की होड़, अन्न का अपमान

विगत दिनों जब शादी-ब्याह का सिलसिला पुनः चालू हुआ तो मुझे भी एक के बाद एक कई शादियों में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। शादी-ब्याह की इस धूमधाम में जाहिर है हमेशा की तरह ही ऐश्वर्य और विलासिता के भरपूर दर्शन हुए। 'नेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे?' की तर्ज पर होने वाली होड़ में आयोजक अपनी क्षमता से अधिक पैसा खर्च करते नजर आए। परिणय स्थल यथा- गार्डन, धर्मशाला, लॉज-होटल की चमक बढ़ाने की गरज से टेबल से विद्युत् साज-सज्जा पर पैसा पानी की तरह बहता दिखाई दिया। समारोह पांडाल की साज-सज्जा तो ठीक भोजन को भी अपनी सामर्थ्य के प्रदर्शन का माध्यम बना लिया गया हो, ऐसा लगा। भोजन में कुछ नया या नई वैरायटी परसने की होड़ में निर्मित व्यंजनों का आंकड़ा 56 के भी पार जाता नजर आया। सभी व्यंजनों के नाम तो शाब्द आयोजक को भी मालूम नहीं होंगे। अब भला खाने वाले 4-5 व्यंजनों से अधिक का स्वाद चख पाएं, न चख पाएं या फिर प्लेट में छोड़ते नजर आए, आयोजक की आर्थिक संपन्नता का प्रदर्शन तो हो ही गया। कहने या बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे शादी समारोह में धन के साथ अन्न का भी अपव्यय होना तय है। आप सोचिए, क्या कोई मेहमान चाहेकर भी भोजन के अपव्यय को रोक पाएगा? समझदारी दिखाकर वह इतने अधिक पकवानों में से कुछ का स्वाद न भी चखे अथवा प्रत्येक पकवान का एक या आधा टुकड़ा ले तो भी कुछ मात्रा में ही सही भोजन का अपव्यय निश्चित है। हालांकि सभी मेहमानों से इतनी समझदारी की उम्मीद लगाना भी बेमानी ही होगा। हमारे देश में जब से 'बुफे' संस्कृति का विस्तार हुआ है, भोजन का अपव्यय भी बढ़ा है। इसमें बुफे संस्कृति की बुराई जैसी कोई बात नहीं है। कमी हममें ही है क्योंकि इसके सही तौर-तरीकों के पालन के संस्कार हमारे यहां नहीं पनप पाए हैं। प्रायः शादी समारोह में यही देखने में आता है कि लोग प्लेट में खाना लेते समय, बाद में मिलेगा या बचेगा कि नहीं की सोच के चलते अपनी प्लेट में एक साथ अधिकाधिक खाद्य सामग्री रख तो लेते हैं किंतु बाद में अधिकांश लोग 'जूठन' के रूप में छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में 56 या अधिक पकवान बन जाए तो भोजन की बर्बादी को कौन रोक सकता है? हमारी संस्कृति में अन्न के एक-एक दाने का महत्व बताया गया है और अन्न को देवतुल्य माना गया है। ऐसी स्थिति में शादी समारोह में भोजन का 'जूठन' के रूप में फिकना क्या अन्न का तिरस्कार या देवता का अपमान नहीं है? जिस देश में बच्चे भुखमरी व कुपोषण का शिकार बन कर असमय दम तोड़ रहे हों, उस देश में अन्न को अपनी सम्पन्नता के प्रदर्शन का माध्यम बनाना कहां तक उचित है? वैवाहिक आयोजकों के माध्यम से दूसरों की अपेक्षा अपने को कहीं अधिक बड़ा, समर्थ, सक्षम व सम्पन्न बताने की यह अंधी होड़ निश्चित ही बेहद खतरनाक है। उधार का धी पीकर अपनी सम्पन्नता दर्शाने की प्रवृत्ति तो निश्चित ही व्यक्ति, परिवार व समाज को पतन की ओर ले जाने वाली है। वर्तमान चार दिन की चकाचौंध भविष्य को गहरे अंधकार में धकेलने वाली है। अंधानुकरण की इस होड़ से हमें समाज को बचाना होगा और यह हम तभी कर पाएंगे या समाज को कोई संदेश दे पाएंगे, जब हम अपने से ही इसकी शुरुआत करेंगे। बेहतर होगा कि हम हमारे घर-परिवार में होने वाले वैवाहिक आयोजन सावधानपूर्वक व गरिमा के साथ आयोजित करें और विवाह समारोह की चकाचौंध पर होने वाले खर्च से 'परिणय-सूत्र' में आबद्ध हो रहे जोड़े के भविष्य को रोशन करें।

(लेखक रमेश रमेशकर हैं, ये उनके अज्ञेय विचार हैं।)



मुद्दा

रोहित माहेश्वरी

20 फरवरी से लागू होने जा रहे इन नियमों के तहत अब एआई से तैयार किए गए फोटो और वीडियो पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फेक कंटेंट को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी गई है। अब साइबर अपराधी कंपनियों की तरह संगठित ढांचे में काम कर रहे हैं। इनके पास भर्ती करने वाली टीम, वेतन और प्रमोशन देखने वाले लोग और यहां तक कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी होती है। एआई ने साइबर अपराध को पहले से कहीं ज्यादा संगठित तेज और खतरनाक बना दिया है। वैसे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की संख्या और कंटेंट की मात्रा इतनी अधिक है कि केवल नियमों के सहारे नियंत्रण करना आसान नहीं होगा। इसके लिए तकनीकी निगरानी तंत्र को मजबूत, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना और उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अब एआई कंटेंट की होगी बेहतर निगरानी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जहां दुनिया को तेज और स्मार्ट बनाया है, वहीं इसके दुरुपयोग ने भी गंभीर चिंता पैदा कर रखी है। डीपफेक वीडियो, फर्जी तस्वीरें और एआई जनित भ्रामक सामग्री न केवल लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि साइबर उगी और सामाजिक भ्रम का कारण भी बन रही हैं। इन खतरों के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में किए गए हालिया संशोधन को डिजिटल दुनिया में बढ़ती चुनौतियों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। आगामी 20 फरवरी से लागू होने जा रहे इन नियमों के तहत अब एआई से तैयार किए गए फोटो और वीडियो पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही फेक कंटेंट को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी गई है। नए प्रावधानों के तहत एआई कंटेंट में स्थायी मेटाडेटा और डिजिटल पहचान चिह्न जोड़ने की अनिवार्यता भी तय की गई है, ताकि ऐसे कंटेंट को पहचान आसानी से की जा सके। यह बदलाव डिजिटल पारदर्शिता और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा अब सबसे बड़ी चुनौती है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, जैसे कि चैटजीपीटी की मदद से नकली आधार और पैन कार्ड बनाए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट ने एआई के संभावित दुरुपयोग की क्षमता के बारे में नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। एक नए सर्वे में 51 फीसदी ब्रिजनेस लीडर्स ने इसे प्राथमिक जोखिम माना। 'फिक्की-ईवाय रिस्क सर्वे 2026' की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। इसमें डिजिटल युग के बढ़ते खतरों पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी जोखिम अब सीधे कंपनी के कामकाज से जुड़ गए हैं। सर्वे के अनुसार, 61 फीसदी लोग साइबर हमलों से डरे हुए हैं। डेटा चोरी और धोखाधड़ी को 57 फीसदी ने बड़ा जोखिम माना। लगभग 47 फीसदी कंपनियों इन आधुनिक खतरों से निपटने में नाकाम हैं। साइबर हमलों से कंपनियों की प्रतिष्ठा और वित्त पर असर पड़ता है। डिजिटल बदलाव कंपनियों की प्रतिस्पर्धी स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। यह सर्वे 137 सीईओ और सीनियर डिजिटीज-मेकर्स पर आधारित है। इसमें 21 फीसदी प्रतिभागी टेक्नोलॉजी सेक्टर से थे। प्रोफेशनल सर्विसेज दूसरे नंबर पर। साइबर अटैक अब सिर्फ आईटी मुद्दा नहीं। यह ऑपरेशनल कंटिन्यूटी से जुड़ा है। 61 फीसदी लीडर्स मानते हैं कि साइबर हमले वित्तीय और रेपुटेशनल खतरा है। तेज टेक्नोलॉजिकल बदलावों को 61 फीसदी कंपनियों प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाला मान रहे हैं। सर्वे के अनुसार, आज के दौर में एआई एक 'दोधारी तलवार' बन गया है। करीब 60 फीसदी विशेषज्ञों का मानना है कि

तकनीकी पिछड़ापन घातक है। सही समय पर नई तकनीक न अपनाया नुकसानदेह हो सकता है। वहीं, 54 फीसदी लोग एआई के पृथक्करण और गवर्नेंस संबंधी जोखिमों से चिंतित हैं। इन जोखिमों का प्रबंधन अभी भी प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है। ग्लोबल साइबरपीस समिट 2026 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार 2024-2025 के दौरान दर्ज साइबर हमलों में एआई और ऑटोमेशन का व्यापक इस्तेमाल देखने को मिला है। अब साइबर अपराधी किसी छोटे गैंग की तरह नहीं, बल्कि कंपनियों की तरह संगठित ढांचे में काम कर रहे हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य-पूर्व और भारत के कुछ हिस्सों से संचालित ये नेटवर्क अलग-अलग विभागों में बंटे हुए हैं। इन गिरोहों



के पास भर्ती करने वाली टीम, वेतन और प्रमोशन देखने वाले लोग और यहां तक कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी होती है। ये टीम टेक्नोलॉजी की कर्मियों और इसानी व्यवहार की कमजोरियों को खोजकर उनका फायदा उठाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में साइबर अपराध से दुनिया को लगभग 10.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान था, जो इस साल करीब 12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंकों का दावा है कि अब लगभग 80 प्रतिशत साइबर हमलों में किसी न किसी रूप में एआई की भूमिका है। एआई का इस्तेमाल अब डीपफेक तकनीक में भी हो रहा है।

डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में अपराधी किसी प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी का चेहरा और आवाज नकली तरीके से दिखाकर पीड़ित को डराते हैं, जिससे वह खुद को असली अधिकारी से बात करते हुए समझता है। साइबर अपराध में अब टिपल एक्सटॉर्शन मॉडल भी सामने आया है। इसमें पहले नैसमवेयर से डेटा लॉक किया जाता है फिर उसे लॉक करने की धमकी देकर पैसे वसूलें जाते हैं। इसके अलावा क्राइम-एस-ए-सर्विस का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें संगठित गिरोह उन लोगों को भी अपराध की सुविधा देते हैं जिनके पास तकनीकी जानकारी नहीं होती।

यानी पैसे दो और तैयार साइबर क्राइम सेवा लो। इस तरह के मामलों में कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तक उगी का शिकार हो चुके हैं। साफ है कि एआई ने साइबर अपराध को पहले से कहीं ज्यादा संगठित तेज और खतरनाक बना दिया है। वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तो कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन इन्हें किस हद तक इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए, इसके लिए नियम-कानूनों का अभाव है। हमारा देश और दुनिया भी एआई के बढ़ते कदमों और उसके प्रभावों को लेकर गंभीर है। इसी क्रम में दिल्ली के भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' का आगाज हो रहा है। 20 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में दुनिया की 300 से ज्यादा कंपनियों भविष्य की तकनीक दिखाएंगी। खेती से लेकर सेहत तक, एआई आपकी जिंदगी को कैसे आसान बनाएगा, इसकी पूरी झलक यहां देखने को मिलेगी। आईटी के नए नियमों का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब एआई से बने कंटेंट को छिपाना आसान नहीं रहेगा। लेबलिंग व डिजिटल पहचान चिह्न से आम व्यक्ति यह समझ सकेगा कि उसके सामने मौजूद सामग्री वास्तविक है या तकनीक से तैयार की गई है। इससे सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक अभियानों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। चुनाव, सामाजिक मुद्दों और संवेदनशील घटनाओं के दौरान यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी सुरक्षित रखने में सहायक होगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। इन तमाम बातों के बीच सवाल यह भी है कि सिर्फ नियम-कायदे बानावा ही काफी नहीं, बल्कि इन्हें सख्ती से लागू करना भी जरूरी है। वैसे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की संख्या और कंटेंट की मात्रा इतनी अधिक है कि केवल नियमों के सहारे नियंत्रण करना आसान नहीं होगा। इसके लिए तकनीकी निगरानी तंत्र को मजबूत करना, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना और उल्लंघन की स्थिति में त्वरित दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। क्योंकि यदि नियमों का पालन ढीला रहा, तो इनका उद्देश्य आभूरा रह जाएगा। इसके साथ ही नगरिकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है।

(लेखक रमेश रमेशकर हैं, ये उनके अज्ञेय विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

आनंद आपके भीतर है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं



संकलित

दर्शन

कल्पना क्या है और सच्चाई क्या है! इसे समझने के लिए आपको जड़ का मजबूत होना जरूरी है। सारी कल्पनाएं आपके अंदर हैं। यह कल्पना नहीं है, यह सच है। कल्पना में डूबना बड़ा आसान है, सच्चाई को जानना बहुत मुश्किल है। जिसको आप खोज रहे हैं, वह आपके अंदर है। उसे जानिए, पहचानिए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि उसमें सबकुछ है। जो आपके भीतर है, वह है शांति। किसी चीज का न होना शांति नहीं है। किसी चीज का होना शांति है। जब मनुष्य खुद को जानेगा, खुद को समझेगा, तब उसके जीवन में शांति होगी। जैसे भोजन खा लेने पर भूख खत्म होती है, उसी प्रकार खुद को जान लेने पर तृष्णा मिट जाती है। शांति मिल जाती है। सोचें कि यह शरीर आपको क्यों मिला है? जिन तत्वों से शरीर बना है, वे सारे तत्व वहीं वापस चले जाएंगे जहां से ये आये थे। जिस तरह पानी, पानी में मिल जाता है। सारी चीजें प्रकृति में वृत्त जाएंगी। क्या समझते हैं आप कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस धरती का वजन बढ़ता है! या जब कोई मर जाता है तो इस धरती का वजन कम होता है! वजन न तो बढ़ता है न कम होता है। क्योंकि जिन चीजों से आप बने हुए हैं वे तो अभी यहीं हैं। परंतु क्या आपने उस चीज को जाना, समझा जो आपके शरीर के अंदर है? इसे जान गए, पहचान गए, फिर आनंद ही आनंद है। आपका नाम आपके शरीर का नाम है। नाम कमाने से क्या होगा। नाम नहीं, ज्ञान कमाइए। आनंद कमाइए। ये आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जहां जाएंगे, वहां ले जा सकते हैं।



संकलित

प्रेरणा

आज की पाती

स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग

कुछ कथित उच्च शिक्षित, जाहिल, गंवार लोग जब सार्वजनिक रूप से (विशेषकर सोशल मीडिया पर) सड़कपाक व्यवहार करने लगते हैं तो ऐसे मूर्ख लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसी खत्म हो जाती है। कला और विचार प्रकट करने की आजादी के नाम पर किसी को भी देश, समाज में अश्लीलता फैलाने के उद्देश्य को दुनिया का कोई भी सभ्य-सुसंस्कृत सभियान कभी कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। ऐसे सदीया अवांछित, अधिग्र, समाज विरोधी कार्य करने वालों का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करने वाले सभी आधुनिक मनोरोगी भी उतने ही बड़े अपराधी माने जाने चाहिए। सिर्फ मजक के नाम पर ही नहीं, कई बार गंभीर मुद्दों में प्रदर्शन करते हुए भी कुछ पांडकसर पर दुर्जन लोग गंदी, अश्लील, अहं, अशोभनीय बातें करते हैं। आजादी का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए।

- सदीय सरकार, बिलासपुर

अंतर्मन



करंट अफेयर

महिला के गरिमा को ठोस एनआरआई को मिली जेल

सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक महिला की गरिमा को ठोस पहुंचाने के इरादे से उसके खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग करने के जुर्म में पांच महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। 'द स्ट्रेट्स टाइम्स' अखबार में सोमवार को प्रकाशित खबर में यह जानकारी दी गई। खबर के मुताबिक, शुक्रवार को सजा के एलान के दौरान अदालत ने कहा कि 42 वर्षीय ओम कुमार राय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। खबर में कहा गया है कि अदालती दस्तावेज से पीड़िता का नाम और घटनास्थल का विवरण हटा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि राय 22 वर्षीय पीड़िता के पिता का सहकर्मी है और वह 17 जून 2025 को तड़के पीड़िता से मिलने पहुंचा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राय पीड़िता को बातचीत के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता को एक धक्का देकर उसके घंगुल से भागने में सफल रही और अपने माता-पिता को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद उन्होंने उसी दिन सुबह नौ बजे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अभियोजकों ने राय को पांच से छह महीने की जेल की सजा देने का अनुरोध किया था।



सबसे आम स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर 'वैस्कूलर डिमेंशिया' (मस्तिष्क में रून का प्रवाह धीमा पड़ने के कारण होने वाला डिमेंशिया) और 'लेवी बॉडी डिमेंशिया' (मस्तिष्क में 'लेवी बॉडी' नाम के प्रोटीन के थक्के जमने से होने वाला डिमेंशिया) के मामले भी सामने आते हैं। डिमेंशिया में तंत्रिका-तंत्र की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे उनमें संचार की प्रक्रिया प्रभावित होती है और व्यक्ति को भ्रम, भूलने की बीमारी और व्यवहार में बदलाव की शिकायत सता सकती है।

ऑफ बीट

नियमित व्यायाम डिमेंशिया से बचाव में है कारगर

जैसे-जैसे डिमेंशिया के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे-वैसे रोकथाम के उपाय जानने की दिलचस्पी में भी इजाजा हो रहा है। मीडिया में आई खबरों में नियमित व्यायाम, स्वस्थ खानपान, दिमागी कसरत और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी को डिमेंशिया के जोखिम में कमी लाने के लिए कारगर बताया गया है। डिमेंशिया तंत्रिका-तंत्र से जुड़ा एक विकार है, जिसमें याददाश्त, सोचने-समझने एवं फैसले लेने की शक्ति और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। अल्जाइमर (मस्तिष्क के अंदर और उसके आसपास की कोशिकाओं में फमिलॉयड नाम के प्रोटीन के थक्के जमने से होने वाला डिमेंशिया) को डिमेंशिया का सबसे आम स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर 'वैस्कूलर डिमेंशिया' (मस्तिष्क में रून का प्रवाह धीमा पड़ने के कारण होने वाला डिमेंशिया) और 'लेवी बॉडी डिमेंशिया' (मस्तिष्क में 'लेवी बॉडी' नाम के प्रोटीन के थक्के जमने से होने वाला डिमेंशिया) के मामले भी सामने आते हैं। डिमेंशिया में तंत्रिका-तंत्र की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे उनमें संचार की प्रक्रिया प्रभावित होती है और व्यक्ति को भ्रम, भूलने की बीमारी और व्यवहार में बदलाव की शिकायत सता सकती है।

टैंड



देश तेजी से प्रगति कर रहा

यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडिया एआई इन्वैस्ट समिट के लिए दुनियाभर से लोग भारत आ रहे हैं। इससे हमारे युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है। यह अक्षर इश बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में आज दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में ₹857 करोड़ की लागत से निर्मित 'रोफ सिटी प्रोजेक्ट' का लोकार्पण किया। साथ ही, ₹368 करोड़ की लागत से रोशाल सेल के इटीवेटेड हेडक्वार्टर का इ-इंफ्रान्वायस किया। -अमित शाह, गृहमंत्री

शंकर से प्रेरणा लेती है सेना सैनिकों के अंदर की भावना हमारी संस्कृति से, महावन शिव की प्रेरणा से आती है। इर से सनाज लंबे समय तक सुरक्षित नहीं हो सकता। एक निरुद्ध सनाज ही मजबूत राष्ट्र बना सकता है। निरुद्धता आध्यात्मिकता से आती है। -राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री

गिग वर्कर को मिले सुरक्षा कुछ दिन पहले जनसंघ ने गिग वर्करों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई। बतवावित से साफ हुआ कि गिग अर्थव्यवस्था के फायदे मजदूरों तक पहुंचाने के लिए मजबूत और जिम्मेदार सरकारों की आवश्यकता है। महिला गिग वर्कर देवेंद्र शोभा का शिकार है, आर्थिक अक्षरता के साथ-साथ सनमान और सुरक्षा का अभाव। -राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

आपने विचार हरिभूमि कार्यालय टिकरपापरा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फेसबुक : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

लैंड फॉर जॉब्स घोटाला : लालू समेत 46 पर आरोप तय, 9 मार्च से शुरू होगा रोजाना ट्रायल

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

बहुचर्चित 'लैंड फॉर जॉब्स' मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 46 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने 9 जनवरी को आदेश पारित करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप निर्धारित किए थे। अब मामले में 9 मार्च से 28 मार्च तक प्रतिदिन सुनवाई कर अभियोजन साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे।

क्या है पूरा मामला

सीबीआई द्वारा दर्ज इस मामले में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे के विभिन्न जोन में गुप-डी के पदों पर 'सब्सिडीयूट' के रूप में नियुक्ति के बदले जमीन या अन्य



संपत्ति ली गई। आरोप है कि यह लेन-देन लालू प्रसाद यादव के परिजनों और सहयोगियों के माध्यम से किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप

पूर्व आईएस आरके महाजन भी 46 आरोपियों में शामिल

तय किए गए हैं। अदालत द्वारा जिन 46 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, उनमें लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके परिवार के पांच सदस्य—राबड़ी देवी, मौसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और हेमा यादव—शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त तीन करीबी सहयोगी—भोल यादव (तत्कालीन विशेष अधिकारी), आर.के. महाजन (तत्कालीन निजी सचिव) और प्रेम चंद गुप्ता (राज्यसभा सांसद, राजद)—का नाम भी आरोपियों में है। एक निजी कंपनी 'ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड', जो वर्तमान में लालू परिवार से संबंधित बताई जा रही है, को भी आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा रेलवे के तत्कालीन महप्रबंधक, सब्सिडीयूट अभ्यर्थी और अन्य निजी व्यक्तियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

कई चार्जशीट दाखिल

सीबीआई ने इस प्रकरण में तीन मुख्य चार्जशीट और दो पूरक चार्जशीट अदालत में दाखिल की थीं। अदालत ने दस्तावेजों और तर्कों पर विचार करने के बाद आरोप तय करने का आदेश दिया।

आरोपियों ने नहीं माना दोष

अदालत ने 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने और आरोप पढ़कर सुनाने की तिथियां तय की थीं। इस दौरान लालू, उनके परिवार के सदस्य और अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए और सभी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार किया। सभी आरोपियों ने दोषी नहीं होने की दलील दी।

9 मार्च से रोजाना सुनवाई

विशेष अदालत ने अब मामले को अभियोजन साक्ष्य के लिए 9 मार्च से 28 मार्च 2026 तक प्रतिदिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस दौरान सीबीआई अपने गवाह और साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश करेगी। राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मामले पर अब सबकी निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को प्रमाणित करने का प्रयास करेगा।

भूपेन ने अचानक दिया इस्तीफा, 4 घंटे बाद पलटे और लिया वापस



गुवाहाटी। असम की सियासत में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा एक बड़ा तमाशाबाजी सामने आई। इसने कांग्रेस और भाजपा दोनों को सुखियों में ला दिया। पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पहले पार्टी से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलचल मचा दी और फिर महज 4 घंटे के भीतर यू-टर्न लेते हुए कांग्रेस में ही बने रहने का ऐलान कर दिया। सोमवार सुबह भूपेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे को अपना इस्तीफा भेजा। उन्होंने पार्टी में अनेदखी और उचित सम्मान न मिलने की बात कही। इस्तीफे की खबर बाहर आते ही असम कांग्रेस में खलबली मच गई। बैठकों का दौर चला, फोन कॉल्स हुए और शाम होते-होते बोरा ने इस्तीफा वापस लेने का फैसला कर लिया।

भूपेन ने नेतृत्व पर साइडलाइन करने का लगाया था आरोप

इस्तीफा वापस लेते वक्त भूपेन ने कहा कि मैंने अभी इस बारे में अपने परिवार से बात नहीं की है। इसलिए मुझे फैसला लेने के लिए और समय चाहिए। 32 वर्षों तक कांग्रेस की सेवा करने वाले भूपेन ने साइडलाइन करने का आरोप लगाया था। भूपेन ने 2021 से 2025 के बीच असम कांग्रेस संगठन की कमान संभाली थी। पिछले वर्ष पार्टी नेतृत्व ने बदलाव करते हुए उनकी जगह गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। सियासी अनुभव की बात करें तो बोरा असम विधानसभा में दो बार विधायक भी रह चुके हैं।

हाईकमान की देखल बनी निर्णायक

इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस हाईकमान की भूमिका निर्णायक रही। पार्टी के अनुसूचक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद भूपेन बोरा से बात की। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी पुष्टि की कि भूपेन बोरा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। हाईकमान ने उन्हें संगठन में अहम जिम्मेदारी देने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद मामला संभल गया।

एसआईआर की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने नाराजगी जताई

याचिकाकर्ता को खूब सुनाया आर्टिकल 32 का मजाक न बनाएं, हम तय करें कि आपके माता-पिता कौन हैं?

28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी

टीएमसी और ईसीआई में तकरार बढ़ी

मोहम्मद नोवाज ने याचिका दाखिल कर लगाई थी सुप्रीम कोर्ट से गुहार

एजेसी ►► नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस बार याचिका दाखिल कर एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने जमकर नाराजगी जताई है। खास बात है कि इस मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल की गुणमूल कांग्रेस सरकार और ईसी आई यानी भारत निर्वाचन आयोग में तकरार जारी है। मोहम्मद जिफरुल्लाह नोवाज ने याचिका दाखिल की थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लाजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट के इस्तेमाल को चुनौती दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आर्टिकल 32 में आप चाहते हैं कि हम यह तय करें कि आपके पिता, माता और आदि कौन हैं। यह आर्टिकल 32 याचिका का मजाक है।

बाबा खतरनाक की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बदरवाद वेणुगोपाल उर्फ बाबा खतरनाक की याचिका को खारिज कर दिया। इसमें वाराणसी में गंगा नदी के पानी की बिगड़ती गुणवत्ता को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता बाबा खतरनाक को संबंधित हाई कोर्ट में जाने की छूट दे दी।

जयपुर से शुरू होगी एआई किसान क्रांति, केंद्रीय मंत्री चौहान लांच करेंगे

हारिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 फरवरी को राजस्थान प्रवास पर रहेंगे। वे जयपुर में, देश भर के किसानों के लिए नया डिजिटल साथी 'भारत विस्तार' लांच करने जा रहे हैं। कृषि और किसानों को स्मार्ट बनाने यह एआई आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को फोन कॉल, चैटबॉट और आगे चलकर ऐप के जरिए मौसम, मंडीभाव, कीटरोग, मिट्टी, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर देगा। फेज 1 में यह सुविधा हिंदी व अंग्रेजी में शुरू होगी और महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचेगी। इसमें राज्यों के कृषि मंत्री व आईसीएआर, केवीके, कृषि विवि तथा अन्य कृषि संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से लाखों किसान वर्चुअली जुड़ेंगे। चौहान के साथ बड़ी संख्या में किसानों के अलावा मुख्य रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, रामनाथ ठाकुर, राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, सांसद, विधायक, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी भी होंगे।

भारतीय किसानों के हितों की बलि दी, ऊर्जा सुरक्षा से खिलवाड़ और देश की संप्रभुता के साथ आत्मनिर्भरता से किया समझौता

भारत के बाजार में बिकेगा, तो भारतीय किसानों की आजीविका संकट में आ जाएगी। उन्होंने सेब, संतरा, चेरी, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों के अमेरिका से आने को भी भारत के किसानों के लिए बेहद नुकसानदायक बताया। सुरजेवाला ने इस बात पर भी चिंता जताई कि यदि भारत में प्रोसेस्ड मक्का, ज्वार, सोयाबीन व अन्य कृषि उत्पाद आएं, तो उनका सीधा प्रभाव भारत की जैविक विविधता और बीज शुद्धता पर भी पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी सरकार ने पिछले दवाजे से भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति दे दी है। उन्होंने आगे बताया कि व्यापार समझौते में नॉन-ट्रेड बैरियर्स को हटाने का सीधा मतलब भारतीय किसान की सब्सिडी को हटाना व जीएम क्रॉप्स के आयात को मंजूरी देना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने किसानों को सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देता है। इसके विपरीत भारतीय किसानों को सीमित सहायता मिलती है, ऐसे में सुरक्षा उपायों में किसी भी प्रकार की और कमी उनके लिए हानिकारक होगी। उन्होंने पूछा कि अमेरिका से भारत आने वाले अतिरिक्त उत्पाद कौन से हैं, जिनका अभी खुलासा नहीं किया गया है? सुरजेवाला ने समझौते को भारत के कपास उत्पादक किसानों और टेक्सटाइल उद्योग के लिए भी खतरा बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश-अमेरिका व्यापार व्यवस्था के तहत बांग्लादेश अमेरिकी कपास व धागा आयात कर जो कपड़ा अमेरिका को निर्यात करेगा, उस पर अमेरिका में शुन्य प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसके उलट अमेरिका में भारत के निर्यात पर 18 प्रतिशत शुल्क लगेगा। उन्होंने कहा कि इसका प्रतिकूल असर भारत के कपड़ा उद्योग पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि भारत से बांग्लादेश को सालाना 24,550 करोड़ रुपए का कपास व धागा निर्यात होता है। जब बांग्लादेश अमेरिका से कपास व धागा मंगवाने लगेगा, तो भारत के कपास उत्पादक किसान व कपड़ा बनाने वाले कारखाने तबाह हो जाएंगे। उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गौरव के बयान का हवाला देकर कहा कि अब अमेरिकी कपास के भारत में निशुल्क आयात का दरवाजा भी खोल दिया गया है, जो किसान पर दोहरी मार की तरह है।

आधार ऐप डाउनलोड्स की संख्या 14 मिलियन के पार

आधार ऐप के जरिए एक मिलियन लोगों ने घर बैठे अपडेट किया मोबाइल नंबर

हरिभूमि ब्यूरो ►► नई दिल्ली

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नए आधार ऐप को लेकर आम जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐप को अपनाने की यह तेज गति सुरक्षित, डिजिटल और सुविधाजनक आधार सेवाओं के प्रति नागरिकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नए आधार ऐप ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक इसे लगभग 14 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। यह सफलता देश भर में आधार सेवाओं को अधिक सुलभ, उपयोगकर्ता के अनुकूल और तुरंत उपलब्ध कराने में इस ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। आधार ऐप एक नेक्स्ट-जेनरेशन का मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे आधार संख्या धारकों (एएनएच) को अपनी डिजिटल पहचान रखने, साझा करने, दिखाने और सत्यापित करने के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और गोपनीयता-केंद्रित तरीका प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एंड्रॉइड और एप्पल आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की जानकारी के अनुसार

28 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किए गए इस नए ऐप को औसतन प्रतिदिन 1,00,000 से अधिक लोग डाउनलोड कर रहे हैं। इस ऐप की बढ़ती उपयोगिता ने आधार सेवाओं को निवासियों के लिए घर बैठे ही सुलभ बना दिया है। अब तक यह ऐप 1 मिलियन निवासियों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने में मदद कर चुका है। वहीं 3,57,000 आधार धारकों ने ऐप के जरिए अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक या अनलॉक किया है। इसी तरह, लगभग 8,00,000 निवासियों ने नए ऐप का उपयोग करके अपना ई-आधार डाउनलोड किया है। इस ऐप में कई आधुनिक और उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं, जैसे प्रेजेंट्स के प्रूफ के तौर पर फेस वेरिफिकेशन, सिंगल क्लिक में बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को देखने की सुविधा और कॉन्टैक्ट डिटैल्स को आसानी से साझा करने के लिए QR-आधारित कॉन्टैक्ट कार्ड। सभी यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह आधार ऐप, दैनिक जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक है। इसके माध्यम से होटल में चेक-इन के दौरान ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटीटी (ओवीएसई) क्यूआर कोड स्कैनिंग, उम्र का सत्यापन, अस्पताल में भर्ती, कार्यक्रमों में प्रवेश और गिग वर्कर्स व सर्विस पार्टनर्स के सत्यापन जैसे कई कार्य सुगम हो गए हैं।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त कमल शर्मा पुत्र श्री छोटे लाल शर्मा निवासी मकान नं. डी-82, लक्ष्मी पार्क, नांगलोई, दिल्ली ने ई-प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.35392 धारा 379/411 भा.द.स., थाना निहाल विहार, नई दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त कमल शर्मा मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त कमल शर्मा फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसके खिलाफ माननीय अदालत द्वारा धारा 82 Cr.P.C. की कार्यवाही जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि ई-प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.35392 धारा 379/411 भा.द.स., थाना निहाल विहार, नई दिल्ली के उक्त अभियुक्त कमल शर्मा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए 21.04.2026 को हाजिर हो।
आदेशानुसार: सुश्री कोमल गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-03 (परिचय) कमरा नं. 292, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
DP/2068/OD/2026

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त दिनेश श. पुत्र: गुमान, पता: 244/90, गली नं.-05, स्कूल ब्लॉक, मंडावली, दिल्ली ने मुकदमा FIR No. 92/2023 U/s 27 NDPS ACT, थाना: मधु विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त दिनेश मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त दिनेश फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि मुकदमा FIR No. 92/2023 U/s 27 NDPS ACT, थाना: मधु विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त दिनेश से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 19.03.2026 को या इससे पहले हाजिर हो।
आदेशानुसार श्री उदभव कुमार जैन न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी-04 कमरा नं. 13, कड़कड़कूवा कोर्ट, दिल्ली
DP/17228/ED/2025 (Court Matter)

| क्र. सं. | बॉर्ड/मि.सं. प्राधि. का नाम | कार्य सूचना तिथि का नाम | सुनने की तिथि वरद होने की तिथि (समय) | गौर/ईएमपी (रकम) | बॉर्ड/रि.म. प्राधि. की वेबसाइट | नोटब अधिकारी / समक वि.म. प्राधि. ई-मेल |
|----------|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| 1 | नगर पालिका जुलाना | एम.सी. जुलाना के कार्यालय भवन की मरम्मत + 7 कार्य। | 12.02.2026 19.07.2026 | ₹. 1,85,43,224/- | https://tenders.hry.nic.in | 7206353677 seerajulana@gmail.com |

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें: www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in
संवाद-13/2026/40/43038/1/88/7 दि. 16.02.26

Please Support me by Joining my Private channel

YOU WILL RECIEVE NEWSPAPERS EARLIER THAN ANYONE OUT THERE. 🙏

📖 Indian Newspapers:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| <u>1) Times of India</u> | <u>6) The Hindu</u> |
| <u>2) Hindustan Times</u> | <u>7) Live Mint</u> |
| <u>3) Business line</u> | <u>8) Financial Express</u> |
| <u>4) The Indian Express</u> | <u>9) Business standard</u> |
| <u>5) Economic Times</u> | <u>+All Editorial PDFs</u> |

Uploding
starts from
5AM

📌 Access to all this
In Just 19 Rupees
[lifetime Validity].

Click below to

Join

📖 International
Newspapers
Channel

📖 Magazine Channel
(National & International).

